आज का तापमान

	अधिकतम	न्यूनतम
लखनऊ	21°C	11°C

इनसाइड न्यूज

भारत के लिए 85 प्रतिशत कच्चा माल चीन से आता है, भारत

उत्तर प्रदेश पेज : 03

लखनऊ और देहरादून से प्रकाशित राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

जन एक्सप्रेस

शुक्रवार 30 जनवरी, 2026 / पेज : 12 / मूल्य : ₹ 3.00/- लखनऊ वर्ष : 17, अंक : 109 www.janexpresslive.com/epaper

विमानन मंत्री ने महाराष्ट्र सीएम फडणवीस... 12

देश का 'आर्थिक रिपोर्ट कार्ड' संसद में पेश

आर्थिक सर्वे के 800 पन्नों का निचोड़ : 56.2 करोड़ लोगों के पास रोजगार का दावा, एफवाई 27 में जीडीपी ग्रोथ 7.2% तक रहने का अनुमान

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार संसद में आर्थिक समीक्षा 2025-26 पेश की। बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले पेश किया गया यह दस्तावेज भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा का आधिकारिक रिपोर्ट कार्ड है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन की देखरेख में तैयार किए गए इस सर्वे का लब्बोलुआब यह है कि भारत की विकास गाथा (ग्रोथ स्टोरी) मजबूत बनी हुई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमें सतर्क रहने की जरूरत है।

1950-51 में पेश हुआ था पहला सर्वे

देश का पहला इकोनॉमिक सर्वे 1951 में पेश किया गया है। तब यह केंद्रीय बजट का ही एक हिस्सा था। 1964 के बाद से इसे बजट से अलग कर दिया गया। तब से बजट डे से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश होता है।

जीडीपी की रफ्तार

1 स्थिर और मजबूत सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.8% से 7.2% के बीच रहेगी। हालांकि, यह चालू वित्त वर्ष (2025-26) के अनुमानित 7.4% से थोड़ी कम है, लेकिन वैश्विक मंदी के माहौल में यह आंकड़ा भारत की स्थिरता को दर्शाता है।

महंगाई पर लगाम

2 आम आदमी के लिए राहत की बात यह है कि महंगाई 'नियंत्रित' है। आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान घरेलू मुद्रास्फीति औसतन 1.7% रही है। कोर इन्फ्लेशन में कमी यह संकेत देती है कि सप्लाई-साइड की स्थिति में सुधार हुआ है।

विदेशी मोर्चे पर चिंता

3 सर्वे ने एक महत्वपूर्ण 'विरोधाभास' की ओर इशारा किया है। जहां भारत के घरेलू फंडामेंटल मजबूत हैं, वहीं बाहरी मोर्चे पर जोखिम बरकरार हैं। विशेष रूप से पूंजी प्रवाह और करेंसी पर दबाव चिंता का विषय है। विदेशी पूंजी के सूखे के कारण 2025 में रुपये का प्रदर्शन कमजोर रहा है।

राजकोषीय अनुशासन

4 सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारा है। वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.8% रहा, जो बजट अनुमानों से बेहतर है। वित्त वर्ष 2026 के लिए इसे 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्यों की 'मुफ्त रेवड़ी' पर चेतावनी

5 सर्वे में राज्यों द्वारा बिना शर्त नकद हस्तांतरण और वित्तीय लोकलुभावनवाद पर चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसे खर्च पूंजीगत व्यय को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे अंततः सॉवरेन उधारी की लागत बढ़ सकती है।

विदेशी मुद्रा भंडार का कवच

6 बाहरी झटकों से निपटने के लिए भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त 'बफर' है। 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है।

7 इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स की लंबी छलांग

अर्थव्यवस्था को गति देने में बुनियादी ढांचे का बड़ा हाथ है :

- **पूंजीगत व्यय :** केंद्र का कैपेक्स FY18 के 2.63 लाख करोड़ रुपये से चार गुना बढ़कर FY26 में 11.21 लाख करोड़ रुपये (बजट अनुमान) हो गया है।
- **सड़क और रेलवे :** हाई-स्पीड कॉरिडोर 550 किमी (FY14) से बढ़कर 5,364 किमी (दिसंबर 2025 तक) हो गए हैं। रेलवे ने FY26 में 3,500 किमी नई लाइनें जोड़ी हैं।

8 गरीबी में भारी गिरावट

नीति आयोग के मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का हवाला देते हुए सर्वे बताता है कि गरीबी 2005-06 के 55.3% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है।

इनोवेशन और रोजगार

भारत ने इनोवेशन में लंबी छलांग लगाई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2019 के 66वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38वें स्थान पर आ गई है। रोजगार के मोर्चे पर, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर FY25 में 2.8 करोड़ से अधिक रिक्तियां मोबिलाइज की गईं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 साफ करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक चुनौतियों के बीच अपनी चमक बनाए रखी है। हालांकि, राज्यों की वित्तीय स्थिति और अस्थिर वैश्विक पूंजी प्रवाह वे क्षेत्र हैं जिन पर नीति निर्माताओं को आगामी बजट में विशेष ध्यान देना होगा।

किस सेक्टर के लिए क्या?

- **बिजली कंपनियां :** डिस्कॉम के लिए यह एक ऐतिहासिक बदलाव का साल रहा, जिन्होंने FY25 में पहली बार 2,701 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।
- **पीएलआई स्कीम :** 14 सेक्टरों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत 2.0 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है और 12.6 लाख से अधिक रोजगार पैदा हुए हैं।
- **सेमीकंडक्टर :** इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 1.60 लाख करोड़ रुपये के 10 प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है।

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

केंद्र को नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश, देशभर में नियमों का विरोध

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर की, जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका देशभर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम देशभर में लागू रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के 4 अहम कमेंट्स

- कोर्ट ने पूछा कि जब 'भेदभाव' की परिभाषा पहले से सभी तरह के भेदभाव को कवर करती है, तो 'जाति-आधारित भेदभाव' को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी?
- कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि रेगुलेशंस में रैगिंग को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि यह कैंपस में एक बड़ी समस्या है।
- सीजेआई ने कहा- अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जातिविहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम अब फिर से पीछे जा रहे हैं?
- सीजेआई ने अलग-अलग जातियों के लिए अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा- भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। हम सब साथ रहते थे, आज इंटर-कास्ट मैरिज भी होती हैं। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए।

केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इन रिट याचिकाओं की सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हमें जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए या हम पीछे जा रह हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे। जिन्हें सुरक्षा चाहिए, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि एक विशेष कमेटी भी बनाई जा सकती है। इसी के साथ नए नियमों की भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पर भी जोर दिया।

केंद्र को नोटिस जारी, 19 मार्च को अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं। कोर्ट के कहा कि नए यूजीसी नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

इसका विरोध कौन कर रहा है?

13 जनवरी को अधिसूचित किए नए इन नियमों का पहले सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हुआ। देखते-देखते इसके विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन होने लगे। मामला बढ़ते-बढ़ते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यहां इसे चुनौती दी गई है। इन नियमों का विरोध मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है। जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर 'सवर्ण समाज समन्वय समिति' का गठन किया है, ताकि रेगुलेशन के खिलाफ संगठित विरोध किया जा सके।

पहले इस पूरे मामले को समझें

यूजीसी के नए कानून का नाम है- 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026।' इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव रोकने के लिए कई निर्देश दिए गए थे। नए नियमों के तहत, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश दिया गया। ये टीमें एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि, सवर्ण जाति के स्टूडेंट्स का आरोप है कि यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है और इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। सवर्ण जाति के स्टूडेंट्स का आरोप है कि नए नियमों में सवर्ण छात्र 'स्वाभाविक अपराधी' बना दिए गए हैं।

विरोध करने वालों का क्या तर्क है?

विरोध करने वालों का ये डर है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही ओबीसी को भी इन नियमों में सुरक्षा देने का विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले संगठनों का मानना है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और नियमों से वंचित छात्रों या शिक्षकों को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है।

यूजीसी का नया नियम क्या है

13 जनवरी को यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु 'यूजीसी समता विनियम 2026' को अधिसूचित किया। इस नियम का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। यह नियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विकलांग व्यक्तियों को किसी भी तरह के भेदभाव से सुरक्षा देता है। नए नियम को सभी विश्वविद्यालय को लागू करना होगा। इसको कैसे लागू किया जाएगा इसके लिए भी यूजीसी ने एक पूरा खाका तैयार किया है।

यूजीसी के नए नियमों से देशभर में आक्रोश

दरअसल, यूजीसी रेगुलेशन, 2026 को 23 जनवरी, 2026 को नोटिफाई किया गया था। जिसे लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया। जिसके बाद इसे कई याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ-साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये नियम सामान्य वर्गों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देते हैं।

यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला : 11.92 लाख शिक्षकों को सौगात

राज्य कर्मचारियों की तरह मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह ही कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दो दी गई है। इस फैसले से 11.92 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले को आयुष्मान व्यवस्था के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस फैसले से शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइया सभी लाभांवित होंगे। इस फैसले के क्रियान्वयन में 358.61 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग को भी कैशलेस सुविधा की मंजूरी दे दी गई है। इससे दो लाख 97 हजार 579 कर्मचारी लाभांवित होंगे। वहीं, सरकार 89.25 करोड़ रुपये का व्यय भार पड़ेगा। हालांकि, जो कर्मचारी पहले से ही किसी सरकारी योजना जैसे आयुष्मान से आच्छादित हैं उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। बता दें कि कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते साल के पांच सितंबर को शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के लिए कैशलेश चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। विभाग की ओर से इस योजना को आयुष्मान योजना की तरह लागू करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 32 में से 30 प्रस्ताव पास हो गए। सिर्फ 14वां और 17वां प्रस्ताव ही रोका गया। ▸ संबंधित खबर पेज 03 पर

बैठक में लिए गए फैसले

- बैठक में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई।
- नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल की जाएगी जिससे कि लोग नक्शा जरूर पास करें। विकास शुल्क के संशोधित प्राइस लागू किए जाएंगे।
- बरेली में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना होगी।
- मुरादाबाद में भी नक्षत्रशाला और विज्ञान पार्क की स्थापना होगी।

आपदा प्रभावित परिवारों का होगा पुनर्वास

बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर मंजूरी दी गई। पीड़ितों को सरकारी आवास और भूमि का पट्टा दिया जाएगा। बहराइच में राजस्व ग्राम परतापुर पर सहित अन्य ग्रामों में आपदा प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए भूमि की व्यवस्था करने के निर्देश सीएम में दिए थे। 29 लोग नदी पार कर रहे थे जिनमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आपदा प्रभावित गांव का हवाई संरक्षण किया गया और परतापुर के गांव के लोगों को पुनर्वासित किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया। 136 परिवारों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा और उनके आवास का भी पट्टा होगा और मुख्यमंत्री आवास के तहत आवास दिया जाएगा जितनी खेती की जरूरत होगी वैसे ही उनका खेती के लिए भी पट्टा दिया जाएगा।

नई लैंड परचेज पॉलिसी से योजनाओं के लिए जमीन जुटाना अब आसान, उत्तराखंड सरकार के बड़े फैसले

जन एक्सप्रेस । देहरादून

उत्तराखंड में सरकारी विभाग अब अपनी योजनाओं के लिए आम लोगों से सीधे जमीन खरीद सकेंगे। इससे जहां आम लोगों को मुआवजा अधिक मिलेगा वहीं विभागों को जमीन जुटाना आसान हो जाएगा। कैबिनेट ने भूअधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए नई लैंड पर चेंज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अभी तक विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार की ओर से भू अधिग्रहण किया जाता है। इसमें न केवल लंबा वक्त लगता है बल्कि उचित दाम न मिलने की वजह से कोर्ट केस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से लंबे समय के लिए सरकारी योजनाएं लटक जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए राजस्व विभाग ने योजनाओं के लिए जमीन जुटाने को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने का विकल्प तैयार किया है। जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि अब विभाग आपसी सहमति से सीधे आम लोगों से जमीन खरीदने के लिए समझौता करेंगे और आपसी सहमति से जमीन के रेट तय किए जाएंगे। मौजूदा पॉलिसी में जमीन का सर्किल रेट का चार गुना अधिक मुआवजा देने का प्रावधान है।

भूजल के कमर्शियल प्रयोग के लिए टैक्स

उत्तराखंड में भूजल के व्यावसायिक प्रयोग के लिए अब शुल्क देना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सात अन्य अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि भूजल-प्राकृतिक स्रोतों के पानी के व्यावसायिक प्रयोग के लिए पंजीकरण करना होगा। इसके लिए शुल्क पांच हजार होगा। हर माह प्रयोग होने वाले पानी का भुगतान एक रुपये से लेकर 120 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से करना होगा। प्रोसेस इंडस्ट्री, कूलिंग, वॉशिंग समेत अन्य उद्योगों को भूजल के दोहन पर एक रुपये से लेकर सात रुपये प्रति किलोलीटर की दर से शुल्क देना होगा। भूजल, प्राकृतिक स्रोतों के पानी का कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वॉटर आदि में इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को एक रुपये से लेकर 120 रुपये प्रति किलो लीटर की दर से भुगतान करना होगा। इसके अलावा पानी का अन्य तरीके से व्यावसायिक इस्तेमाल पर प्रति किलोलीटर एक रुपये से लेकर 20 रुपये का भुगतान करना होगा।

प्राग फार्म में सिडकुल की जमीन सबलेट हो सकेगी

कैबिनेट ने यूएस नगर के प्राग फार्म में पट्टाधारकों को सिडकुल की जमीन सबलेट करने की इजाजत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्राग फार्म में कुल 1354.14 एकड़ जमीन औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए सिडकुल को दी गई है। अभी तक व्यवस्था थी कि सिडकुल जिस पट्टेधारक को जमीन देगा उसे ही उद्योग स्थापित करना था।

जीआरडी को मिलेगा विश्वविद्यालय का दर्जा

कैबिनेट ने जीआरडी उत्तराखंड विवि के गठन को मंजूरी दे दी है। राज्य को उच्च शिक्षा का हब बनाने और शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना महानिदेशक ने बताया कि नए विवि का नाम जीआरडी उत्तराखंड विवि होगा। यह विवि नए और रोजगारोन्मुख कोर्स शुरू करने के साथ ही युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

अन्य फैसलों पर भी नजर

चिन्यालीसौड़, गौचर हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय को देने की मंजूरी। उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति, 2026 को मंजूरी। यूएसनगर प्राग फार्म की 1354.14 एकड़ भूमि सिडकुल को देने के लिए कैबिनेट के पुराने फैसले में संशोधन को मंजूरी। राजस्व की सहमति से पट्टे पर आवंटित भूमि को समान प्रयोजन के लिए सब लीज का अधिकार देने की मंजूरी। दून, चमोली, यूएसनगर, पिथौरागढ़ में जनजाति कल्याण विभाग की योजनाओं के संचालन को विभागीय ढांचें के पुनर्गठन को मंजूरी। जीआरडी उत्तराखंड विश्वविद्यालय को मंजूरी।

अयोध्या जेल के जेलर-डिप्टी जेलर समेत 10 निलंबित

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

अयोध्या जेल से दो बंदियों के फरार होने के मामले में वरिष्ठ जेल अधीक्षक जेलर, डिप्टी जेलर समेत दस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अयोध्या रेंज के डीआईजी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर इन सभी पर कार्रवाई की गई।अमेठी के मुसाफिरखाना निवासी गोलू अग्रहरि उर्फ सूरज पर दुष्कर्म के केस में 14 सितंबर 2025 से जेल में बंद था। वहीं सुल्तानपुर के रौदी निवासी शेर अली डकैती के केस में 28 नवंबर 2024 से जेल में था। दोनों पर हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी व छेड़खानी के भी मामले दर्ज हैं। बुधवार रात बैरक की दीवार को तोड़कर दोनों भाग निकले। डीजी जेल पीसी मीणा ने बताया कि मामले की प्रारंभिक जांच अयोध्या रेंज के डीआईजी शैलेंद्र कुमार मैत्रेय को सौंपी गई थी। प्रारंभिक जांच में जेल के वरिष्ठ अधीक्षक तीन अफसर समेत दस कर्मी दोषी पाए गए। उसी जेल के वरिष्ठ अधीक्षक उदय प्रताप मिश्र, जेलर जितेंद्र कुमार यादव, डिप्टी जेलर मयंक त्रिपाठी, हेड जेल वार्डर हरिहर प्रसाद व त्रिपुरारी मिश्र और जेल वार्डर सुरेश कुमार दुबे, जयप्रकाश यादव, सुनील कुमार, रमेश सहानी, रवि यादव व मनोज को निलंबित कर दिया गया है।

परंपरा और राष्ट्रगौरव : राष्ट्रपति की मौजूदगी में बीटिंग रिट्रीट ने बांधा समां

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ 77वें गणतंत्र दिवस समारोहों का औपचारिक समापन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देश की सैन्य परंपराओं, अनुशासन व शौर्य का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित रहे। 'कदम कदम बढ़ाये जा', 'विजय भारत' और अन्य गीतों ने गुरुवार को रायसीना हिल पर बीटिंग रिट्रीट समारोह में माहौल को देशभक्ति की भावना से भर दिया।

क्या है बीटिंग रिट्रीट का महत्व?

बीटिंग रिट्रीट समारोह हर वर्ष विजय चौक पर आयोजित होता है और यह गणतंत्र दिवस समारोहों के समापन का प्रतीक है। सैन्य परंपरा से निकले इस आयोजन में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बैंड देशभक्ति और शास्त्रीय धुनों की प्रस्तुति देते हैं। यह आयोजन भारतीय सशस्त्र बलों की परंपरा, अनुशासन और वीरता को रेखांकित करता है। संगीत और संरचना के माध्यम से सैन्य बलों के बलिदान और पराक्रम को श्रद्धांजलि दी गई।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी

समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी ने आयोजन को गरिमा प्रदान की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समारोह में शामिल हुए। तीनों शीर्ष संवैधानिक पदों पर आसीन नेताओं की उपस्थिति ने इस आयोजन के राष्ट्रीय महत्व को और मजबूत किया।

दबंग गैंग ने किया असहाय गरीब दिव्यांग के मकान पर कब्जा! डीएम से लगाई गुहार

जन एक्सप्रेस । बांदा

जनपद के कमासिन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुमेढ़ा सानी बगलन पुरवा में एक गरीब दिव्यांग व्यक्ति के निजी मकान पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है।पीड़ित गया प्रसाद कुशवाहा पुत्र स्व. रामप्यारे ने जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है।पीड़ित के अनुसार, मोहन लाल पुत्र भूसी निवासी ग्राम कुचारम थाना पहाड़ी, जनपद चित्रकूट तथा राजकुमार पुत्र चुनबाद कुशवाहा,रमेश एवं प्रकाश पुत्रगण चन्द्रपाल निवासी ग्राम कुमेढ़ा सानी ने उसके रहायशी मकान पर जबरन कब्जा कर लिया।आरोप है कि उक्त

लोगों ने घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया।घटना के समय गया प्रसाद खेत पर काम कर रहा था, वापस लौटने पर उसने अपने घर पर कब्जा पाया।पीड़ित ने बताया कि इस संबंध में उसने दिनांक 14 जनवरी को थाना कमासिन में लिखित शिकायत दी थी,लेकिन अब तक उसका मकान खाली नहीं कराया गया।कब्जे के कारण उसका पूरा परिवार बेघर हो गया है और खेत में रहने को मजबूर है।पीड़ित के साथ उसका 10 वर्षीय पुत्र जितेन्द्र और 5 वर्षीय पुत्री कु. चन्दा भी खुले में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए गया प्रसाद ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर मकान खाली कराने की मांग की है। मामले ने प्रशासनिक संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

जिलाधिकारी ने किया गोल तालाब और पुरानी बावली का स्थलीय निरीक्षण

जन एक्सप्रेस । चित्रकूट

जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने गुरुवार को नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या छह तुलसी नगर कुंजन पुरवा अंतर्गत गोल तालाब व भैरोपागा गंगा जी रोड में संतोषी माता मंदिर के पास स्थित पुरानी बावली का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने दोनों जगहों के संरक्षण व सौंदर्यीकरण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान डीएम ने देखा की वार्ड में निवासरत नागरिकों के घरों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे तालाब में प्रवाहित हो रहा है तथा तालाब में अत्यधिक मात्रा में जलकुंभी फैली हुई है जिसके कारण तालाब का पानी अत्यंत गंदा है। इस पर डीएम ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी को निर्देशित किया कि तालाब में गिरने वाले सभी नाले-नोलियों के पानी को रोकने के लिए तत्काल कार्य योजना तैयार कर कार्य शुरु कराया जाए। इस दौरान मोहल्लेवासियों द्वारा वार्ड में नियमित साफ-सफाई न होने की शिकायत की गई। इस पर भी डीएम ने अधिशासी अधिकारी को मोहल्ले में नियमित साफ-सफाई एवं डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ने भैरो पागा गंगा जी रोड में संतोषी माता मंदिर के पास स्थित पुरानी बावली का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने बावली के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी लालजी यादव सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

दिन दहाड़े हो रहा अवैध खनन! एसपी से शिकायत, अवैध खनन से हो सकती है जनहानि

जन एक्सप्रेस । बांदा

जनपद में इस समय जमकर जिम्मेदारों के संरक्षण में अवैध खनन रात दिन हो रहा है।अगर अवैध खनन की कोई शिकायत करता है।तो अपने जान से भी हाथ धोना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला संज्ञान में आया है जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है दिन के उजाले में अवैध खनन किया जा रहा है महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश भी की गई महिला बाल बाल बच गई साथ ही पीड़ित परिवार ने बताया कि दरवाजे में पथराव भी किया गया दिन गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे पीड़ित सुरेंद्र सिंह निवासी राजघाट खुटला कोतवाली नगर ने शिकायती पत्र देकर बताया की राजघाट खुटला में। पुश्तैनी गाटा संख्या 5040 व 5106 में कागजात में दर्ज है जो दबंग स्थानीय अंशु विष्णु महाकाल ट्रैक्टर माफिया हैं।जो अवैध बालू खनन रात दिन बराबर करते है।जो 28 जनवरी को सुबह लगभग 7 बजे के करीब पीड़ित के दरवाजे से अवैध खनन कर बालू से भरे ट्रैक्टर निकल रहे थे कि अचानक बालू से भरा ट्रैक्टर तेज गति से निकला जिससे पीड़ित सुरेन्द्र व पत्नी जो सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे थे बाल बाल बच गए वरना ट्रैक्टर उनके ऊपर चढ़ जाता पीड़ित ने डायल 112 की पुलिस को भी बुलाया पुलिस कर्मियों के सामने ही अंशु विष्णु और महाकाल ने ट्रैक्टर निकालकर ले गए।जिसका सीसीटीवी वीडियो भी है अवैध खनन को लेकर 0615/ 25 मुकदमा भी दर्ज है व न्यायालय में अभी तक चार्ज शीट दाखिल की नहीं की गई। ना ही खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई जिससे उनके हौसले और बुलंद हैं पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है।

आंगनबाड़ी कर्मचारी एंव सहायिका एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन

जन एक्सप्रेस । चित्रकूट

पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर गुरुवार को आंगनबाडी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन ने जिला मुख्यालय में प्रदर्षन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रदर्शन दौरान एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष ऊषा द्विवेदी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां एवं सहायिकाएं विगत कई दषकों से महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारशिला के रूप मे कार्य करते हुए पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, टीकाकरण, मातृ-शिशु देखभाल सहित केन्द्र एवं राज्य सरकार की अनेकों योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करतीं चली आ रही हैं। इसके बावजूद आज तक न तो आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है और न ही उन्हें वैधानिक, सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं हैं। इस मुद्दे को लेकर पूर्व में भी कई बार सरकार को ज्ञापन दिया जा चुका है, किन्तु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्रदान करते हुए वेतन मांग, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, मंहगाई भत्ता एवं सवेतन मेडिकल अवकाश सहित समस्त वैधानिक लाभ दिए जाएं। साथ ही अन्य राज्यों की भांति अपने प्रदेश में भी रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष की जाए और कोरोना काल से अब तक सेवानिवृत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेंशन एवं ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। इसके अलावा आंगनबाडी से मुख्य सेविका पद पर एवं सहायिका से कार्यकर्ताओं पद पर योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर नियमित और समयबद्ध पदोन्नति शासनादेश के अनुसार दी जाए तथा पदोन्नति में आयु सीमा की बाध्यता समाप्त की जाए। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी अजय यादव को सौंपा गया।

नशे की हालत में ड्राईविंग न करें,ओवर इस्पीडिंग से बचें, जिंदगी बहुत कीमती है, उसकी सुरक्षा करें

जन एक्सप्रेस । हमीरपुर

नशे की हालत में ड्राईविंग न करें,ओवर इस्पीडिंग से बचें, जिंदगी बहुत कीमती है, उसकी सुरक्षा करें। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एआरटीओ अमिताभ राय, पीटीओ चन्दन पाण्डेय सहित ट्राफिक प्रभारी टीएस आई हरवेन्द्र सिंह के ज्वाईन्ट नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के छात्र-छात्राओं के साथ जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का मकसद छात्र-छात्राओं सहित आमलोगों को ट्राफिक रुल के पालन, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ ही सड़क हादसों की रोकथाम के लिये एलर्ट करना था। रैली के दौरान छात्र-छात्राओं को ट्राफिक रुल का पालन करें, हेलमेट सहित सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, नशे की हालत में वाहन न चलायें, ओवरस्पीडिंग से बचें, साथ ही सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संदेशों से जुड़े स्लोगन पेश किये गये। इस मौके पर जिम्मेदारों ने छात्र-छात्राओं को ट्राफिक रुल के बारे में खास जानकारी देते हुए सेफ्टी के साथ वाहन चलाने के लिये जागरूक किया गया। साथ ही सभी से ट्राफिक नियमों को फालो करने की अपील की।

चैपाल लगाकर महिलाओं और चैकीदारों को किया गया जागरूक

जन एक्सप्रेस/चित्रकूट। महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरु किए गए महिला सशक्तिकरण अभियान के पांचवे चरण के तहत गुरुवार को समाजसेवी संस्था इण्टरनेशनल पायनियर्स क्लब द्वारा थाना भरतकूप में चैपाल लगाकर महिलाओं व चैकीदारों को जागरूक किया गया। इस दौरान शीतकालीन सत्र के अंतिम चरण के तहत महिलाओं व चैकीदारों को कम्बल भी वितरित किए गए। चैपाल में क्षेत्राधिकारी नगर अरविन्द कुमार वर्मा ने महिलाओं को उनके हक और अधिकारों के प्रति जागरूक करते बच्चों की शिक्षा व साफ-सफाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। कहा कि समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 112, 1090 पर कॉल करें, पुलिस हमेशा आपके साथ है। चैकीदारों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि चैकीदार पुलिस और जनता के बीच की कड़ी होते हैं। संस्था के अध्यक्ष केशव शिवहरे ने कहा कि शीतकालीन सत्र के अंतिम चरण के तहत जरूरतमंद महिलाओं एवं ग्रामीण चैकीदारों को कम्बल वितरित किए गए है। उन्होंने महिलाओं व चैकीदारों का हौंसला बढ़ाते हुए जागरूक किया। क्षेत्राधिकारी यातायात यामीन अहमद ने कहा कि ठंड में सुदूरवर्ती गांवों में कम्बल वितरण का कार्य सराहनीय है। सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूक करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें एवं दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। थाना प्रभारी उपेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से जनता एवं पुलिस के बीच सौहार्द बढ़ता है। इस दौरान एक सैकड़ा महिलाओं व चैकीदारों को कंबल भी वितरित किए गए। इस मौके पर प्रभारी अपराध शाखा अभय राज सिंह, उपनिरीक्षक अतेंद्र सिंह, बलवंत यादव, आरक्षी प्रवीण पांडेय, शक्ति सिंह, शिवलाल, संस्था पदाधिकारी विवेक अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, शिवम गुप्ता आदि मौजूद रहे।

प्रदीप पाण्डेय बने अध्यक्ष, राजेन्द्र सिंह बने जिला महामंत्री, मीडिया प्रभारी बने अनुराग द्विवेदी

जन एक्सप्रेस । चित्रकट

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की जनपदीय शाखा का द्विवार्षिक अधिवेशन गुरुवार को आयोजित किया गया। जिसमें प्रदीप कुमार पांडेय को परिषद का नया जिलाध्यक्ष चुना गया।

जिला मुख्यालय स्थित कृषि भवन सभागार में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के संरक्षक वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में गुरुवार को द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। जिसमें चुनाव अधिकारी के रूप में आए परिषद के मण्डल अध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्र की मौजूदगी में चुनाव कराया गया। उन्होंने बताया कि सर्वसम्मति से हुए चुनाव में प्रदीप कुमार पांडेय को जिलाध्यक्ष, अशोक कुमार यादव को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजेन्द्र सिंह को जिला महामंत्री, बृजेश कुमार यादव को कोषाध्यक्ष और महेन्द्र सिंह यादव को संप्रेक्षक चुना गया है। छात्र जीवन के दौरान गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के तेज-तर्रार छात्र नेता रहे अनुराग द्विवेदी को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। इस दौरान सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संघ के सम्विधान की शपथ भी दिलायी गई।

निर्वाचित पदाधिकारियों को सदन द्वारा कार्यकारिणी के विस्तार का अधिकार देते हुए 15 दिन के अंदर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संपूर्ण कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कराने को कहा गया है। जिसमें मीडिया प्रभारी अनुराग द्विवेदी को सभी लोगों को सूचित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर जगबली सिंह, कृष्णपाल सिंह, जयगोपाल कुशवाहा, अमरजीत, चित्रांश श्रीवास्तव, अरुण कुमार, रामबाबू, देवकुमार यादव, गुलाब सिंह, फूलचन्द्र यादव, नितिन, धर्मेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।

मंदिर में चोरों का धावा: छत्र, मुकुट व नाक की बेसर लेकर हुऐ फरार साथ कैमरे की हार्डडिस्क भी ले गये चोर

जन एक्सप्रेस । बांदा

पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत खप्टिहाकला स्थित सिद्ध पीठ पाथादाई मंदिर में बीती रात मां दुर्गा जी की मूर्ति में लगे चांदी के छत्र मुकुट 500 ग्राम व नाक की सोने की बेसर वह कैमरे की हार्ड डिस्क ले गए हैं जो मंदिर के गेट पर ताला लगा था। जब सुबह भक्त रामू पूजा करने के लिए मंदिर गया तो वहां देखा कि अल्युमिनियम का पल्ला तोड़कर व सी सी कैमरा की केबिल तोड़कर एवं हार्ड डिस्क निकाल कर व चांदी का मुकुट व नाक की बेसर जब नहीं दिखाई दी तो पडो़स के लोगों को जानकारी दी वहीं मौके पर पहुंचे मुख्य पुजारी राकेश बाबा,प्रधान पति रामचंद्र निषाद,सुरेश,अमित सिंह, राहुल यादव,शिवकुमार,अंकित सिंह,सुधाकर शुक्ला,भोला सिंह,विनय,रामदत्त तिवारी आदि ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और चौकी प्रभारी हरीशरण सिंह को अज्ञात चोरों द्वारा चांदी का मुकुट,सोने की बेसर व हार्ड डिस्क चोरी किए जाने को लेकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया वहीं मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी हरीशरण सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मुकदमा दर्ज कराए जाने को लेकर आश्वासन दिया और कहा कि जल्द ही अज्ञात चोरों का पता लगाकर कार्यवाही की जाएगी।

नगर पालिका की लापरवाही से नाले में गिरने से हो रही गौवशों की मौत

जन एक्सप्रेस । बांदा

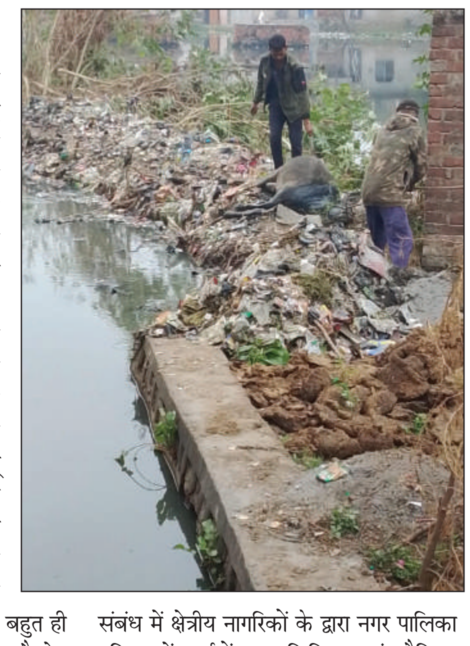

शहर के अलीगंज में स्थित सेढ़ू तलैया नाले में टेंडर प्रक्रिया होने के बावजूद नगर पालिका परिषद नाला नहीं बनवा पा रहा है। सेढ़ू तलैया अलीगंज स्थित नाला वर्तमान समय में अत्यंत जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में है नगर पालिका परिषद के द्वारा 6 महीने पहले टेंडर कराकर ठेकादार को ठेका देने के बावजूद भी संबंधित ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया जिसके कारण पिछले 6 महीने में नाले में गिरने से तीन गायों की मौतें हो चुकी है ज्ञात हो कि वर्तमान में शहर के सेढ़ू तलैया नाला लोहिया पुल से लेकर विराट पैलेस अतर्रा चुंगी तक जाता है जो 20- 25 वर्ष पहले निर्मित हुआ था तथा बीच बीच में कई जगह नाला निर्माण नहीं किया गया नाले की दीवारें बहुत ही नीची है तथा नाला कई जगह से टूटा है।सेढ़ू तलैया छोटी काली देवी मंदिर की मुख्य सड़क पर जल संस्थान के द्वारा नाले के बीचो-बीच से पानी की पाइपलाइन डालने से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है कई बार शिकायत करने के बावजूद पानी की पाइपलाइन को विभाग द्वारा नहीं हटाया जा रहा। बारिश के बाद नाले की सफाई भी नहीं कराई गई है।ठेकेदार के द्वारा नाले की निकासी भी पूरी तरह बंद कर दी गई है जिसके कारण नाले में पानी भरा हुआ है और जानवर लगातार मौत के शिकार हो रहे हैं।इस संबंध में क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा नगर पालिका परिषद में दर्जनों बार लिखित एवं मौखिक शिकायत की गई परंतु संबंधित विभाग नाले एवं पुलिया का निर्माण नहीं कराया जा रहा। न ही नाले का जीर्णोद्धार किया जा रहा।जिसके कारण बारिश में सैकड़ो लोगों के मकानों में पानी घुस जाता है। जिससे नागरिकों को लाखों रुपए की जनधन की हानि होती है कुछ लोगों ने नाले पर अतिक्रमण भी कर रखा है निर्माण विभाग की उदासीनता एवं नगर पालिका परिषद की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

आयुक्त ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर लिया जायजा

जन एक्सप्रेस/हमीरपुर। आयुक्त बांदा अजीत सिंह ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की समीक्षा करने के साथ ही सभी राजनैतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक में कड़ेदीन शर्मा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि जिले में 52 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की तैनाती की गयी है जो सभी काम के दिनों में बैठक नोटिस की सुनवाई का कार्य कर रहे हैं। जिले में वर्तमान में 1015 मतदेय स्थलों के सापेक्ष 1015 बीएलओ, जबकि 102 बीएलओ सुपरवाइजर की तैनाती की गयी है साथ ही सभी बीएलओ सहित सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दी गई है। आयुक्त ने निर्देशित किया कि सभी बीएलओ को सही तरीके से प्रशिक्षण दिया किया जाये। साथ ही कहा कि सभी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में जरूर दर्ज हो। यदि किसी वोटर ने कोई डिटेल नहीं दी है, या फार्म अधूरा भर दिया गया है।

नि:शुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन, सैकड़ों मरीजों ने लिया लाभ

जन एक्सप्रेस । चित्रकूट

जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत गुरुवार को राजापुर तहसील परिसर में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से आए 242 मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर निःशुल्क दवाइयों का लाभ उठाया।

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ दिलीप सिंह ने बताया कि शिविर में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ राजेश पांडेय व डॉ शशि केशरवानी द्वारा सर्दी-खांसी, बुखार, जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग, एलर्जी, पेट संबंधी रोग, महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याएं एवं बच्चों की सामान्य बीमारियों का उपचार किया गया तथा निःशुल्क दवाएं दी गई। साथ ही रोगियों को जीवनशैली में सुधार, संतुलित आहार तथा नियमित दिनचर्या अपनाने की सलाह भी दी गई। बताया कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सुरक्षित, प्रभावी एवं बिना किसी दुष्प्रभाव के रोगों के उपचार में सहायक है। शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना तथा होम्योपैथिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। शिविर में फार्मासिस्ट लालचंद, अनुज, शिवशंकर आदि का योगदान रहा।

कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में नवीन महिला छात्रावास के लिए सम्पन्न हुआ भूमि पूजन

जन एक्सप्रेस । बांदा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है।इसी क्रम में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में नए 100 बेड क्षमता के महिला छात्रावास का भूमि पूजन कुलपति प्रो. एस. वी. एस. राजू द्वारा किया गया।नया छात्रावास,छात्राओं को आधुनिक आवासीय सुविधाएं प्रदान करेगा जिससे छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। इस अवसर पर प्रो राजू ने कहा कि कृषि शिक्षा में लगातार महिला छात्राओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है।जिसके कारण काफी समय से विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए छात्रावास की आवश्यकता थी।इसी वर्ष विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अनुदान से एक महिला छात्रावास बनकर तैयार है।इस नवीन छात्रावास के साथ विश्वविद्यालय में कुल तीन महिला छात्रावास हो जाएंगे। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ0 एस0 के0 सिंह, निदेशक- प्रशासन एवं अनुश्रवण, डॉ0 नरेन्द्र सिंह,अधिष्ठाता छात्र कल्याण,डॉ0 अजीत सिंह,अधिष्ठाता कृषि/उद्यान/वानिकी महाविद्यालय,डॉ0 जी0एस0 पवार,डॉ0 एस0वी0 द्विवेदी,डॉ0 संजीव कुमार,सहायक सम्पत्ति अधिकारी,डॉ0 सुनील कुमार,सह अधिष्ठाता,पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय,डॉ0 शैलेन्द्र चौरसिया व विश्वविद्यालय तथा कार्यदायी संस्था के अधिकारीगण उपस्थित थे।

लखनऊ एक्सप्रेस

हिंदी दैनिक, जन एक्सप्रेस | @janexpressnews | janexpresslive | www.janexpresslive.com/epaper | janexpresslive | लखनऊ, शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026

'अजित दादा' पंचतत्व में विलीन...

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को गुरुवार को उनके गृहनगर बारामती में अंतिम विदाई दी गई। एक दुखद विमान हादसे में उनके निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान बारामती... ▸ पढ़ें पेज 12 पर...

शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा जगत से जुड़े लाखों कर्मियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। अब प्रदेश के माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मी और उनके आश्रित परिवार सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। इससे 15 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी लाभान्वित होंगे। इस पर समग्र रूप से लगभग 448 करोड़ रुपये का व्यय होगा। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेसवार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में कुल 32 प्रस्ताव आए, जिनमें 30 को कैबिनेट की मंजूरी मिली।

शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा लाभ

कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। इलाज की दरें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय मानकों के अनुसार होंगी। स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को वेरिफिकेशन के बाद योजना का लाभ मिलेगा। वेरिफिकेशन के लिए जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले से जो लोग केंद्र या राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

कैबिनेट ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर जताया शोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट ने 28 जनवरी को महाराष्ट्र के बारामती में हुई विमान दुर्घटना में अजित पवार व अन्य लोगों के निधन को दुखद बताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत पुण्यात्माओं की शांति की कामना की। सदस्यों ने कहा कि अजित पवार ने अपने महाराष्ट्र की जनता से गहरा जुड़ाव रखते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया। गरीबों एवं वंचितों को सशक्त बनाने तथा महाराष्ट्र के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता सदैव स्मरणीय रहेगी।

विधानमंडल का बजट सत्र 11 को पेश होगा बजट

विधानमंडल का बजट सत्र आगामी 9 फरवरी से शुरू होगा। वहीं 11 फरवरी को प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल का बजट सत्र शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सत्र के पहले दिन 9 फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। तत्पश्चात 10 फरवरी को सदन में दिवंगत सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। वहीं 11 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट में सरकार का फोकस विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक मजबूती पर रहेगा। विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही की अवधि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय की जाएगी।

उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति तेज करने को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। भरोसेमंद, सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति, निवेश और रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाती है। इसी सोच के अंतर्गत प्रदेश में बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार लागू किए गए हैं। प्रदेश सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है। औद्योगिक विकास के लिए 24 घंटे अबाधित बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करना प्रमुख लक्ष्य है। बीते वर्षों में नए पावर प्लांट की स्थापना, ट्रांसमिशन नेटवर्क के विस्तार और सब स्टेशनों के निर्माण से बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है। औद्योगिक क्षेत्रों और एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर के आसपास बिजली अवसंरचना को विशेष रूप से मजबूत किया गया है। ताकि उद्योगों को निर्बाध आपूर्ति मिल सके और उत्पादन प्रभावित न हो। प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए वर्ष 2017 से नवंबर, 2025 के मध्य तक 15,87,369 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित किये जा चुके हैं। 33/11 केवी क्षमता वाले 765 नए सब स्टेशन बनाये गए। 2,455 पुराने विद्युत् उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ाई गई है। कम लागत की बिजली को प्रदेश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने का अहम साधन माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि सस्ती बिजली मिलने से उद्योगों की उत्पादन लागत घटेगी, जिससे वे घरेलू और वैश्विक बाजार में बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीतियों में ऊर्जा लागत को नियंत्रण में रखने पर जोर दिया गया है। निवेशकों को स्थिर दरों पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने का भरोसा दिया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में किए गए सुधारों का असर निवेश माहौल पर भी दिखाई दे रहा है। बेहतर बिजली आपूर्ति के कारण मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर में नए निवेश प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों का मानना है कि स्थिर बिजली आपूर्ति से उत्पादन की निरंतरता बनी रहती है, जिससे परियोजनाओं की समयसीमा और लागत दोनों नियंत्रित रहती हैं। योगी सरकार के द्वारा औद्योगिक इकाइयों के विस्तार को लेकर उठाये जा रहे कदमों से प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सस्ती और निर्बाध बिजली से फैक्ट्रियों का संचालन आसान होगा और नई इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

बांग्लादेश से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों का होगा स्थायी पुनर्वासन

कैबिनेट ने पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित होकर यूपी में रह रहे हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वासन को लेकर मानवीय फैसला लिया है। कैबिनेट ने मेरठ में निवास कर रहे विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बता दें कि मेरठ की तहसील मवाना के ग्राम नंगला गोसाई में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 99 हिंदू बंगाली परिवार झील की भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद इन सभी 99 परिवारों का पुनर्वासन कानपुर देहात जिले की रसूलाबाद तहसील के दो गांवों में किया जाएगा। भैंसाया गांव में पुनर्वास विभाग के नाम दर्ज 11.1375 हेक्टेयर (27.5097 एकड़) भूमि पर 50 परिवारों को तथा ताजपुर तरसौली में पुनर्वास विभाग के नाम अंकित 10.530 हेक्टेयर (26.009 एकड़) भूमि पर शेष 49 परिवारों को बसाया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 0.50 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। यह भूमि प्रीमियम अथवा लीज रेंट पर 30 वर्ष के पट्टे पर दी जाएगी, जिसे आगे 30-30 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। इस प्रकार पट्टे की अधिकतम अवधि 90 वर्ष होगी। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विस्थापित परिवारों के सम्मानजनक और सुरक्षित पुनर्वासन को सुनिश्चित करेगा। लंबे समय बाद इन परिवारों को स्थायी ठिकाना और सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा।

9351 सहायक मोटरयान निरीक्षक पदों पर होगी भर्ती

परिवहन विभाग 351 पदों पर सहायक मोटरयान निरीक्षकों के पदों पर भर्ती करेगा। बृहस्पतिवार को कैबिनेट में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में तीन नए परिवहन परिक्षेत्रों के गठन को भी हरी झंडी मिल गई है। इसमें गोरखपुर, बुंदेलखंड (झांसी) और अयोध्या शामिल हैं। इन तीन परिक्षेत्रों के गठन के बाद प्रदेश में कुल 9 परिक्षेत्र हो जाएंगे। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सड़क सुरक्षा (एआरटीओ) के 36 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों पर भी जल्द भर्ती होंगी।

99% से अधिक इंडेक्सिंग, 98% स्कैनिंग पूरी

प्रदेशभर में इस परियोजना के तहत इंडेक्सिंग का 99.11 प्रतिशत और स्कैनिंग का 98.37 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। अधिकांश जिलों में यह कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। फिलहाल एटा, वाराणसी, मुरादाबाद, मैनपुरी, लखनऊ, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, सहारनपुर व प्रयागराज में कुछ कार्य शेष है, जिसे अगले 6 माह में पूरा कर लिया जाएगा।

दो स्तर पर हो रही जांच व सत्यापन

डिजिटाइजेशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर दस्तावेज का दो स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है। पहले स्तर पर सहायक महानिरीक्षक निबंधन द्वारा जांच की जा रही है, जबकि दूसरे स्तर पर मंडलों और वृत्तों के उप महानिरीक्षक निबंधन द्वारा पुनः परीक्षण किया जा रहा है। यह प्रक्रिया शत-प्रतिशत सत्यापन तक जारी रहेगी। पुराने दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन से कूटरचना व फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और जमीन-जायदाद से जुड़े रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित हो सकेंगे।

ई-वाहनों पर राहत

कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के तहत प्रदेश में खरीदे और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को नीति के चौथे व पांचवें वर्ष में पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में सौ फीसदी की छूट देने संबंधी अधिसूचना को भी मंजूरी दी है।

घर बैठे डीएल करें अपडेट, नहीं लगाने होंगे चक्कर

ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी चार सेवाओं का उपयोग अब आम लोग घर बैठे कर सकेंगे। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि परिवर्तन, पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने की अनुमति, पंजीकरण संख्या प्रतिधारण और गैर-उपयोग सूचना परमिट की सुविधा ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।

देवरिया-कसया मार्ग का होगा चौड़ीकरण

कैबिनेट ने देवरिया में देवरिया-कसया मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा 31.500 किमी मार्ग के चौड़ीकरण करने में 292.06 करोड़ रुपये की लागत आएगी। साथ ही देश-विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को देवरिया शहर एवं भगवान बुद्ध की महा परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर और नेपाल जाने में सुविधा होगी। साथ ही जिले का चहुंमुखी विकास होगा।

सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी

कैबिनेट ने दो सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। वाराणसी-चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर (मुगलसराय) चकिया राज्यमार्ग 11.235 किमी चौड़ा किया जाएगा। इसमें 325.93 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे सीएनसी रेलिंग, विक्टोरियन इलेक्ट्रिक पोल, इंट्रेंस गेट, फुटओवर ब्रिज और हेरिटेज स्तंभ का कार्य कराया जाएगा।

बहराइच के आपदा प्रभावित 136 परिवारों को मिलेंगे पक्के आवास

बहराइच के राजस्व ग्राम भरथापुर के आपदा प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। बीती 29 अक्तूबर को कौड़ियाल नदी में नाव पलटने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिससे प्रभावित परिवारों को अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास मुहैया कराए जाएंगे। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 नवंबर को गांव का हवाई सर्वेक्षण किया था और पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर बसाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में बृहस्पतिवार को कैबिनेट ने भरथापुर गांव के 136 परिवारों को विस्थापित कर मिहींपुरवा तहसील के ग्राम पंचायत सेमरहना में पुनर्वासित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 1.70 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया डीएम बहराइच पूरी करेंगे। नई बस्ती का नामकरण मुख्यमंत्री की अनुमति से किया जाएगा।

यूजीसी 'इक्विटी रेगुलेशन' से देश में बवाल

- सड़कों से संसद तक टकराव, विश्वविद्यालयों में उबाल

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

उच्च शिक्षा में 'समानता' लागू करने के नाम पर यूजीसी द्वारा लाया गया 'इक्विटी रेगुलेशन-2026' देश को दो हिस्सों में बांटता नजर आ रहा है। सरकार इसे ऐतिहासिक सुधार बता रही है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि छात्र, शिक्षक और सामान्य वर्ग खुलकर विरोध में उतर आए हैं। विश्वविद्यालय परिसरों से लेकर संसद और लखनऊ की सड़कों तक एक ही सवाल गूंज रहा है 'यह समानता है या शिक्षा के ज़रिये नई सामाजिक इंजीनियरिंग?' इन नियमों की सिफारिश करने वाली संसदीय स्थायी समिति की अध्यक्षता कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की थी। समिति में भाजपा, कांग्रेस, वाम दल, आप और एनसीपी सहित 30 सांसद शामिल रहे।

अब सवालः क्या बिना व्यापक सामाजिक संवाद के इतना संवेदनशील बदलाव देश पर थोप दिया गया?

मंत्री के हस्ताक्षर, जनता में अविश्वास

यूजीसी विनियम पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हस्ताक्षर हैं। भाजपा इसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जोड़कर बचाव कर रही है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि मैदान में भरोसा नहीं, आक्रोश है।

'योग्यता पर कुठाराघात' का आरोप

प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठनों का कहना है मेरिट आधारित प्रवेश व्यवस्था कमजोर होगी पहले से लागू आरक्षण के ऊपर नया इक्विटी फ्रेमवर्क सामान्य वर्ग के अवसर और सिमटेंगे सीधा आरोप 'समानता के नाम पर असमानता को संस्थागत किया जा रहा है।'

लखनऊ में सवर्ण समाज सड़क पर

यूजीसी बिल और इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ क्षत्रिय-ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतरा। नारे गूंजे– 'यूजीसी बिल वापस लो' 'शिक्षा का राजनीतिकरण बंद करो' 'बिना संवाद के फैसले' का आरोप प्रदर्शनकारियों का कहना है न शिक्षाविदों से सलाह न छात्रों से संवाद विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खतरे में एक वक्ता का दो टूक बयान 'शिक्षा प्रशासनिक आदेशों से नहीं, स्वतंत्र सोच से चलती है।'

सबसे बड़ा सवाल

सरकार जो कह रही है, वह अलग है। देश जो महसूस कर रहा है, वह अलग। क्या 'इक्विटी रेगुलेशन-2026' सच में समानता लाएगा? या शिक्षा के रास्ते समाज को नए सिरे से बांटने की नींव रखी जा रही है?

बालागंज में अवैध निर्माण पर 'सील' सिर्फ काग़ज़ों में

आईजीआरएस शिकायत के बाद भी ज़मीन पर कार्रवाई शून्य, एलडीए की भूमिका संदिग्ध

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी आईजीआरएस शिकायत के बावजूद बालागंज के हरीनगर चौराहा, जल निगम रोड क्षेत्र में अवैध निर्माण पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की कार्रवाई सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह गई है। मौके पर न सीलिंग हुई, न ध्वस्तीकरण–और अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। आईजीआरएस शिकायत संख्या 40015725130457 के तहत 22 जनवरी 2026 को दर्ज शिकायत में बिना स्वीकृत मानचित्र निर्माण कराए जाने का आरोप लगाया गया था। जांच की जिम्मेदारी प्रवर्तन जोन-7 के अवर अभियंता अंगद सिंह को सौंपी गई। जांच आख्या में खुद एलडीए ने स्वीकार किया कि चन्द्र प्रकाश अवस्थी व अन्य द्वारा थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के जल निगम रोड पर किया जा रहा निर्माण उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-

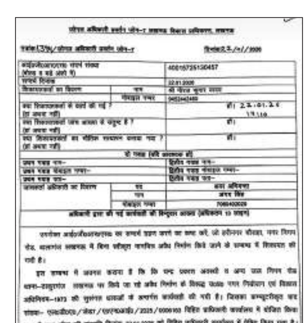

1973 का खुला उल्लंघन है। इसके बावजूद मौके पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। प्रवर्तन विभाग ने मामले में कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या ख8/7/हठ्ठ/2025/0006163 दर्ज कर 22 जनवरी को विहित प्राधिकारी को सीलिंग की संस्तुति भेजने की औपचारिकता पूरी कर दी। लेकिन सवाल जस का तस है–जब अवैध निर्माण की पुष्टि हो चुकी, तो बुलडोज़र क्यों नहीं चला? जांच रिपोर्ट खुद कई सवाल खड़े करती है। शिकायतकर्ता से कथित वार्ता का ज़िक्र तो है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि शिकायतकर्ता जांच से संतुष्ट है या नहीं। भौतिक सत्यापन का रिकॉर्ड भी अधूरा और अस्पष्ट है, जिससे पूरी जांच प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ जाती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बालागंज में अवैध निर्माण प्रशासन की मौन सहमति से फल-फूल रहे हैं। शिकायत, जांच, फाइल और फिर सन्नाटा–इसी ढर्रे पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

सवालों के घेरे में एलडीए अधिकारी

इस पूरे मामले में जब जन एक्सप्रेस के संवाददाता ने एलडीए जोन-7 के अधिशासी अभियंता अंगद सिंह से शाम लगभग 3:40 बजे बातचीत की, तो उन्होंने कहा 'आप व्हाट्सएप पर पत्र भेज दीजिए, दिखवाता हूं।' हैरानी की बात यह है कि शिकायत पत्र पर रिपोर्ट स्वयं उन्हीं की लगी हुई है। इसके बावजूद लगभग एक घंटा बीतने के बाद दोबारा फोन किया गया, तो दो बार घंटी बजने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं की गई।

बड़ा सवाल

- क्या एलडीए की सीलिंग संस्तुति सिर्फ काग़ज़ी खानापूर्ति है, या वास्तव में अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी?
- अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठे, तो यह मामला भी सिस्टम की सुस्ती और मिलीभगत का एक और उदाहरण बनकर रह जाएगा।

सीईआईआर ने चोरों की तोड़ी रीढ़

- आशियाना पुलिस ने लौटाई जनता की मेहनत की कमाई
- 18 मोबाइल ट्रेस, 2.65 लाख की बड़ी रिकवरी

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

मोबाइल चोरी के बाद आम आदमी अक्सर सिस्टम से उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन आशियाना पुलिस ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। सीईआईआर पोर्टल की सटीक तकनीक और साइबर टीम की सक्रियता से थाना आशियाना पुलिस ने 18 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर असली मालिकों को सौंप दिए। करीब ?2.65 लाख कीमत के इन स्मार्टफोन की रिकवरी ऐसे समय में हुई है, जब मोबाइल स्नैचिंग और डिजिटल अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं।

टेक्नोलॉजी के दम पर चोर बेनकाब

पुलिस उपायुक्त मध्य के पर्यवेक्षण में, अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य) और सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक आशियाना के नेतृत्व में साइबर टीम ने सीईआईआर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के आधार पर मोबाइलों की लोकेशन ट्रेस की। अलग-अलग क्षेत्रों में सक्रिय मोबाइलों को समन्वित कार्रवाई के जरिए रिकवर किया गया।

थाने में लौटा भरोसा

मोबाइल पाकर पीड़ितों के चेहरे खिल उठे। कई लोगों ने कहा कि उन्हें फोन मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आशियाना पुलिस की इस कार्रवाई ने पुलिस-जन विश्वास को मजबूती दी है।

इस टीम ने रचा भरोसे का रिकॉर्ड

- छत्रपाल सिंह (प्रभारी निरीक्षक)
- उप निरीक्षक सुनील कुमार यादव
- उप निरीक्षक अभिषेक कुमार,
- पूनम केसरवानी (कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी)
- कांस्टेबल अमन कुमार,
- हेड कांस्टेबल तौफीक खान
- मोबाइल पाकर मुस्कुराते पीड़ित सीईआईआर पोर्टल के जरिए आशियाना पुलिस ने चोरों पर कसी नकेल।

गोरखपुर में 721.40 करोड़ की सीवरेज परियोजना को मंजूरी

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 यानि अमृत-2.0 अंतर्गत गोरखपुर में सीवरेज परियोजना को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने गोरखपुर मेंसीवरेज योजना जोन-ए-3 से संबंधित 721.40 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी। परियोजना नगर निगम क्षेत्र में सीवेज प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। परियोजना से 17 वार्डों की 1.95 लाख से अधिकआबादी को सीवेज सुविधा का लाभ मिलेगा। फैसले को शहरी आधारभूत संरचना को व्यवस्थित व टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस स्वीकृत लागत में जीएसटी व सेंटेज की रकम भी शामिल है।नगर निगम गोरखपुर की परियोजना की अनुमोदित लागत 721.40 करोड़ रुपये है, जिसमें 27.28 करोड़ रुपये सेंटेज शामिल है। परियोजना की लागत में भारत सरकार का अंश 231.35 करोड़ रुपये, राज्य सरकार का अंश 435 करोड़ रुपये तथा निकाय का अंश 27.76 करोड़ रुपये निर्धारित है। सेंटेज की धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। केंद्र और राज्य की साझेदारी से इस नगरीय विकास योजना को गति मिलेगी, जो अनुकरणीय उदाहरण है।

भाजपा जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने बूथ पर विशेष अभियान चलाकर मतदाता फॉर्म भरवाए

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

लखनऊ महानगर में आज जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारीयों और कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर विशेष अभियान चलाकर फॉर्म 6 भरवाए। वही प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह द्वारा मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत 29 और 30 जनवरी को विशेष अभियान चलाकर सभी को अपने-अपने बूथ पर न्यूनतम 10 फॉर्म भरवाकर बीएलओ के पास जमा कराने का लक्ष्य दिया गया। वही अभियान के तहत प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने मध्य विधानसभा की बूथ संख्या 278 पर, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कैंट विधानसभा के गुरु नानक वार्ड की बूथ संख्या 129 पर, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा ने पश्चिम मंडल 1 की बूथ संख्या 37 पर, विधायक डॉ नीरज बोरा ने उत्तर मंडल में बूथ संख्या 369 पर, विधायक ओपी श्रीवास्तव ने पूर्व मंडल 3 की बूथ संख्या 182 और 83 पर अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मतदाता फॉर्म भरवाए।

यूजीसी के विरोध में बीकेटी तहसील में वकीलों ने प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

जन एक्सप्रेस । लखनऊ

- इटौंजा की माल रोड पर एक निजी लॉन में श्रवण समाज के लोगों ने की बैठक

लखनऊ जिले के बीकेटी तहसील में अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह, हिमांशु द्विवेदी, जितेन्द्र कुमार सिंह महामंत्री समेत सैकड़ो की तादाद में वकीलों ने यूजीसी कानून का विरोध करते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे बीकेटी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने कहा कि इससे आशंका व्यक्त होती है कि यह नियम अनजाने में शिक्षा परिसर में अविश्वास मानसिक दबाव एवं एक तरफा शिकायत का कारण बन सकता है जिसे वापस लेना न्यायहित में अति आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में समाज में असामनता होगी और आपस में भेदभाव एवं विवाद बढ़ेगा और संविधान की मूल भावना समानता का अधिकार को ठेस पहुंचेगी। जिससे अराजकता का माहौल बना रहेगा, जिसे तत्काल वापस लिया जाए अन्यथा की स्थिति में बी0के0टी0 बार एसोसिएशन लखनऊ के अधिवक्तागण इस काला कानून यूजीसी के विरोध में आन्दोलन करने के लिए बाध्य होगें।वही इटौंजा अशोक रोड पर एक निजी लॉन में यूजीसी के विरोध में इटौंजा के क्षेत्रीय गांव के श्रवण समाज के क्षेत्रीय सभी लोगों ने बैठक की?। जिसमें सभी लोगों ने यूजीसी का कड़ा विरोध किया और यूजीसी को खत्म करने की मांग की है। इस दौरान अजय मिश्रा महोना, राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा व्यापार मंडल अध्यक्ष इटौंजा,बबलू मिश्रा, भुवनेश्वर द्विवेदी उर्फ बच्चा महाराज अकड़रिया कलां, राम प्रकाश सिंह चंदनापुर,योगेश शुक्ला नगर चौगवां, नागेंद्र सिंह एडवोकेट सोनीकपुर, पिंटू मिश्रा, सुदीप श्रीवास्तव इटौंजा, मनोज सिंह व बबलू सिंह रायपुर राजा, सुशील कुमार मिश्रा इटौंजा,कमल सिंह राठौर कमालपुर, संतोष सिंह मानपुर, अनुज जयपालपुर, अमित मिश्रा बाहर गांव, अभिषेक शर्मा नगर चौगवां, बृजेश सिंह जयपालपुर, अमित तिवारी सोनवां, दीपक शुक्ला तिरंगा मरपा, योगेश सिंह उसरना अन्य लोग मौजूद रहें।

विधायक की वास्तविक योग्यता जनता का विश्वासः महाना

जन एक्सप्रेस। लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका और जनसेवा के महत्व पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 'लोकतंत्र में वही विधायक सफल होता है जो स्वयं को जनता का व्यक्ति समझे, केवल विधायक बनकर नहीं। जनता से ऐसा जीवंत और आत्मीय जुड़ाव होना चाहिए कि लोग आपसे मिलने को उत्सुक हों न कि किसी मजबूरी में। यदि कभी जनता में असंतोष दिखाई दे तो जनप्रतिनिधि को धैर्य, संयम और संवेदनशीलता के साथ उनकी बात सुननी चाहिए।' सतीश महाना से हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने शिष्टाचार भेंट की। यह समिति किशोरी लाल के सभापतित्व में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सात सदस्यीय दल के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के भ्रमण पर आई थी।

जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक डीएम की अध्यक्षता में आयोजित

जन एक्सप्रेस । बलरामपुर

गुरुवार को जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जनपद में बच्चों के संरक्षण, कल्याण एवं उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करना रहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम, बाल श्रम उन्मूलन, बाल विवाह रोकथाम, स्पॉन्सरशिप योजना, बाल देखभाल संस्थाओं की स्थिति, चाइल्ड हेल्पलाइन एवं संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्यवाही की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चिन्हित मामलों में समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र बच्चों तक अनिवार्य रूप से पहुंचे। बैठक में बाल संरक्षण से जुड़े प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग, जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन एवं फील्ड-लेवल पर सक्रिय निगरानी पर विशेष बल दिया गया। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, समिति के सदस्य एवं अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गुप्ता , अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, प्रबन्धक जिला अग्रणी बैंक, सहायक श्रमायुक्त, बलरामपुर, अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति, सहायक मुख्य विधिक सहायता एवं प्रतिरक्षा, परामर्शदाता (प्रतिनिधि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण), विधि सह परिवीक्षा अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रभारी विशेष किशोर पुलिस इकाई, मैनेजर/को-ऑर्डिनेटर चाइल्ड हेल्पलाइन, मैनेजर/को-ऑर्डिनेटर राजकीय दत्तक ग्रहण इकाई, केस वर्कर वन स्टॉप सेन्टर, श्री अर्पित श्रीवास्तव (रोज़ा संस्था) सहित जिला बाल संरक्षण इकाई एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

02 को दिव्यांग न्यायालय का आयोजन सामुदायिक केंद्र रतापुर में

जन एक्सप्रेस । रायबरेली

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रायबरेली सृष्टि अवस्थी ने बताया है कि समस्त दिव्यांगजनों को सूचित किया जाता है, कि 02 फरवरी 2026 को प्रातः 10ः00 बजे से सामुदायिक केन्द्र रतापुर, रायबरेली में मा0 न्यायालय/राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ मोबाइल कोर्ट (दिव्यांग न्यायालय) का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में जनपद के समस्त विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजन उपस्थित होकर अपनी शिकायतों/समस्याओं का निराकरण उक्त तिथि को ही कराया जा सकता है।

रायबरेली में चोरी की घटनाओं पर पुलिस का एक्शन, चोरी की 10 बैटरियों सहित 3 चोर गिरफ्तार

जन एक्सप्रेस । रायबरेली

रायबरेली जिले में चोरी की घटनाओं पर लगाम कसते हुए कोतवाली नगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने चोरी की गई 10 बैटरियों के साथ तीन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई संदिग्ध व्यक्ति और वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर की गई।

पुलिस के अनुसार, कोतवाली नगर क्षेत्र में स्थित एक टायर की दुकान से बैटरियों की चोरी की शिकायत मिली थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में बछरावां रोड स्थित बावन बीघा मैदान के पास से तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सभी 10 बैटरियां बरामद कर ली गई हैं। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान चंद्रबाबू, निवासी सर्वोदय नगर, थाना मिलएरिया, निगम कुमार, निवासी सर्वोदय नगर, थाना मिलएरिया, और प्रवेश कुमार, निवासी विसन का पुरवा, थाना भदोखर के रूप में हुई है।

पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपी पेशेवर चोर हैं और पूर्व में भी चोरी की घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

ग्रीन वैली इंटर कॉलेज में खेल प्रतिभाओं का शानदार प्रदर्शन

जन एक्सप्रेस । अमेठी

बृहस्पतिवार को एम.जे.एस. मेमोरियल ग्रीन वैली इंटर कॉलेज राजगढ़ गौरीगंज में शैक्षिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत आयोजित स्पोर्ट्स मीट का शुभारंभ पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ हुआ।विद्यालय परिसर खेल, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधक मंशाराम मौर्य, मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र वर्मा तथा वरिष्ठ अध्यापक कमला नन्द तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया।स्पोर्ट्स मीट के प्रथम दिवस तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी शारीरिक क्षमता, आत्मविश्वास और अनुशासन का उत्कृष्ट परिचय दिया।बालक एवं बालिका वर्ग में आयोजित मुकाबले दर्शकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहे।तैराकी प्रतियोगिता में आरिफ,दीपिका,आयुष, दीपांशु एवं पायल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया।खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित अतिथियों और शिक्षकों ने तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ाया।विजेताओं को विद्यालय प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए गए।इस अवसर पर प्रबंधक मंशा राम मौर्य ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम हैं,बल्कि यह जीवन में अनुशासन,नेतृत्व और टीम भावना भी विकसित करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र वर्मा ने विद्यार्थियों को खेलों के साथ पढ़ाई में भी संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा दी।कार्यक्रम को सफल बनाने में रेफरी चौरसिया,विजय तिवारी, सोनू, ऋषभ, प्रीति तिवारी, सौरभ मिश्रा,अशोक वर्मा सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकों व कर्मचारियों का सराहनीय योगदान रहा।आयोजन के समापन पर विद्यालय परिवार ने प्रतिभागी खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

जनपद में 32 गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित

जन एक्सप्रेस । रायबरेली

रबी विपणन वर्ष 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के आदेशानुसार जनपद रायबरेली में क्रय एजेंसी खाद्य विभाग के 27 तथा भा0खा0नि0 के 05 प्रेषित प्रस्तावों के अनुसार 32 गेहूँ क्रय केन्द्रों को खोले जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अनुसार तहसील सदर के ब्लाक राही में 06 एवं ब्लाक सतांव में 01 एवं ब्लाक हरचन्दपुर में 03 गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है। इसी प्रकार तहसील महराजगंज के ब्लाक महराजगंज 07, ब्लॉक शिवगढ़ 01, तहसील/ब्लाक लालगंज में 02, तहसील/ब्लाक ऊँचाहार में 04, तहसील/ब्लाक डलमऊ में 02, तहसील/ब्लाक सलोन में 03, ब्लाक डीह में 01 एवं ब्लाक छतोह में 02 गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिये है कि गेहूँ क्रय केन्द्रों पर गेहूँ खरीद से संबंधित समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराते हुए शासनादेशानुसार/नियमानुसार समस्त कार्यवाही ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

एनसीसी छात्रों की रैली से गूंजा गौरीगंज सड़क सुरक्षा को लेकर दिया जागरूकता का संदेश

जन एक्सप्रेस । अमेठी

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जनपद मुख्यालय गौरीगंज कस्बे में गुरुवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई।इस रैली में एनसीसी के छात्र-छात्राओं ने अनुशासित मार्च करते हुए लोगों को सुरक्षितयातायात के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।रैली के दौरान कस्बे का मुख्य मार्ग सड़क सुरक्षा के नारों से गूंज उठा।जागरूकता रैली में शामिल एनसीसी कैडेट्स ने हाथों में तख्तियां लेकर ÷सड़क सुरक्षा,जीवन रक्षा÷, ÷हेलमेट पहनें, जीवन बचाएं÷ और ÷सीट बेल्ट आपकी सुरक्षा÷ जैसे प्रभावशाली नारे लगाए।छात्रों ने राहगीरों और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।रैली का नेतृत्व एआरटीओ महेंद्र बाबू गुप्ता ने किया।इस मौके पर पीटीओ,जिला यातायात प्रभारी सहित यातायात विभाग की टीम भी मौजूद रही।अधिकारियों ने रैली के माध्यम से आमजन को यह संदेश दिया कि थोड़ी सी सावधानी और नियमों का पालन कई कीमती जिंदगियों को बचा सकता है।रैली के दौरान विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने और चारपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की अपील की गई। एआरटीओ महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।यातायात माह और यातायात सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया जाता है।इसी कड़ी में यह जागरूकता रैली आयोजित की गई है।उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।यदि सभी लोग नियमों का पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।रैली के समापन पर एनसीसी छात्रों की भूमिका की सराहना करते हुए उन्हें समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

सेना में चयनित एनसीसी कैडेटों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित

जन एक्सप्रेस । बलरामपुर

जनपद बलरामपुर के एमएलके पीजी कॉलेज में संचालित एनसीसी की ओर से सेना में चयनित जवानों के सम्मान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गत दिनों किया गया। इस दौरान अपने विद्यालय से मिले सम्मान से अविभूत जवानों ने राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया।

जानकारी के अनुसार समारोह का शुभारंभ महाविद्यालय प्राचार्य प्रो0 जे पी पाण्डेय, मुख्य नियंता प्रो0 वीणा सिंह, प्रो0 अरविंद द्विवेदी, प्रो0 एस पी मिश्र, प्रो0 रेखा विश्वकर्मा व लेफ्टिनेंट डॉ देवेन्द्र कुमार चौहान ने दीप प्रज्वलित एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। सभी को बधाई देते हुए प्राचार्य प्रो0 पाण्डेय ने कहा कि आज का दिन हमारे संस्थान के लिए अत्यंत गौरवशाली है। महाविद्यालय के इन प्रतिभावान युवाओं का चयन भारतीय सेना में होना न केवल इनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे संस्थान के लिए सम्मान की बात है। आपने यह साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छाशक्ति और कड़े अनुशासन से किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे सैनिकों, अब आप साधारण युवा नहीं, बल्कि इस महान राष्ट्र के प्रहरी हैं। वर्दी की गरिमा बनाए रखना, %सर्विस बिफोर सेल्फ% (सेवा स्वयं से पहले) के सिद्धांत पर चलना, और विपरीत परिस्थितियों में भी साहस का परिचय देना—यही आपकी पहचान होगी। सभी जवानों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय के एसोसिएट एन सी सी ऑफिसर लेफ्टिनेंट (डॉ) देवेन्द्र कुमार चौहान ने कहा कि सीमाओं पर आप अपनी ड्यूटी के दौरान, याद रखिएगा कि पूरा देश आपकी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत है। आपके कंधे पर जो जिम्मेदारी है, वह बहुत बड़ी है, और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। सेना का जीवन केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक संस्कृति है—त्याग और समर्पण की संस्कृति। आप सभी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को प्रमुखता से निभाएं। आपके उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम का संचालन सह परीक्षा प्रभारी डॉ सुनील कुमार शुक्ल ने किया। समारोह में सीआरपीएफ ष्टश्वक्क में चयनित अभिषेक उपाध्याय व बसंत लाल यादव, एसएसबी स्स्क्च में आलोक कुमार तिवारी, सीआईएसएफ ष्टढ्ढस्स्न में अजय कुमार गोस्वामी तथा भारतीय नौसेना के लिए रूबी वर्मा व शिवनाथ गोस्वामी तथा एनसीसी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वीरेन्द्र कुमार को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रो0 तबस्सुम फरखी, डॉ राम रहीस, डॉ शिव महेंद्र, डॉ अजहरुद्दीन, डॉ सुनील मिश्र, डॉ स्वदेश भट्ट, डॉ प्रखर त्रिपाठी, डॉ बसंत कुमार, डॉ ऋषि रंजन व डॉ लवकुश पाण्डेय मौजूद रहे।

अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन

जन एक्सप्रेस । तुलसीपुर बलरामपुर

जनपद बलरामपुर के गैसडी में गत दिनों सम्पन्न हुए पांच दिवसीय गायत्री महायज्ञ के साथ नव विवाहित जोड़ों में उनके कर्तव्य बोध के लिए एक इकतीस युगलों का नव दाम्पत्य सम्मेलन व शिक्षक छात्र सम्मेलन के साथ कथा प्रवचन सम्पन्न हुआ था। आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने में तन-मन-धन से शामिल सृजन सेनानियो, पत्रकार बंधुओं और समाज के वरिष्ठों के साथ गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ता का अनुयाज के क्रम में 31 जनवरी 2026 को स्थानीय रामलीला मैदान में होगा।

जानकारी के अनुसार 29 जनवरी को अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार से जनजागरण ज्योति कलश रथ यात्रा 13 फरवरी से 28 फरवरी तक बलरामपुर जनपद का भ्रमण करेगी। इसी परिपेक्ष्य में यात्रा की तैयारी हेतु गायत्री परिवार के सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक गोष्ठी बलरामपुर गायत्री शक्तिपीठ पर 1 फरवरी को आहूत की गई है। इसकी तैयारी पूरी करने के लिए गायत्री परिवार के जिला समन्वयक सत्य प्रकाश शुक्ला, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रभारी आद गुलाब चंद भारती, मंदिर व्यवस्थापक सतीश मिश्रा सहित जनपद युवा प्रभारी संदीप जायसवाल, संजय जायसवाल, प्रदीप गोयल, नीरज गुप्ता, माता प्रसाद गुप्ता, श्रीराम भारती, सुनील वर्मा, कृष्ण कुमार कश्यप तथा महिला मंडल की सदस्यों की उपस्थिति रहेगी।

बार काउंसिल चुनाव में यशपाल सिंह को मिल रहा सभी वर्गों का समर्थन

जन एक्सप्रेस । रायबरेली

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश चुनाव के चौथे एवं अंतिम चरण में रायबरेली जनपद के अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस सेवा फाउंडेशन की बैठक में बार काउंसिल सदस्य पद के प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता यशपाल सिंह के पक्ष में मतदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि यशपाल सिंह न केवल एक अनुभवी अधिवक्ता हैं, बल्कि कानून और समाज सेवा के क्षेत्र में भी निरंतर सक्रिय रहते हुए अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं। इस मौके पर प्रत्याशी यशपाल सिंह ने अपना विजन बताते हुए सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। सेंट्रल बार एसोसिएशन, रायबरेली के अध्यक्ष राकेश तिवारी और महामंत्री योगेंद्र दीक्षित ने यशपाल सिंह को योग्य प्रत्याशी बताते हुए उनके पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। पूर्व अध्यक्ष रामबरन सिंह, कमलेश चंद्र पांडेय और पूर्व महामंत्री गंगा प्रसाद यादव ने यशपाल सिंह को अधिवक्ताओं का सच्चा हितैषी बताते हुए कहा कि उन्हें न केवल जिले में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के अधिवक्ताओं का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। फाउंडेशन के सचिव अनूप श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिवक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित अधिवक्ताओं ने एक स्वर में प्रत्याशी यशपाल सिंह को प्रथम वरीयता का मत देने का निर्णय लिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता अम्बरीष अग्रवाल, शिव कुमार श्रीवास्तव, अनूप जायसवाल, विजय द्विवेदी, कमलेश चंद्र श्रीवास्तव, विजय मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव, राजकुमार, उत्तम श्रीवास्तव, राहुल यादव, मयंक खरे, योगेन्द्र शुक्ला, पुनीत सिंह जगाधरी, शशिकांत, अमरेश श्रीवास्तव, प्रभु कुमार, प्रदीप कुमार, इन्द्र कुमार सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।

21 नवजात कन्याओं का हुआ कन्या जन्मोत्सव

जन एक्सप्रेस । रायबरेली

जिला महिला चिकित्सालय में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन केक कटवाकर और नवजात बालिकाओं को बेबी किट और कॉफी मग वितरित कर मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राघवेन्द्र प्रताप सिंह, जिला पंचायत सदस्य द्वारा अपने वक्तव्य में बताया गया कि समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना ही नए भारत की नींव है। बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य, शिक्षा एवं अधिकारों पर जोर दिया गया तथा समाज से बाल विवाह न करने की अपील की गई। जिला प्रोबेशन अधिकारी जयपाल वर्मा द्वारा उपस्थित महिलाओं को बाल विवाह जैसी कुप्रथा के प्रति जागरूक किया गया तथा बच्चियों एवं महिलाओं संबंधी योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला हेल्पलाइन 181, 1090 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गई।

भाकपा (माले) ने मतदाता पुनरीक्षण के तहत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की कड़ी आलोचना

जन एक्सप्रेस । रायबरेली

भाकपा (माले) ने जनपद में गहन मतदाता पुनरीक्षण के तहत तीन लाख अडतालीस हजार आठ सौ सड़सठ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह सब एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। अकुशल , अप्रशिक्षित बीएलओ, समय की कमी प्रशासनिक दबाव तथा सत्ता धारी दल की मंशा के अनुरूप चुनाव आयोग की अघोषित गरीबों,दलितो,अल्पसंख्यकों का वोट काटने की दिशा का मिला जिला परिणाम है। भाकपा (माले) राज्य कमेटी सदस्य विजय विद्रोही और माले जिला सचिव हनोमान अम्बेडकर ने संयुक्त बयान में कहा कि 2003 की मतदाता सूची में नाम होने, माता ,पिता का नाम होने, उनके पुस्तैनी घर , जमीन ,संपत्तियां होने के बावजूद लोगों के नाम काट दिए गए। उन्होंने कहा अब दूसरे दौर में भी उसी तरह का खेल जारी है। अधिकांश लोगों को नोटिस भी नहीं दिया जा रहा है। यही नहीं समय इतना कम दिया जा रहा है कि महिलाओं के लिए अपने पितृजन का अभिलेख उपलब्ध कराना इतनी अल्पावधि में संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी ग्राम सभा के सचिवालय, आंगनवाड़ी केंद्र में मतदाता सूची निरीक्षण के लिए सार्वजनिक रूप से नहीं प्रदर्शित की गई है। जिन गांवों में दूसरे दौर की प्रक्रिया कथित रूप से चल रही है, वहां भी कोई सूचना सार्वजनिक नहीं की जा रही , न डुग्गी , न मुनादी ,न सचिवालय पर नोटिस और न बीएलओ द्वारा घर घर सूचना ही दी जा रही है। माले नेताओं ने कहा कि संविधान में मिला एक मूल अधिकार तिकड़म के जरिए छीनकर एक असंतुलित मतदाता सूची बनाकर फासिस्ट ताकतें सत्ता पर निरंतर काबिज होने की जमीन तैयार कर रही हैं। इसके खिलाफ माले ने संविधान बचाओ, मताधिकार बचाओ अभियान शुरू किया है । माले नेताओं ने आज कुचरिया गांव के मुहल्ले के बाहर किए गए मतदाताओं की सूची के साथ जिलाधिकारी को प्रतिवाद पत्र सौंपने के साथ आगामी 31 जनवरी 2026 को इसके विरुद्ध जिला मुख्यालय में प्रतिवाद प्रदर्शन का ऐलान किया।

पृथ्वी पर जब- जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान का जन्म होता हैः पंडित आशीष महाराज

जन एक्सप्रेस। कानपुर नगर

बिठूर के 40 फिट हनुमान मंदिर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 33वां वार्षिकोत्सव बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस बार भी वार्षिकोत्सव में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र पावन कथा एवं ज्ञान यज्ञ एवं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कार्यक्रम के पंचम दिवस वृंदावन से पधारे सुप्रसिद्ध कथा व्यास पं. आशीष जी महाराज नें श्रोता समाज को बताया कि भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करने से पापों का शमन हो जाता है। भारत भूमि में परमात्मा ने कई बार अवतार लेकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए दैत्य का संघार कर उद्धार किया है। जिसमें पूतना जो कि वासना का प्रतीक थी का उद्धार किया। कथा में आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को धर्म के हिसाब से चलना चाहिए क्योंकि सनातन ही सर्वोपरि है जो इंसान धर्म के अनुसार नहीं चलता है उसका सदैव नुकसान ही होता है हिंदू सनातन संस्कृति सनातन धर्म का महत्व पूरी देश और दुनिया में है क्योंकि हमारा धर्म सबसे पहले आया है कथा व्यास ने बताया कि हिंदू समाज जागरूक हो और आसपास हो रही कथाओं धार्मिक हिंदू कार्यक्रम में बड़ी से बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करें महिलाओं से कथा व्यास ने बताया कि किसी भी तरह का कोई भी काम घर में करते समय प्रभु का गुणगान जरूर करें क्योंकि जब आप प्रभु का गुणगान करते हैं तब आपका मन मस्तिष्क में गलत विकार नहीं पैदा होते हैं बच्चों को संस्कार दें शिक्षित करें सनातन संस्कृति के बारे में बताएं राम कृष्ण के बारे में बताएं बिठूर वे स्थान है जहां देश और दुनिया से हर इंसान घूमते ही नहीं बल्कि यहां का महत्व जानने आता है जब बिठूर कानपुर का महत्व तथा व्यास ने बताया कि नेपाल में कथा के दौरान उन्होंने व्याख्या की तो वहां के आम नागरिक व्याकुल हुए कि ऐसे तीर्थ स्थल का पर हम भी घूमने चाहेंगे और उसका महत्व समझाने का प्रयास करेंगे बिठूर तीर्थ देश और दुनिया में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है क्योंकि मां गंगा एवं लवकुश धाम मां सीता की कहानी की अद्भुत नगरी हैं कथा के कार्यक्रम में आसपास की महिलाएं बच्चे बुजुर्ग नौजवान एकत्रित होकर कथा का रसपान कर रहे हैं और कथा का महत्व समझकर अपने जीवन में अच्छी और बुरी आदतों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए पं. उत्तम शुक्ला ने बताया कि 2 दिन बचे हैं अमृत कथा के और इन दो दिन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष समेत अन्य तमाम जनप्रतिनिधि गण इस बिठूर पवित्र पावन धाम पर चल रही कथा में शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनिल द्विवेदी, सूबेदार पांडे, सिपाही लाल यादव, कथा संयोजक दीपक अवस्थी, अंकित जी महाराज, सोनू महाराज, व्यवस्थापिका श्रीमती अल्पना तिवारी, एवं महंत श्री देवदास जी महाराज मौजूद रहे।

उच्चतम न्यायालय का यूजीसी विनियम, 2026 पर स्थगन का आदेश स्वागत योग्य

सभी वर्गों से सौहार्द बनाए रखने की अपीलः अभाविप

जन एक्सप्रेस। कानपुर नगर

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानो में समता संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 पर स्थगन आदेश का स्वागत करती है। यह आदेश वर्तमान में देशभर में यूजीसी समता नियमों में अस्पष्टता को लेकर चल रही भ्रांति को रोकते हुए संवैधानिक समता और समानता के अंतर्निहित मूल्यों के पक्ष में महत्वपूर्ण है और यह आदेश अभाविप द्वारा उक्त विषय पर जारी वक्तव्य में यूजीसी नियमों पर स्पष्टीकरण की मांगों के भी अनुरूप है। इस विषय संबंधी वर्ष 2012 के विनियम पूर्ववत जारी रहेंगे।

अभाविप का मानना है कि यूजीसी और सभी शैक्षणिक संस्थानों को लोकतंत्र की उस अंतर्निहित भावना को अक्षुण्ण रखना चाहिए, जहाँ प्रत्येक नागरिक के पास समान अधिकार हों और भारत भेदभाव मुक्त तथा समता युक्त बने। यह बात अभाविप ने अपने पूर्व वक्तव्य में भी स्पष्ट करते हुए जारी किये गए विनियम पर स्पष्टता और संतुलन बनाए रखने की मांग की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ द्वारा इस निर्णय की काफी आवश्यकता थी क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में इस विनियम को लेकर काफी भ्रांति भी फैली थी, जिससे विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य वैमनस्य पैदा होने की आशंका थी। अभाविप का यह स्पष्ट मत है कि शैक्षिक परिसर में सदैव ही सकारात्मक, भेदभावमुक्त एवं समतायुक्त परिवेश रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिले।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि, माननीय उच्चतम न्यायालय का यूजीसी रेगुलेशन पर स्थगन का आदेश स्वागतयोग्य है। अभाविप सदैव से शैक्षणिक परिसरों में समता, सौहार्द एवं समान अवसरों की पक्षधर रही है। यूजीसी द्वारा जारी किए गए विनियमों में स्पष्टता एवं संतुलन का अभाव छात्रों के बीच भ्रम और असंतोष को जन्म दे सकता है। न्यायालय का यह हस्तक्षेप समयोचित है और इससे संवाद व विमर्श के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। अभाविप सभी वर्गों, छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों से अपील करती है कि वे शांति, संयम और सौहार्द बनाए रखें तथा राष्ट्रहित में रचनात्मक संवाद के माध्यम से समाधान की दिशा में आगे बढ़ें।

अभाविप कानपुर प्रान्त के प्रांत मंत्री दिनेश यादव ने कहा कि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी समता विनियम, 2026 पर स्थगन का आदेश स्वागतयोग्य है। यह निर्णय शैक्षिक परिसरों में व्याप्त भ्रम को दूर करेगा और सभी वर्गों के मध्य सौहार्द बनाए रखने में सहायक होगा।

बारह घण्टे के समय में वोटर कैसे देगा एसआईआर नोटिस का जवाब

- एसआईआर में कटी नोटिसों पर दिया जा रहा बारह घण्टे में उपस्थित होने का समय

जन एक्सप्रेस। सीतापुर

एसआईआर व्यवस्था को लेकर अफरा तफरी का माहौल कायम है। इस कार्य में लगे अफसर तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे है लेकिन उनके अधीनस्थो की लापरवाही नागरिकों पर भारी पड़ रही है। जिससे नागरिक साइबर से लेकर कैम्प तक जाकर अपनी फरियाद करते है। कुछ कर्मचारी तो नागरिक को सीधा रास्ता बता देते है लेकिन कुछ कर्मचारी इस कदर नागरिको को परेशान कर रहे कि वह नोटिस में सही प्रपत्र लगाने का मतलब हथेली पर सरसो उगाने के बराबर समझने लगा है। मामला मण्डी स्थल में लगे एसआईआर कैम्पे से सामने आ रहा है। यहां पर सबसे चर्चित और अपने चैम्बर के सामने लाइन लगवाने में माहिर कहे जाने रत्नेश त्रिपाठी पीड़ितो का खड़ा करने के साथ ही उनको परेशान कर रहे है। हर बात वह कहते है कि जाओं जिलाधिकारी से मिलकर अपना कार्य करवाओं जाकर। पीड़ितो की समस्याओं को वह सुनते ही नही है जिसका परिणाम यह निकल रहा है कि पीड़ित दिन भर लाइन में लगा रहता है और बाद में परेशान होकर चला जाता है। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे है कि एसआईआर की नोटिस में हम इतना परेशान नही हो पायेगे जो होगा देखा जायेगा। हर व्यक्ति एसआईआर को प्राथमिकता देकर बताये गये नियमों पर चल रहा है लेकिन नियमो पर चलने वाले नागरिकों के लिये कैम्प में तैनात किये गये जिम्मेदार अफसर परेशानी का सबब बन रहे है। मण्डी परिसर के एक कैम्प के इचार्ज रत्नेश को बनाया गया है। वह इस समय मनमानी पर उतारू हो गये है। नोटिस का समाधान कराने आये व्यक्तियों मुं मन चाहा समाधान किया मनचाहा तो कह दिया ऑन लाइन समाधान करवा लो अगर किसी ने तनिक भी कह दिया कि सर यही से देख लो तो वह सीधे कहते है कि जाओं डीएम से अपना काम करवा लो। इस तरह से पीड़ित व्यक्ति और भी जयादा परेशान हो रहा है। अगर कहीं रत्ने का चैम्बर कैमरे की नजर में हो कैमरे में हो रही कार्यवाही से हकीकत का पता चल जायेगा और यह भी पता चल जायेगा कि इस कदर भीड़ क्यो लगी हुई है।

बीएलओ की ममानी बनी सरदर्द

सबसे ज्यादा तो बीएलओ द्वारा परेशान किया जा रहा है। बीएलओ द्वारा एसआर की नोटिस पहुचाई जा रही है। बीएलओ का आलम यह है कि वह नोटिस का जवाब देने के लिये केवल एक रात का ही समय देता है। अब अफसर ही समझे कि रात में पीड़ित नोटिस का जवाब और प्रापत्र कैसे तैयार कर सकता है कम से कम उसको दो चार दिनों का समय तो देना ही चाहिए। हरदोई चुंगी के बीएलओ ने एक युवक को एसआईआर की नोटिस दी नोटिस 21 जनवरी की शाम को दी गई और तारीख उपस्थित होने की तारीख बाइस जनवरी को लगा दी है। जब शाम को नोटिस दी जायेगी तो भला एक ही रात में वह नोटिस का जवाब कैसे दे पायेगे। पीड़ित ने बीएलओ से बात की बीएलओ ने कहा मण्डी जाकर रत्नेश से मिलो पीडित रत्नेश के पास गया तो उन्होने कहा बीएलओ से मिलो पीड़ित ने कहा बीएलओ से मिल चुके है तो रत्नेश ने कहा ऑन लाइन करवाओं जाकर या फिर सीधे जिलाधिकारी से मिलो बस पीड़ित की गलती इतनी थी कि उसने रत्ने से कह दिया था कि सर शाम में नोटिस भेजी जाती है रातभर में जवाब कैसे तैयार किया जाता है नोटिस भेजने और उपस्थित होने का समय कितना होना चाहिए इस पर कोई गाइड लाइन है क्या?

नही उठा एसडीएम सदर का फोन

इस सम्बन्ध में जब एसडीएम सदर से जाने लेने के लिये उनके सीयूजी नम्बर पर कई बार काल की गई। लेकिन बजती रही घण्टी नही उठा फोन। इस कारण इस मामले पर उनका पक्ष नही जाना जा सका।

बीस हजार रूपये का ईनामी डकैत कलीम गिरफ्तार

जन एक्सप्रेस। सीतापुर

थाना तालगांव पुलिस टीम द्वारा तालगांव क्षेत्रांतर्गत हुई डकैती की घटना में वांछित अभियुक्त कलीम पुत्र नूर अहमद निवासी संगत टोला कस्बा व थाना तम्बौर जनपद सीतापुर को ग्राम सलेमपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त से घटना संबंधी माल कुल 10,000- रुपये तथा 01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। अभियुक्त ने साथियों के साथ मिलकर थाना तालगांव क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर में गांव के बाहर बने एक पक्के घर जो किसी लेखपाल का है, के अन्दर प्रवेश कर तमंचों से लैस होकर वहां मौजूद लोगो को डरा धमकाकर अलमारी का ताला तोड़कर डकैती डाली थी, घटना के संबंध में थाना तालगांव पर मु.अ.सं.15/26 पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में पूर्व में 07 संलिप्तो को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं वांछित उपरोक्त अभियुक्त कलीम की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु

कानपुर में विज्ञान फाउंडेशन की कार्यशाला

श्रमिकों को नए श्रम कानूनों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की दी गई जानकारी

जन एक्सप्रेस। कानपुर नगर

विज्ञान फाउंडेशन द्वारा श्रमिकों के सामाजिक उत्थान और श्रम कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला गुमटी नंबर 5 स्थित होटल सेलिब्रेशन में 'माइग्रेंट रेसिलियंस कोलैबोरेटिव' परियोजना के अंतर्गत संपन्न हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य जनपद के प्रवासी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और नए श्रम कानूनों की जानकारी देना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रम विभाग के श्रम परिवर्तन अधिकारी अखिलेश कुमार वर्मा उपस्थित रहे। उनके साथ विज्ञान फाउंडेशन के रामायण यादव, जनसाहस फाउंडेशन के राज्य समन्वयक सैफ जिलानी, क्वालिटी एंड डेवलपमेंट समन्वयक सोनू तथा संस्था की कोर टीम ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ सोनू ने स्वागत संबोधन और रूपरेखा प्रस्तुति के साथ किया।

सत्र के दौरान अखिलेश कुमार वर्मा ने केंद्र सरकार द्वारा लागू चार नए लेबर कोड और उनसे जुड़े प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही श्रम कल्याण परिषद और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (क्व्ह्ष्ट्ड्ढ) की योजनाओं के लाभ और पंजीकरण प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया। सामाजिक सुरक्षा और श्रमिक संरक्षण से जुड़े कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा हुई।

अंत में सैफ जिलानी ने परियोजना की प्रगति की सराहना की, जबकि रामायण यादव ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार जताया। कार्यशाला का मुख्य संदेश रहा- श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें योजनाओं से जोड़ना।

परिवार के भरण-पोषण के लिए निकाला भुगतान-प्रधानपति हीरापुर

जन एक्सप्रेस। सीतापुर

विकास खण्ड पहला में सचिवो व प्रधानो के अजीबो गरीब कारनामे खुलकर सामने आ रहे है, शासन के द्वारा दिनाक 26 अप्रैल 2022 को पत्रांक संख्या 710/33-3-2022-11/2022 में मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रधानो के द्वारा सामग्री आपूर्ति व अन्य कार्यो के लिए परिवारीजनों व नाते रिश्तेदारो के नाम ग्राम निधि से भुगतान नही किया जाएगा, लेकिन विकास खण्ड पहला में सचिवो व प्रधानो के द्वारा जारी आदेशो की घज्जिया उड़ाई जा रही है विकास खण्ड में तैनात सचिव आरती गौर की तैनाती वाली ग्राम पंचायतो में जमकर प्रधान परिजनों के नाम ग्राम निधि से भुगतान कर सरकारी धन का बंदरबाँट किया जा रहा है, सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत हीरापुर में प्रधान सविता देवी पत्नी सुनील कुमार से सांठगांठ कर प्रधान के परिवारीजनों के नाम भुगतान निकाल कर जारी आदेशो की घज्जिया उड़ा दी गयी है, प्रधान ने सचिवो से मिलीभगत कर अपने पति सुनील कुमार पुत्र श्यामसुंदर के नाम पर लगभग 1 लाख 80 हजार रुपये का भुगतान किया गया वही प्रधानपति के भाइयो विजय पुत्र श्यामसुंदर, अवधेश,अमरेश कुमार, व प्रधानपति के चचेरे भाइयो प्रदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश व संदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश के नाम पर भी लाखो का भुगतान कर सरकारी धन का दुरूपयोग किया है, समाचार पत्र में प्रकाशित खबर को देखकर आक्रोशित होकर प्रधानपति सुनील कुमार ने फोन करके धमकी देते हुए बताया कि हम कोर्ट जाकर मुकदमा करेंगे तुमने खबर क्यो प्रकाशित की है, तुम्हारा क्या ले रहे है मैं ऐसे किसी आदेश के बारे में नही जानता हूं जिसमे कहा गया प्रधान अपने घरवालों के नाम भुगतान नही कर सकता हो, अगर ऐसा आदेश है भी तो क्या मेरे घरवाले भूखे मर जाये हमने घरवालों से काम कराया और उनके नाम भुगतान भी निकाला है। अब सवाल यह उठता है कि क्या शासन से जारी आदेश मात्र जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय तक ही दफन हो जाते है या फिर जारी आदेश सचिवों तक जाकर ही सीमित रह जाते है प्रधानों को आदेशों को सम्बन्ध में सचिव द्वारा जानकारी नही दी जाती है। और सचिव अपनी मनमानी कार्यशैली को अपनाते हुए जारी आदेशों को ताख पर रखकर सरकारी धन का दुरूपयोग करते रहते है क्योंकि ग्राम पंचायत में तैनात सचिव आरती गौर द्वारा पूर्व में भी यह कहा जा चुका है कि हम सरकारी आदेशों को नही मानते है अपनी अपनी कार्यशैली के अनुसार कार्य करते है।

बहुचर्चित जे ई की तरह पहला में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते एडीओ पंचायत

विकास खण्ड पहला के बहुचर्चित जे ई जोकि विकास खण्ड पहला को लेकर हमेशा चर्चाओं में बने रहते है शिकायत उपरांत भी कार्यवाही मात्र कागजपूर्ती तक ही सीमित रह जाती है, विकास खण्ड पहला में बहुचर्चित जे ई बाद सहायक विकास अधिकारी पंचायत दिनेश मिश्रा विकास खण्ड क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है बताते चले कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत पूर्व में विकास खण्ड क्षेत्र में सचिव के पद पर कार्यरत रखकर विकास खण्ड क्षेत्र में अपना कार्यकाल पूर्ण कर गैर- जनपद में स्थानांतरित किए गए थे सचिव के बाद मजबूत सांठगाठ के चलते सहायक विकास अधिकारी पंचायत दिनेश मिश्रा पदोन्नति होते ही जनपद सीतापुर में पुनः स्थानांतरण कराकर विकास खण्ड पहला में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पद को सणरक्षंदाताओ के बल पर हथिया लिया बताते चले कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत केपी सिंह जोकि लम्बे समय से नियमो का ताख पर रखकर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय सम्बद्ध थे सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार दी गयी शिकायतों के बाद सहायक विकास अधिकारी पंचायत के.पी. सिंह को विकास खण्ड पहला में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पद पर तैनात किया गया था लेकिन सहायक विकास अधिकारी पंचायत दिनेश मिश्रा के जनपद में आते ही संरक्षणदाताओं ने चंद दिनों में ही सहायक विकास अधिकारी पंचायत के.पी सिंह को विकास खण्ड महमूदाबाद में तैनात करते हुए सहायक विकास अधिकारी पंचायत दिनेश मिश्रा को विकास खण्ड पहला में तैनात किया गया जिससे सचिव के पद पर रहकर दिनेश मिश्रा द्वारा जँहा चंद ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की ट्रेन दौड़ाई जा रही थी वही सहायक विकास अधिकारी पंचायत के पद पर रहकर दिनेश मिश्रा द्वारा पूरे विकास खण्ड में भ्रष्टाचार की एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ा सके जिससे यह प्रतीत होता है कि संरक्षणदाताओं के बलबूते पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत दिनेश मिश्रा विकास खण्ड क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिये लगातार प्रयासरत है।

एक्सप्रेस खबरें...

दफा 25 के तहत गिरफ्तार

जन एक्सप्रेस। सीतापुर। थाना मछरेहटा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त नौशाद पुत्र सत्तार निवासी ग्राम गदपुरवा थाना मछरेहटा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। बरामद अवैध शस्त्र के संबंध में थाना मछरेहटा पर मु0अ0सं0 25/26 धारा 25(1-बी) आर्म एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त उपरोक्त का चालान न्यायालय किया गया है।

चोर गिरफ्तार नगद व शस्त्र बरामद

जन एक्सप्रेस। सीतापुर। थाना सिधौली पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर चोरी के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 445/2025, मु0अ0सं0 446/2025 धारा 317(2)/331(4)/305ए बीएनएस थाना सिधौली, मु0अ0सं0 340/25, 341/25 धारा 317(2)/331(4)/305ए बीएनएस में वांछित अभियुक्त लुकमान पुत्र इसरार निवासी ग्राम अकहोरा थाना सिधौली को मनिकापुर सिधौली मार्ग के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त उपरोक्त के पास से 4,150 रूपये नगदी(अभियोगों से संबंधित) व एक अदद तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुए है।

डीएम ने किया भण्डारण कक्ष का निरीक्षण

जन एक्सप्रेस। सीतापुर। जिलाधिकारी डा0 राजागणपति आर0 ने आज इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन भण्डारण कक्ष एवं वी0वी0 पैट भण्डारण कक्ष का मासिक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखीं एवं आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित को दिये। उन्होंने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन भण्डारण कक्ष में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे की जांच टी0वी0 स्क्रीन पर देखी एवं साफ-सफाई के निर्देश भी दिये।इस दौरान अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

छात्रावासों में मनाया गया गणवतंत्र दिवस

जन एक्सप्रेस। सीतापुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोती लाल ने बताया कि उ0प्र0 शासन निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा गणतन्त्र दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा जनपद सीतापुर में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासों में जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थित में गणतन्त्र दिवस कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया। उक्त कार्यक्रमों में छात्रावासवार में राजकीय अनुसूचित जाति (बालिका) छात्रावास, सदर सीतापुर में सभासद सुरेश चन्द्र कनौजिया एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर। राजकीय अनुसूचित जाति (बालक) छात्रावास, तरीनपुर सीतापुर में सभासद किशोरी लाल एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर। राजकीय अनुसूचित जाति (बालक) छात्रावास, महोली सीतापुर में प्रधानाचार्य डॉ0 सुशील चन्द्र त्रिवेदी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर। राजकीय अनुसूचित जाति (बालक) छात्रावास, बिसवाँ सीतापुर में प्रधानाचार्य सुरेश चन्द्र मौर्या एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर। बाबू जगजीवनराम (बालक) छात्रावास, महमूदाबाद सीतापुर में प्रधानाचार्य अमित कुमार बघेल एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी, उपस्थित रहे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एच.बी.टी.यू. मुख्य द्वार पर छात्रों ने यूजीसी शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया

जन एक्सप्रेस। कानपुर नगर

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी के गाइड लाइन रोकने के बाद एच बी टी यू मुख्य द्वार पर छात्रों ने यूजीसी की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया, छात्र नेता अभिजीत राय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश यूजीसी के मुंह पर तमाचा है वहीं छात्रनेता अनस व आर्यन का कहना है कि यूजीसी को अब अपनी गलती मान लेनी चाहिए और कोर्ट में माफीनामा लगाना चाहिए, वहीं छात्र जितेंद्र मिश्रा कृषि विश्वविद्यालय ने बोला कि हम छात्र एक हैं जाति में बांटने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे आगे भी ऐसा कोई कानून आया तो पुरजोर विरोध होगा, छात्र छात्राएं ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ में चढबढ़ के सहभाग किया पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रही और यूजीसी को सद्बुद्धि दो स्वाहा से पूरा माहौल गूंज उठा। इस दौरान रुद्राक्ष सिंह रेहटी , अखिल भूमिहार, अंशुमान त्रिपाठी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी आशीष द्विवेदी, रिद्धि शर्मा छात्रा सीएसए, समेत दर्जनों छात्र उपस्थित रहे।

गणित दिवस पर सम्पन्न हुए अनेको कार्यक्रम

जन एक्सप्रेस। सीतापुर

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में जिला विज्ञान क्लब सीतापुर द्वारा सीतापुर जनपद के सबसे प्राचीन विद्यालय उजागर लाल इंटर कॉलेज में आज भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष में राष्ट्रीय गणित दिवस कार्यक्रम में व्याख्यान वाला तथा निबंध भाषण तथा प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के 14 विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया इसमें निबंध प्रतियोगिता आलेखन प्रतियोगिता तथा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्यमंत्री राकेश राठौर गुरु ने मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके उपरांत प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों के द्वारा मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करके तथा बैच लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद निबंध प्रतियोगिता में उजागर लाल इंटर कॉलेज की दिव्या तथा पी एन सहगल इंटर कॉलेज सीतापुर की मन्नत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ पटेल इंटर कॉलेज की सुरभि तथा सरस्वती विद्या मंदिर सीतापुर की अनुराधा को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ,

जबकि उजागर लाल के पीयूष वर्मा तथा पी0एन0 सहगल इंटर कॉलेज के अनुभव को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 10 छात्र-छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए।

बिना नक्शे के बनवाया तो पचड़े में पड़ सकता है भवन

जन एक्सप्रेस। सीतापुर। नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र /नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि नगर में विकास से सम्बन्धित नियंत्रित क्षेत्र (विनियमित क्षेत्र) में भवन आवासीय व्यवसायिक औद्योगिक एवं अन्य निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी (नियत प्राधिकारी) से मानचित्र (नक्शा) की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।यह देखने में आता है कि कतिपय व्यक्तियों के द्वारा जानकारी के अभाव में या अनजाने में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण अथवा आवासीय भवन का व्यवसायिक उपयोग प्रारम्भ कर लिया जाता है। जोकि प्रचलित नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत अनुमन्य नही है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति को कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।यह स्पष्ट किया जाता है कि बिना स्वीकृत मानचित्र के कोई भी निर्माण, उपयोग परिवर्तन या व्यवसायिक गतिविधि नियम विरूद्ध मानी जायेगी तथा अवैध निर्माण कर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। ऐसी कार्यवाही में निर्माण को सील किया जाना, जुर्माना लगाया जाना अथवा अन्य वैधानिक कदम उठाया जाना शामिल हो सकता है।सीतापुर महायोजना-2031 के अन्तर्गत निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र कार्यालय से भवन मानचित्र की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

बाल विवाह जागरूकता रथ को एडीएम ने दिखाई हरी झण्डी

जन एक्सप्रेस। सीतापुर

> इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार अवस्थी, बाल कल्याण समिति के सदस्य संजय शुक्ला, चाइल्ड हेल्पलाइन सीतापुर

महिला कल्याण विभाग द्वारा बाल विवाह की जागरूकता हेतु जागरूकता रथ को जनपद की समस्त विकास खण्डो में जागरूकता हेतु रवाना किया गया, इस अवसर पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार अवस्थी, बाल कल्याण समिति के सदस्य संजय शुक्ला, चाइल्ड हेल्पलाइन सीतापुर के परियोजना समन्वयक द्वारा सभी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए हुए बताया गया कि बाल विवाह करने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास पूर्णतया नहीं हो पता है जिससे बालक एवं बालिकाओं का पूरा जीवन अंधकारमय बीतता है । बाल विवाह करना एक कानून अपराध है यदि कोई भी व्यक्ति बाल विवाह करता है तब उसको 1 लाख रुपए जुर्माना एवं 2 वर्ष तक का कठोरतम कारावास या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। परिवार, समाज, समुदाय एवं देश के प्रत्येक नागरिक को बाल विवाह रोकने हेतु सक्रिय सहभागिता के साथ बाल विवाह का अंत करना होगा तभी बाल विवाह मुक्त भारत संभव हो सकेगा और बताया गया कि विवाह करने की उम्र लड़की की 18 वर्ष से अधिक तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।

▸ पढ़ें पेज 12 पर...

जन एक्सप्रेस

सम्पादकीय

सरल नहीं पर प्रभावशाली थे अजित पवार

देखा जाये तो अजित पवार का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, यह उस राजनीतिक शैली का अंत है जो चुपचाप काम करने में यकीन रखती थी। उनकी राजनीति प्रशासनिक पकड़, आंकड़ों की समझ और सत्ता की नस पहचानने की कला से बनी थी। शरद पवार की विशाल छाया में राजनीति शुरू करना आसान था, लेकिन उस छाया से निकलकर अपनी पहचान बनाना बेहद कठिन था। अजित पवार ने यह कठिन रास्ता चुना। वह हमेशा इस द्वंद्व में रहे कि उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाए या एक स्वतंत्र नेता के रूप में।

महाराष्ट्र की राजनीति को आज तब गहरा आघात लगा जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में विमान हादसे में निधन हो गया। लैंडिंग के दौरान विमान में आई तकनीकी खराबी के बाद यह दुर्घटना हुई। हादसे की खबर फैलते ही राज्य भर में शोक की लहर दौड़ गई। देखा जाये तो अजित पवार महाराष्ट्र के उन नेताओं में थे जिन्होंने सत्ता के केंद्र में रहते हुए भी जमीन से नाता नहीं तोड़ा। वह भले ही कभी मुख्यमंत्री न बने हों, लेकिन राज्य में सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री रहने का इतिहास उनके नाम दर्ज है। छह बार उपमुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने वाले अजित पवार ने अलग-अलग सरकारों में अपनी प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखा। बारामती में अजित पवार की राजनीति का सबसे बड़ा प्रमाण उनका काम खुद था। वह उन गिने चुने नेताओं में थे जिनके लिए अपना खुद का चुनाव प्रचार एक औपचारिकता भर था। विधानसभा चुनावों में वह हमेशा समय पर अपना नामांकन दाखिल करते थे, लेकिन उसके बाद बारामती की गलियों में शायद ही कभी उन्हें प्रचार करते देखा गया। जनता जानती थी कि किसे वोट देना है, इसलिए जनता ही उनका प्रचार करती थी। अजित पवार का भरोसा नारों पर नहीं, काम पर था। इसी आत्मविश्वास के चलते वह बारामती से निश्चिंत रहकर राज्य के दूसरे इलाकों में पार्टी उम्मीदवारों के प्रचार में जुट जाते थे। बारामती उनके लिए सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं था, वह उनका कर्मक्षेत्र था, जहां उन्होंने यह साबित किया कि जब विकास बोलता है तो नेता को खुद बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अजित पवार ने 1982 में सहकारी क्षेत्र से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। वह चीनी मिल के बोर्ड में चुने गए और यहीं से बारामती की राजनीति में उनकी जड़ें मजबूत होती गईं। 1991 में वह पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने और उसी वर्ष बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए। बाद में उन्होंने यह सीट शरद पवार के लिए खाली की। इसके बाद वह बारामती से सात बार विधायक बने। उनके परिवार में पत्नी सुनेत्रा पवार और दो पुत्र जय और पार्थ हैं। सहकार से सत्ता तक का उनका सफर बारामती से शुरू हुआ और वहीं समाप्त हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को चुनाव आयोग ने पार्टी का मूल नाम और चुनाव चिन्ह सौंपा था। यह गुट भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति के साथ जुड़ा। वहीं उनके चाचा और वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अलग रह कर एनसीपी-एससीपी का नेतृत्व संभाला। यह विभाजन महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे भावनात्मक और निर्णायक मोड़ माना गया। दोनों पक्षों का विवाद अदालत के दरवाजे तक पहुँचा लेकिन हाल के दिनों में पवार परिवार एकजुट नजर आ रहा था। हम आपको याद दिला दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ उतार कर पारिवारिक और राजनीतिक रिश्तों में तीखापन ला दिया था, लेकिन समय के साथ उन्होंने यह स्वीकार किया था कि वह फैसला एक भूल था। राजनीति के उस कठोर दौर के बाद हालिया निकाय चुनावों में उन्होंने जिस परिपक्वता का परिचय दिया, वह उनके व्यक्तित्व का दूसरा और अधिक मानवीय पक्ष सामने लाता है। शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन कर दोनों एनसीपी को एक मंच पर लाने की पहल उन्होंने खुद की थी। बहन सुप्रिया के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने साफ कहा था कि परिवार में कोई मतभेद नहीं हैं और जनता चाहती है कि दोनों दल साथ मिलकर काम करें। यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक स्वीकारोक्ति भी थी। देखा जाये तो अपने निधन से पहले अजित पवार कम से कम इतना तो कर ही गए कि उन्होंने परिवार से सुलह कर ली।

एक्सप्रेस आलेख

भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। छोटे और मध्यम उद्योग जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, तभी फल–फूल सकते हैं जब उन्हें पर्याप्त घरेलू बाजार मिले। पर्यावरण की दृष्टि से भी स्वदेशी उत्पादों का महत्व बढ़ जाता है। जब हम स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो परिवहन से होने वाला कार्बन उत्सर्जन कम होता है। साथ ही, स्थानीय उत्पादन अक्सर पारंपरिक और टिकाऊ तरीकों का उपयोग करता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। गांधीजी ने भी कहा था कि पृथ्वी के पास हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।

कनाडा के प्रधानमंत्री की स्वदेशी अपनाने की अपील का संदेश

अशोक मधुप

कोविड–19 महामारी ने भी हमें सिखाया कि अत्यधिक आयात निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं टूट गईं, तो कई देशों को आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना पड़ा। भारत ने इस संकट से सीख लेते हुए दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, और अन्य आवश्यक वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया है।कभी हम न मास्क बनाते थे। न सेनेटाइजर, न अन्य उपकरण।

कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने देश के नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। ट्रंप प्रशासन द्वारा कनाडाई उत्पादों पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी को देखते हुए ये अपील की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वह चीन के साथ व्यापार समझौता करता है तो वह कनाड़ा पर सौ फीसदी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद एक वीडियो संदेश में कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 'कनाडा की अर्थव्यवस्था पर बाहरी दबाव है। ऐसे में कनाडा के लोगों के पास यही रास्ता है कि वो ही सामान खरीदें, जो कनाडा में बने हों। दूसरे देश क्या करते हैं, हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जो हमारे नियंत्रण में है उसपर फोकस करें। हम ही कनाडा के सबसे अच्छे ग्राहक हैं और हमें कनाडा में बने उत्पाद खरीदने चाहिए ताकि देश को मजबूत बनाया जा सके। अमेरिका और कनाडा दोनों देशों के बीच ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद तल्खी तब और बढ़ गई जब ट्रंप ने कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही, हालांकि पिछले साल कार्नी ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कनाडा बिकाऊ नहीं है। आज जो हालात कनाडा के साथ हैं, वही दुनिया के कई अन्य देशों के साथ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कभी भारत तो धमकी देते हैं तो कभी चीन को। ग्रीनलैंड का समर्थन करने वाले देशों को भी इस तरह की उनकी हाल में धमकी आई है। इस तरह की धमकी एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। बड़ी शक्तियों छोटी शक्ति और देशों को दबाकर रखना चाहती हैं। वे छोटे और सम्प्रभू देशों को अपना गुलाम बनाकर रखना पसंद करती है। अपने पर निर्भर बनाए रखना चाहती है। इस तरह के आसन्न खतरे को भारत ने पहले ही भांप लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी समय से स्वदेशी अपनाने पर वैसे ही नही जोर दे रहे। भारत में स्वदेशी का विचार कोई नया नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विचार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से नया आयाम दिया है। वोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए उन्होंने देशवासियों से भारतीय उत्पादों को अपनाने और उन्हें वैश्विक बनाने का आह्वान किया है। यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान से भी जुड़ा हुआ है। जब हम अपने देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, तो हम न केवल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करते हैं। दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी। उनका हम पर दबाव कम होगा। स्वदेशी की अवधारणा को समझने के लिए हमें महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन को याद करना होगा। गांधीजी ने स्वदेशी को केवल आर्थिक रणनीति के रूप में नहीं देखा था, बल्कि इसे स्वराज और आत्मनिर्भरता के व्यापक दर्शन का हिस्सा माना था। उनका मानना था कि जब तक हम आर्थिक रूप से परतंत्र रहेंगे, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और चरखे से बने खादी को अपनाने पर जोर दिया। गांधीजी के लिए चरखा केवल कपड़ा बनाने का साधन नहीं था, बल्कि यह आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक था। दरअसल अंग्रेजों के शासन से पहले जरूरत का सारा सामान हमारे यहां गांव-गांव और आसपास में पैदा होता हैं। जरूरत का काफी सामान हम अपने घर तैयार कर लेते थे। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बड़े-बड़े उद्योग लगाकर खत्म कर दिया। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का महत्व समझा। उनका स्वदेशी आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हथियार बना। उन्होंने लोगों को समझाया कि जब हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने देश की संपत्ति को बाहर भेज रहे हैं, बल्कि अपने कारीगरों और श्रमिकों को भी बेरोजगार कर रहे हैं। उनका मानना था कि प्रत्येक भारतीय को अपने गांव और अपने देश में बनी वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह विचार इतना प्रभावशाली था कि लाखों भारतीयों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी को अपनाया। यह आंदोलन केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि इसने राष्ट्रीय चेतना को जगाने और लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की वैश्वीकृत दुनिया में स्वदेशी की अवधारणा नए अर्थ और महत्व प्राप्त कर रही है। कनाडा पर ट्रंप की टैरिफ धमकी यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कितना अनिश्चित और राजनीतिक रूप से प्रभावित हो सकता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश पर आर्थिक दबाव बनाना चाहता है, तो व्यापार शुल्क एक प्रमुख हथियार बन जाता है। ऐसी स्थिति में जो देश अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत रखते हैं, वे बेहतर तरीके से इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यही कारण है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से देश में बने उत्पादों को खरीदने का आग्रह किया है। भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल इसी दिशा में एक व्यापक और दूरदर्शी कदम है। इस अभियान का उद्देश्य केवल आयात को कम करना नहीं है, बल्कि भारत को विनिर्माण, नवाचार और तकनीकी विकास का एक वैश्विक केंद्र बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार कहा है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ आत्मकेंद्रित होना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय और मजबूत भागीदार बनना है। जब भारतीय उत्पाद गुणवत्ता और नवाचार में उत्कृष्ट होंगे, तो वे न केवल घरेलू बाजार में सफल होंगे बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बनाएंगे। स्वदेशी को अपनाने का अर्थ यह नहीं है कि हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार या वैश्वीकरण के खिलाफ हैं। बल्कि यह एक संतुलित दृष्टिकोण है जो घरेलू उद्योगों को मजबूत करते हुए वैश्विक बाजार में भागीदारी को भी बढ़ावा देता है। जब हमारे उद्योग मजबूत होंगे, तो हम बेहतर शर्तों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग ले सकेंगे। यही कारण है कि भारत मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से घरेलू उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। स्वदेशी उत्पादों को अपनाने से रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, तो हम अपने देश के कारीगरों, किसानों, छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों की आजीविका का समर्थन करते हैं।

स्वदेशी को सफल बनाने के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। जब हम खरीदारी करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि वह उत्पाद कहां बना है और किसके द्वारा बनाया गया है।

किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय, और सही नक्षत्र का होना जरुरी होता है, आज हम आपको आज के दिन का सही समय जो की सही कार्य करने का है, और आज कब कौन सी दशा कौन से टाइम में चल रही है उसका समुचित विवरण हिन्दू कैलेंडर और हिन्दू पंचांग के अनुसार दे रहे है, आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। आज का दिन शुभ कार्य के लिए सही कार्य है या नहीं आज के चौघड़िया के अनुसार जानें। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, गृह निर्माण कर रहे है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या कोई अन्य शुभ कार्य करने के लिए सोच रहे है तो पहले यहाँ सही समय देख लें, आपका कार्य शुभ और सफल होगा, यही हमारी ओर से शुभ मंगल कामना है।

तिथिः	द्वादशी 11:09 तक
नक्षत्रः	आद्रा 03:27 तक
पक्षः	शुक्ल
वारः	शुक्रवार
योगः	वैधृति, 04:58
सूर्योदयः	07:11
सूर्यास्तः	18:08
चंद्रमाः	मिथुन राशि में
राहुकालः	11:17-12:40
विक्रमी संवत्:	2082
शक सम्वतः	1947
मासः	माघ
शुभ मुहूर्तः	12:18-13:01

जन एक्सप्रेस

रो रहे प्रशंसक !

हुआ बड़ा ये हादसा ।
चली गयी जान ।।
करने थे कई काम अभी ।
हुआ बहुत नुकसान ।।
डूबा गम के सागर में ।
उनका घर परिवार ।।
रो रहे प्रशंसक ।
खो गया आधार ।।
हुई क्षति ये भारी ।
घड़ी है ऐसी आन ।।
हुआ सब अचानक ।
बसा बस निशान ।।
जाना एक दिन सबको ।
पर ऐसे यूं जाना ।।
मृत्यु ने भी लगता ।
ढूंढ़ा बस बहाना ।।

- कृष्णेन्द्र राय

एक्सप्रेस स्वास्थ्य

गैस में अजवाइन का तेल कैसे लगाएं?

आजकल की तेज तर्रार लाइफस्टाइल में गैस की समस्या किसी के लिए भी आम हो गई है। छोटे बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, पेट फूलना, भारीपन, डकार और गैस से जुड़ी परेशानियां हर उम्र में देखने को मिलती हैं। कई बार यह समस्या इतनी बढ़ जाती है कि पूरे दिन की एक्टिविटीज पर असर डालती है। ऐसे में आयुर्वेदिक उपाय हमेशा से ही कारगर और सुरक्षित विकल्प रहे हैं। इनमें से एक पारंपरिक और प्रभावी उपाय है अजवाइन का तेल, जिसे सही तरीके से बनाने और इस्तेमाल करने पर गैस की समस्या से आराम मिलता है।

अजवाइन के औषधीय गुणः अजवाइन में कई औषधीय तत्व पाए जाते हैं, जो पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और गैस बनने की प्रक्रिया को कम करते हैं। आयुर्वेदाचार्य किरण गुप्ता बताती हैं कि अजवाइन का तेल पेट में सूजन और भारीपन को कम करने में मदद करता है। यह पेट के लिए हल्का गर्म असर पैदा करता है, जिससे गैस बाहर निकलती है और पाचन बेहतर होता है। अजवाइन का तेल केवल गैस ही नहीं कम करता, बल्कि पेट की ऐंठन, डकार और भारीपन की समस्या में भी राहत देता है। यह पाचन

क्रिया को बेहतर बनाता है और पेट में मौजूद हानिकारक गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। नियमित इस्तेमाल से कब्ज जैसी समस्या भी कम होती है।

गैस में अजवाइन तेल लगाने का सही तरीकाः आयुर्वेदाचार्य किरण गुप्ता के अनुसार, अजवाइन का तेल पेट पर लगाने का तरीका बहुत जरूरी है। पेट को साफ रखें और अजवाइन का तेल थोड़ा सा हाथ में लेकर पेट के ऊपर गोल-गोल मालिश करें। मालिश 5-10 मिनट तक करें और हल्के हाथ से पेट की मांसपेशियों को दबाएं। मालिश के बाद पेट को गर्म तौलिये या रजाई से ढक दें। गैस की समस्या बच्चों और बुजुर्गों में भी आम है। आयुर्वेदाचार्य किरण गुप्ता कहती हैं कि बच्चों के लिए तेल की मात्रा बहुत कम रखें और हल्के हाथ से मालिश करें। बुजुर्गों में तेल को हल्का गर्म करके ही इस्तेमाल करें ताकि त्वचा पर जलनन हो।

अजवाइन का तेल बनाने का तरीकाः अजवाइन - 2 चम्मच तिल का तेल या सरसों का तेल - 100द्व्य सबसे पहले तिल या सरसों का तेल हल्का गुनगुना करें। इसमें अजवाइन डालकर धीमी आंच पर 1 मिनट तक भूनें। तेल को ठंडा होने दें और फिर किसी कांच की बोतल में रख लें।

निष्कर्षः गैस की समस्या से राहत पाने के लिए अजवाइन का तेल एक सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। आयुर्वेदाचार्य किरण गुप्ता के अनुसार, इसे सही मात्रा में बनाना और सही तरीके से पेट पर मालिश करना बेहद जरूरी है। अजवाइन का तेल न केवल गैस, पेट फूलना और भारीपन को कम करता है, बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। नियमित इस्तेमाल और सही तरीका अपनाकर आप अपने पेट की गैस की समस्या को घर बैठे आसानी से कम कर सकते हैं।

एक्सप्रेस विशेष

भेदभाव की दीवारें गिराने चले, भरोसे की नींव ही हिला दी

प्रो. आरके जैन

समानता का अर्थ यह नहीं कि एक वर्ग की सुरक्षा के नाम पर दूसरे को भय और असुरक्षा में डाल दिया जाए। उच्च शिक्षा में समावेशिता निस्संदेह आवश्यक है, लेकिन वह संतुलन, पारदर्शिता और पारस्परिक विश्वास के बिना संभव नहीं।

भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर ऐसे संवेदनशील चौराहे पर खड़ी है, जहाँ 'समानता ', 'न्याय' और 'सुरक्षा' जैसे शब्दों के अर्थ को लेकर गहरी बहस छिड़ गई है। 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन विनियम को आधिकारिक रूप से जाति आधारित भेदभाव समाप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया गया। आयोग का तर्क है कि पिछले पाँच वर्षों में जातिगत शिकायतों में 118.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और रोहित वेमुला तथा पायल तड़वी जैसे मामलों ने संस्थानों की संवेदनहीनता को उजागर किया है। इसी आधार पर हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में समान अवसर केंद्र, समानता समिति, 24 घंटे की हेल्पलाइन और संस्थान प्रमुखों की सीधी जवाबदेही जैसे कड़े प्रावधान किए गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था वास्तव में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करेगी, या फिर समानता के नाम पर एक नई असमानता को जन्म देगी। नए नियमों की मूल संरचना ही सबसे बड़ा विवाद बन गई है। जातिगत भेदभाव की परिभाषा लगभग पूरी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित कर दी गई है। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि सामान्य वर्ग के छात्र या शिक्षक यदि किसी प्रकार के भेदभाव का सामना करें, तो उनके लिए कोई स्पष्ट और समान तंत्र मौजूद नहीं है। पुराने 2012 के नियमों में झूठी शिकायतों पर दंड का प्रावधान था, जिसे नए नियमों में हटा दिया गया है, जिससे जांच प्रक्रिया में संतुलन बना रहता था। नए नियमों में इस प्रावधान को हटाना कई लोगों को चिंतित कर रहा है। आलोचकों का कहना है कि इससे शिकायतें न्याय का साधन कम और दबाव का हथियार अधिक बन सकती हैं। समानता समिति में सामान्य वर्ग का अनिवार्य प्रतिनिधित्व न होना भी निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। यही कारण है कि कई लोग इसे संविधान में निहित समानता और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध मान रहे हैं। यह असंतोष अब केवल अकादमिक बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक भूचाल में बदल गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और पदाधिकारियों ने खुलकर विरोध दर्ज कराया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, जिसमें उन्होंने यूजीसी नियमों को 'ब्लैक लॉ' करार देते हुए सामान्य वर्ग को असुरक्षित बताया और शंकराचार्य के साथ कथित दुर्व्यवहार का भी जिक्र किया; इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी। लखनऊ में युवा मोर्चा और किसान मोर्चा के अनेक नेताओं सहित कई बीजेपी पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा देकर पार्टी नेतृत्व को चेतावनी दी और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई। सामाजिक माध्यमों पर प्रसिद्ध हस्तियों की टिप्पणियों ने भावनात्मक स्वर को और तीखा कर दिया। आलोचकों का आरोप है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को नियमों में प्रमुखता देकर राजनीतिक लाभ साधने का प्रयास किया गया, जबकि सामान्य वर्ग को हाशिए पर धकेला जा रहा है। राजनीतिक हलचल के समानांतर, देशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया है। दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय के बाहर सामान्य वर्ग के छात्रों का धरना यह स्पष्ट संकेत देता है कि विरोध भेदभाव रोकने के उद्देश्य के खिलाफ नहीं, बल्कि एकतरफा व्यवस्था के खिलाफ है। 'कैंपस में अराजकता नहीं, समानता चाहिए' जैसे नारे छात्रों की मानसिक पीड़ा को उजागर करते हैं। अखिल एबीवीपी (बीजेपी से जुड़ा) और एनएसयूआई (कांग्रेस से जुड़ा) जैसे वैचारिक रूप से अलग संगठन भी इस मुद्दे पर एक मंच पर दिखाई दिए, जो अपने आप में असाधारण है। कई छात्र संघों ने औपचारिक पत्र लिखकर नियमों को वापस लेने या संशोधित करने की माँग की है। छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि अनुपालन का अत्यधिक दबाव संस्थानों को रक्षात्मक बना देगा।

उनकी माँग है कि झूठी शिकायतों पर सख्त दंड का प्रावधान जोड़ा जाए, भेदभाव की परिभाषा सभी वर्गों के लिए समान हो और समानता समिति में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाए। आयोग का कहना है कि बढ़ती शिकायतों ने कठोर कदम आवश्यक बना दिए थे, लेकिन विरोधी मानते हैं कि आँकड़ों के पीछे के कारणों की गहन जाँच के बिना बनाए गए नियम समस्या को सुलझाने के बजाय बढ़ा सकते हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशकः अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा ए0वी0बी0 रेप्रोग्राफिक्स, ए-59, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ताल कटोरा, लखनऊ से मुद्रित तथा अय्यूब कॉम्प्लेक्स, 82/68, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ पिन-226004, उ0प्र0 से प्रकाशित। संपादकः अरुण कुमार त्रिपाठी, (प्रबन्ध संपादक- मनोज तिवारी, सह-संपादकः इमरान खान, राज्य ब्यूरो प्रमुख- सन्तोष कुमार दीक्षित) आर.एन.आई. पंजीयन संख्या : UPHIN/2009/30003, फोन नं.: 0522-4330955 मोबाइल नं. 8933805555, (नोटः सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ स्थित न्यायालय होगा।)

ओवरस्पीडिंग व नशे में वाहन चलाना दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण: वीरेंद्र सिंह (एआरटीओ)

सड़क सुरक्षा माह- ग्राम पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान
ललौरीखेड़ा, मरौरी व अमरिया ब्लॉक में हुई सड़क सुरक्षा संगोष्ठियां

जन एक्सप्रेस। पीलीभीत

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को ग्राम पंचायत स्तर तक विस्तार दिया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिले के सभी आठ विकासखंडों में ग्राम प्रधानों, पंचायत सदस्यों एवं पंचायत सचिवों के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को ललौरीखेड़ा, मरौरी एवं अमरिया विकासखंड में एक-एक सड़क सुरक्षा संगोष्ठी आयोजित की गई। इन कार्यक्रमों में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया।संगोष्ठियों में प्रतिभाग करते हुए एआरटीओ वीरेंद्र सिंह एवं यात्रीकर अधिकारी बर्डिस चतुर्वेदी ने बताया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं ओवरस्पीडिंग, लापरवाही से ओवरटेकिंग, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, नशे की हालत में वाहन चलाने तथा हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग न करने के कारण हो रही हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने-अपने गांवों में सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठकें आयोजित कर ग्रामीणों को जागरूक करें।अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि किसी ग्राम क्षेत्र में दुर्घटनाएं बार-बार हो रही हैं तो ऐसे स्थानों को चिन्हित कर प्रशासन को सूचित किया जाए, ताकि वहां आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

कैशलेस इलाज, हिट एंड रन योजना व राहवीर पुरस्कार की जानकारी संगोष्ठियों में सड़क दुर्घटनाओं के घायलों के लिए लागू कैशलेस उपचार योजना, अज्ञात वाहन से टक्कर में घायल अथवा मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने वाली हिट एंड रन सोलैशियम योजना तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले नेक व्यक्तियों को 'राहवीर' मानते हुए 25 हजार रुपये तक की पुरस्कार राशि दिए जाने की जानकारी भी दी गई।

ललौरीखेड़ा ब्लॉक में आयोजित संगोष्ठी के दौरान ब्लॉक प्रमुख अजय गंगवार भी उपस्थित रहे। उन्होंने सड़क सुरक्षा को लेकर अपने सुझाव साझा किए और पंचायत प्रतिनिधियों से इन पर प्रभावी अमल करने का आह्वान किया।

बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता

ललौरीखेड़ा विकासखंड में 63, मरौरी में 54 तथा अमरिया विकासखंड में 58 ग्राम प्रधानों, पंचायत सदस्यों एवं पंचायत सचिवों ने संगोष्ठियों में सहभागिता की। तीनों विकासखंडों में आयोजित इन कार्यक्रमों में खंड विकास अधिकारी एवं सहायक पंचायत अधिकारी भी मौजूद रहे।

जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण, कई विभागों में कर्मचारी मिले अनुपस्थित

- अनुपस्थित कर्मियों का वेतन काटने व स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश
- तीन दिन में आख्या तलब, नो वर्क-नो पे के आधार पर होगी कार्रवाई

जन एक्सप्रेस। पीलीभीत

जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह ने गुरुवार सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर कलेक्ट्रेट स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर उपस्थिति रजिस्टर पंजिकाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ कोषाधिकारी कार्यालय, खाद्य विभाग, जिला पूर्ति कार्यालय, संयुक्त कार्यालय एवं नजारत कार्यालय में कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।

वरिष्ठ कोषाधिकारी कार्यालय की उपस्थिति पंजिका की जांच में राजेन्द्र कुमार, अंकुर अग्रवाल, आशुतोष मिश्रा, जितेन्द्र कुमार, अरविन्द कुमार (सभी लेखाकार), ठाकुर सिंह (सहायक लेखाकार) एवं हरिमोहन (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने वरिष्ठ कोषाधिकारी को निर्देश दिए कि अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन नो वर्क-नो पे के आधार पर काटा जाए तथा की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

खाद्य विभाग में तीन अधिकारी अनुपस्थित

प्रभारी अधिकारी (खाद्य) कार्यालय की जांच के दौरान नेहा वैश (डीआई), शान्तनु कुमार एवं सतीश कुमार (एफएसओ) अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने प्रभारी अधिकारी (खाद्य) को निर्देश दिए कि सभी अनुपस्थित कर्मियों को स्पष्टीकरण जारी कर तीन दिन के भीतर आख्या उपलब्ध कराई जाए।

जिला पूर्ति कार्यालय में भी लापरवाही

जिला पूर्ति कार्यालय की उपस्थिति पंजिका की जांच में मुकेशो कुमारी (कनिष्ठ सहायक) अनुपस्थित पाई गईं। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को स्पष्टीकरण जारी कर तीन दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

संयुक्त कार्यालय में बड़ी संख्या में कर्मचारी गैरहाजिर

प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय की जांच के दौरान कैलाश चन्द्र राठौर, मेराज अहमद, संजीव कुमार सक्सेना, छेदालाल, हेमा गुप्ता, एकता उर्फ पुष्पा देवी, अनीता वर्मा, शशीवाला, विपिन कुमार पाण्डेय, कान्ता प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, निखिल कुमार एवं राकेश कुमार अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय को सभी से स्पष्टीकरण जारी कर तीन दिवस में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

नजारत कार्यालय में भी कई कर्मचारी अनुपस्थित

नजारत कार्यालय की उपस्थिति पंजिका के निरीक्षण में वीरेन्द्र कुमार, विजय कुमार, प्रेम प्रकाश, विजय पाल, हरीश कुमार एवं गोकरनलाल अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने प्रभारी अधिकारी नजारत को निर्देशित किया कि संबंधित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेकर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासकीय कार्यों में लापरवाही व अनुशासनहीनता किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे।

बरखेड़ा में रफ्तार का कहर- बाइक सवार परिवार को रौंदा

- महिला को कुचलकर भागा कार चालक, सीसीटीवी में कैद हुई हैवानियत, दंपती व दो मासूम गंभीर, इलाके में उबाल

जन एक्सप्रेस। पीलीभीत

बरखेड़ा कस्बे में बुधवार रात घटित सड़क हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं पर करारा तमाचा है। ब्लॉक तिराहे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपती और उनके दो मासूम बच्चों को कुचल दिया। इससे भी अधिक शर्मनाक यह रहा कि टक्कर के बाद कार चालक ने इंसानियत दिखाने के बजाय सड़क पर गिरी महिला को दोबारा कुचलते हुए फरार होकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। जानकारी के अनुसार, बुधवार रात करीब 10 बजे बरखेड़ा निवासी जमील अपनी पत्नी महनाज बी और दो बेटियों नौ वर्षीय शाहिदा तथा एक वर्षीय शाबिया के साथ बाइक से ब्लॉक तिराहा पार कर रहे थे। इसी दौरान पीलीभीत की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महनाज अपनी गोद में मासूम बच्ची को लिए करीब पांच फीट दूर जा गिरी।

हादसे में दंपती और दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने जब कार चालक को पकड़ने का प्रयास किया, तो आरोपी ने बच निकलने के लिए सड़क पर तड़प रही महनाज के ऊपर से कार चढ़ा दी। इस निर्ममता में महिला के दोनों पैर बुरी तरह कुचल गए। इसके बाद चालक कार लेकर बीसलपुर की ओर फरार हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और बेलगाम रफ्तार व पुलिस की निष्क्रिय गश्त पर सवाल खड़े होने लगे। घायलों को पहले सीएचसी बरखेड़ा ले जाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन परिजन गंभीर हालत को देखते हुए सभी को बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज करा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे ने तब और झकझोर दिया, जब सामने आया कि पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। फुटेज में कार चालक की क्रूरता और लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। इसके बावजूद आरोपी का फरार होना कानून व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। यह घटना न सिर्फ सड़क सुरक्षा की पोल खोलती है, बल्कि यह भी बताती है कि तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्ती अब केवल कागजों तक सीमित है। स्थानीय लोगों ने आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी, कार की जब्ती और कठोर कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह है कि क्या इस हैवानियत के बाद भी प्रशासन नींद में रहेगा, या फिर कोई ठोस संदेश समाज को दिया जाएगा?

जंगल का रोमांच और जिम्मेदारी

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भालू और बाघों का आमना-सामना

जन एक्सप्रेस। मुकेश कुमार

पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जंगल सफारी के दौरान बृहस्पतिवार को जो दृश्य सैलानियों ने देखा, वह रोमांच से भरपूर होने के साथ-साथ कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। सफारी मार्ग पर भालू का पीछा करते तीन बाघों का दिखाई देना जहां रोमांचक अनुभव रहा, वहीं यह घटना जंगल के बदलते संतुलन और मानवीय दखल की सीमाओं को भी रेखांकित करती है। पीटीआर में बाघों की संख्या बढ़ना निस्संदेह संरक्षण प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। लेकिन जब बाघ, भालू जैसे वन्यजीव सफारी मार्ग पर आमने-सामने आते हैं, तो यह केवल रोमांच का दृश्य नहीं रह जाता, बल्कि यह संकेत देता है कि जंगल के भीतर जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। सैलानियों द्वारा मोबाइल कैमरों में कैद यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होना आज के डिजिटल दौर की सच्चाई है। ऐसे दृश्य पर्यटकों को आकर्षित जरूर करते हैं, लेकिन यह भी आवश्यक है कि रोमांच की तलाश में जंगल की मर्यादा न टूटे। वन्यजीवों की गतिविधियां किसी मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि प्राकृतिक जीवन चक्र का हिस्सा हैं।

वन विभाग द्वारा सतर्कता बढ़ाना और सफारी मार्गों पर निगरानी मजबूत करना सराहनीय कदम है। डीएफओ मनीष सिंह का यह कहना कि सैलानियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, विभागीय जिम्मेदारी को दर्शाता है। हालांकि, केवल गश्त बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। सफारी मार्गों का वैज्ञानिक मूल्यांकन, वन्यजीवों के मूवमेंट का अध्ययन और संवेदनशील क्षेत्रों में अस्थायी प्रतिबंध जैसे कदम भी समय-समय पर जरूरी हो जाते हैं।

यह घटना हमें याद दिलाती है कि जंगल केवल देखने की चीज नहीं, बल्कि समझने और सम्मान करने की जगह है। पर्यटन और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। यदि यह संतुलन बिगड़ा, तो न रोमांच सुरक्षित रहेगा और न ही वन्यजीव। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की यह घटना रोमांचक जरूर है, लेकिन इससे बड़ा संदेश यह है कि प्रकृति के साथ सहअस्तित्व तभी संभव है, जब मानव अपनी सीमाएं पहचाने और जंगल को उसके नियमों के साथ स्वीकार करे।

योग से स्वस्थ नगर की परिकल्पना

योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और रोगमुक्त रखने की एक संपूर्ण जीवन पद्धति- संजय अग्रवाल
नगर पालिका की पहल से हर वार्ड में निःशुल्क योग केंद्रों की तैयारी

जन एक्सप्रेस। पीलीभीत

बदलती जीवनशैली और बढ़ती बीमारियों के बीच यदि कोई पहल समाज को भीतर से सशक्त बना सकती है, तो वह है योग। नगर पालिका परिषद, पीलीभीत द्वारा नगर के सभी वार्डों में निःशुल्क योग केंद्रों की स्थापना को लेकर आयोजित बैठक इसी दिशा में एक दूरदर्शी और सराहनीय प्रयास के रूप में सामने आई है। यह पहल केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक समाज की नींव रखने का प्रयास है। बैठक के दौरान योग एवं स्वस्थ जीवनशैली को जन-जन तक पहुँचाने पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। इसी क्रम में सी.ए. संजय अग्रवाल ने भारतीय योग संस्थान, पीलीभीत की ओर से नगर पालिका चेयरमैन डॉ. आस्था अग्रवाल को संस्थान की त्रैमासिक पत्रिका योग मंजरी के आहार विशेषांक की प्रति भेंट कर योग, पोषण और संतुलित जीवन के महत्व को रेखांकित किया। सी.ए. संजय अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और रोगमुक्त रखने की एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। भारतीय योग संस्थान वर्षों से योग, प्राणायाम और संतुलित आहार के माध्यम से जनस्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहा है। योग मंजरी का आहार विशेषांक आमजन को सरल भाषा में यह समझाने का प्रयास है कि स्वस्थ शरीर के लिए सही खानपान और योग कितना आवश्यक है। यह स्वस्थ समाज की दिशा में एक सार्थक कदम है। नगर पालिका चेयरमैन डॉ. आस्था अग्रवाल ने इस पहल की खुले मन से सराहना करते हुए कहा कि नगर के प्रत्येक वार्ड में निःशुल्क योग केंद्रों की स्थापना से बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को नियमित योगाभ्यास का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज की शहरी जीवनशैली में तनाव, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियाँ आम होती जा रही हैं, जिन पर योग के माध्यम से प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

डॉ. आस्था अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि नगर पालिका जनहित से जुड़े ऐसे प्रयासों में भारतीय योग संस्थान को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उनका मानना है कि यदि नागरिक स्वस्थ होंगे तो नगर स्वतः ही प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर, यह पहल केवल योग केंद्र खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जागरूक, स्वस्थ और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण की दिशा में मजबूत संदेश देती है। अब आवश्यकता है कि इस सोच को धरातल पर उतारते हुए हर वार्ड में योग को जनआंदोलन बनाया जाए।

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक का जिला कारागार में औचक निरीक्षण

- बंदियों से की बातचीत, समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश
- स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही पर सख्ती, मानक के अनुरूप व्यवस्थाएं देने के आदेश

जन एक्सप्रेस। पीलीभीत

जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने गुरुवार को जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने किशोर बैरक सहित अन्य बैरकों एवं जेल अस्पताल का गहन अवलोकन किया। जेल अस्पताल के निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने बीमार बंदियों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उपस्थित चिकित्सक को सख्त निर्देश दिए गए कि बीमार बंदियों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और उन्हें समय पर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बैरकों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बंदियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बंदियों से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि बंदियों को शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही कारागार परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया और इसे नियमित बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक, जेलर सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

धनाराघाट मार्ग पर दूसरे दिन भी आवागमन बाधित

जन एक्सप्रेस। पूरनपुर

तहसील क्षेत्र के धनाराघाट मार्ग पर लगातार बारिश के चलते दूसरे दिन भी आवागमन बाधित रहा। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे और कीचड़ फैलने से वाहनों के फंसने का खतरा बना हुआ है। इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों, स्कूली बच्चों, किसानों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पेंटून पुल पर तैनात मुंशी बबलू मांझी ने गुरुवार दोपहर 12 बजे से इस मार्ग पर न आने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जब तक पानी की निकासी नहीं होती और सड़क की मरम्मत नहीं की जाती, तब तक इस मार्ग से गुजरना जोखिम भरा है। लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है।

टीवी देखने को लेकर भाइयों में विवाद, युवक ने पी लिया जहरीला पदार्थ

- पिता के समझाने पर भी नहीं माना बड़ा भाई, हालत गंभीर
- जिला अस्पताल में चल रहा उपचार, पुलिस को दी गई सूचना

जन एक्सप्रेस। पीलीभीत

न्यूरिया थाना क्षेत्र के भरतपुर कॉलोनी में टीवी देखने को लेकर शुरू हुआ मामूली पारिवारिक विवाद उस समय गंभीर घटना में बदल गया, जब गुस्से में आए एक युवक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। घटना से परिवार में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार भरतपुर कॉलोनी निवासी देवदास बैरागी का छोटा पुत्र अनूप बैरागी घर में टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल देख रहा था। इसी दौरान उसका बड़ा भाई शिवम बैरागी वहां पहुंचा और टीवी पर मूवी लगाने की बात कही। इस पर छोटे भाई ने आपत्ति जताई, जिससे दोनों भाइयों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। पिता के समझाने पर भी नहीं हुआ शांत विवाद बढ़ता देख परिजनों ने दोनों भाइयों को समझाने का प्रयास किया। पिता देवदास बैरागी ने बड़े पुत्र शिवम को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक नाराज हो गया। गुस्से में शिवम घर के दूसरे कमरे में चला गया, जहां उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कुछ ही देर बाद शिवम की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में युवक का उपचार जारी है। पुलिस कर रही मामले की जांच घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। युवक द्वारा विषाक्त पदार्थ सेवन के कारणों की जांच की जा रही है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है।

युवती की मौत, पेड़ से लटका मिला शव संदिग्ध हालात में मिली लाश

जन एक्सप्रेस। पूरनपुर

थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के ग्राम हीरपुर में गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब गांव के बाहर एक पेड़ से युवती का शव लटका हुआ मिला। सूचना मिलते ही ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।मृतका की उम्र करीब 19 से 20 वर्ष बताई जा रही है। वह चार भाई-बहनों में सबसे छोटी थी, जबकि बड़ी बहन का विवाह पहले हो चुका है। जिस स्थान और ऊंचाई पर शव लटका मिला, उसे देखकर ग्रामीणों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों का कहना है कि युवती का स्वयं वहां तक पहुंचना आसान प्रतीत नहीं होता।घटना के बाद गांव में शोक व भय का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मौके से जुड़े फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। मोबाइल फोन सहित अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से पूर्व प्रधान पति की मौत

जन एक्सप्रेस। पीलीभीत

बीसलपुर-बिलसंडा मार्ग पर गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पूर्व प्रधान के पति की जान चली गई। अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है।कोतवाली देवरिया कलां क्षेत्र के ग्राम सनगवां निवासी बृजपाल उर्फ छोटे (55), पुत्र माखनलाल, गुरुवार को किसी निजी कार्य से बीसलपुर आए थे। कार्य निपटाकर वह स्कूटी से गांव लौट रहे थे। जैसे ही वह बीसलपुर-बिलसंडा मार्ग स्थित आरबीएल इंटर कॉलेज के सामने पहुंचे, तभी पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बृजपाल सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल, चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल एंबुलेंस की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार शुक्ला पुलिस बल के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों के पहुंचने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया।

अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस

दुर्घटना को अंजाम देने वाला वाहन मौके से फरार हो गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। वहीं अचानक हुए इस हादसे से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

यूजीसी एक्ट के विरोध में प्रदर्शन सवर्ण समाज ने सौंपा ज्ञापन

जन एक्सप्रेस। पूरनपुर

यूजीसी एक्ट के विरोध में गुरुवार को सवर्ण समाज ने गांधी पार्क से जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को काला कानून बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी एक्ट शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन के खिलाफ है।

यह कानून समाज के एक बड़े वर्ग के अधिकारों का हनन करता है। चेतावनी दी गई कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गांधी पार्क से तहसील परिसर तक निकाले गए प्रदर्शन में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए।

वक्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बताते हुए 2027 के चुनाव को लेकर भी चेतावनी दी। सभा को संबोधित करते हुए प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि यूजीसी एक्ट किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इस दौरान अश्वनी शुक्ला, गौरव पांडे, रवि मिश्रा, मयंक सक्सेना, संजय मिश्रा, अनुभव पांडे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

अधिवक्ता के पति की कार से खींचकर बेरहमी से पिटाई, इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती

जन एक्सप्रेस । हरदोई

हरदोई के कछौना थाना क्षेत्र में प्रधान प्रतिनिधि के इशारे पर उसके घर वालों ने अधिवक्ता के पति को कार से खींच कर बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी जिससे उसकी आवाज़ चली गई। साथ ही बचाने पहुंचे कई लोगों के सिर फोड़ दिए, जिन्हे इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पिटाई के दौरान बनाया गया वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो गया है,जिसमें की जा रही पिटाई देख कर अच्छे-अच्छों के होश उड़ गए। पुलिस ने अधिवक्ता की तहरीर पर प्रधान प्रतिनिधि,उसके प्रधान भाई के अलावा 10 नामज़द और 50-60 अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है।

बताया जा रहा है कि कछौना थाना क्षेत्र के तकिया गांव निवासी अधिवक्ता फिरदौस जहां कछौना में गौसगंज रोड पर इस्लाम नगर में नया मकान बना कर रह रहीं हैं।उन्होंने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि रविवार को तकिया गांव निवासी वहाब पुत्र सुल्तान और रफीक पुत्र गफूरे के बीच झगड़ा हुआ था, शाम को उनके पति सलीम उसी मामले में तहरीर ले कर कोतवाली जा रहे थे। रास्तें में प्रधान प्रतिनिधि नसीम पुत्र नन्हे बाबा ने रोका और उसके प्रधान भाई मुख्तार, शरीफ, इरशाद, पुत्र अमीर, जमाल पुत्र हसनैन, शकील पुत्र पुत्तन, अकील पुत्र पुत्तन, इरफान पुत्र शरीफ, इकबाल पुत्र शरीफ, रफीक पुत्र गफूरे व सुफील पुत्र रफीक ने अपने 50-60 अज्ञात साथियों के पति सलीम को कार से बाहर खींचते हुए लाठी-डंडों से बुरी तरह से पीटने लगे, बचाने पहुंचे अली जान, जान मोहम्मद, शान, वहीद, मोहम्मद जान और साहिल का हमला कर सिर फोड़ दिया।इतना ही नहीं अधिवक्ता फिरदौस जहां के साथ बदसुलूकी करते हुए प्राइवेट पार्ट पर चोंट पहुंचाई। तहरीर में आगे कहा गया है कि हमलावर 20 हज़ार रुपये और सोने की चैन भी लूट ले गए। हमलें के शिकार हुए सभी को लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है,अधिवक्ता का कहना है कि उनके पति सलीम की आवाज़ चली गई।

हमलावरो की हमदर्द बन सामने आई कछौना पुलिस

कछौना पुलिस पूरी तरह से अधिवक्ता फिरदौस जहां और उनके पति सलीम के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले हमलावरों की हमदर्द ही नहीं साबित हुई बल्कि पुलिस अफसरों ने भी उसकी इस हरकत को पकड़ लिया। अधिवक्ता फिरदौस जहां अपने पति को उठा कर लखनऊ ट्रामा सेंटर पहुंची और इधर पुलिस ने पेश बंदी करते हुए प्रधान प्रतिनिधि द्वारा दी गयी तहरीर पर जांच के बिना अधिवक्ता,उनके पति समेत कई लोगों पर केस दर्ज कर लिया।

बिना जांच पीड़ित पक्ष के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करने पर कोतवाल निलम्बित

जन एक्सप्रेस । हरदोई

पीड़ित की मदद के बजाय उल्टा उसी पर केस दर्ज करने वाले प्रभारी निरीक्षक कछौना को एसपी ने निलंबित कर दिया है।आरोप है कि उनके द्वारा थाना कछौना क्षेत्र से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मारपीट संबधी खबर की सत्यता से जांच न करते हुए विपक्षी की तरफ से आवेदिका पक्ष के विरुद्ध फर्जी अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्रकरण की सत्यता ज्ञात होने के उपरांत भी आवेदिका पक्ष की तरफ से अभियोग पंजीकृत न कर अपने कर्तव्य व दायित्वों के प्रति लापरवाही बरती गई। इस संबंध में एसपी द्वारा कछौना के प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच आसन्न की गई है।

कछौना देहात गांव की है,जहां महिला

अधिवक्ता फिरदौस जहां ने ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी।आरटीआई से 13 लाख 57 हजार रुपये के गबन का खुलासा हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने ग्राम प्रधान के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए। इसी कार्रवाई से बौखलाए प्रधान ने कथित तौर पर कानून हाथ में ले लिया और शिकायतकर्ता के पति को कार से खींचकर दबंग ग्राम प्रधान नसीम अपने साथियों के साथ महिला अधिवक्ता के पति सलीम को सरेआम कार से खींचकर बेरहमी से पीटा। लाठी-डंडों से किए गए इस हमले में पूरा परिवार निशाने पर रहा और आठ लोग घायल हो गए।

दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों में कोहराम

जन एक्सप्रेस । शाहाबाद

शाहाबाद कोतवाली के शाहजहांपुर हाईवे पर नवीन मंडी स्थल के निकट बुधवार की रात नौ बजे खाना खाकर टहलने निकले युवक के तेज रफ्तार फोर व्हीलर ने टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गिलजई निवासी मोहम्मद जैद 34 वर्ष पुत्र मुख्तार अली खां अपने मित्र अलीम के साथ बुधवार की रात 9ः00 खाना खाकर टहलने के लिए निकले थे। शाहजहांपुर हाईवे पर नवीन मंडी स्थल के निकट पीछे से आ रहे की तेज रफ्तार फोर व्हीलर ने उनके टक्कर मार दी जिससे वह घायल हो गए। घायल अवस्था में तत्काल सीएचसी ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक विवाहित था उसके दो बेटियां हैं। एक बेटी 8 वर्ष और दूसरी 6 वर्ष है । मृतक पांच भाइयों में सबसे छोटा था। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने किशोर को कुचला, दर्दनाक मौत

जन एक्सप्रेस । शाहाबाद

शाहाबाद कोतवाली के दौलतपुर गंगादास निवासी एक 17 वर्षीय किशोर को तेज रफ्तार गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्राली ने कुचल दिया जिससे उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ट्रैक्टर ट्राली को चालक सहित हिरासत में लिया गया है। शाहाबाद कोतवाली के दौलतपुर गंगा दास निवासी बाबूराम का 17 वर्षीय पुत्र श्यामू बच्चों के साथ सड़क पर खेल रहा था। दोपहर करीब 12ः30 बजे करीमनगर से गन्ना लाद कर ले जा रहे एक ट्रैक्टर ट्राली ने मलकापुर और दौलतपुर गंगा दास के बीच में किशोर को कुचल दिया जिससे किशोर की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। ट्रैक्टर चालक बबलू पुत्र रियासत निवासी ग्राम एगमा को दौड़ाकर पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। मृत अवस्था में किशोर को लेकर परिजन और ग्रामीण कोतवाली पहुंचे जहां पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई । पुलिस ने जैसे तैसे समझा कर परिजनों को सीएचसी भिजवाया। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया तहरीर के आधार पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जिला कारागार के औचक निरीक्षण में परखी गई सुरक्षा व्यवस्था

बैरकों में नहीं मिली कोई आपत्तिजनक वस्तु, प्रतिदिन निरीक्षण के निर्देश

जन एक्सप्रेस । उरई

जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने जिला कारागार का सघन औचक निरीक्षण कर सम्बंधित अधिकरियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कारागार की समस्त बैरकों की गहन तलाशी ली गई। जिसमें किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक अथवा प्रतिबंधित सामग्री नहीं पाई गई। डीएम ने जेल अधीक्षक को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि बैरकों की प्रतिदिन अनिवार्य रूप से गहन जांच कराई जाए तथा प्रत्येक निरीक्षण का अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु पाए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान बंदियों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, रसोईघर की स्वच्छता एवं आपूर्ति व्यवस्था की भी सघन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि भोजन शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो तथा गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कारागार प्रशासन में अनुशासन, सुरक्षा एवं पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी स्तर की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को चौकसी बढ़ाने, नियमित सघन चेकिंग करने एवं कारागार परिसर में अनुशासन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कारागार की सुरक्षा से में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक नीरज देव सहित कारागार के समस्त संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

दबंगो ने युवक को गोली मारकर किया घायल,पीड़ित लखनऊ रेफर

जन एक्सप्रेस । माधौगंज

थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को दबंगो ने गोली मारकर घायल कर दिया।घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल पहुंचकर घटना का जायजा लिया तथा घायल को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया।जहां से नाजुक हालत को देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार माधौगंज थाना क्षेत्र की कुरसठ चौकी के अटवा अली मर्दानपुर गांव निवासी लगभग 40 वर्षीय सुखवासी पुत्र संतू बुधवार शाम करीब साढ़े आठ सड़क से गांव जा रहा था। तभी लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के पास अचानक कुछ लोगों ने उसे घेरकर मारना पीटना शुरू कर दिया।सुखबासी द्वारा मारपीट का विरोध करने पर दबंगो ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। जहां नाजुक हालत के चलते लखनऊ रेफर कर दिया गया। परिवार के लोग खेत में चने उखाड़ने को लेकर रंजिश बता रहे हैं। दोनों पक्षों में दो साल पूर्व मारपीट का मुकदमा लिखा गया था।मौके पर पहुंचे सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश सिंह ने घटना का जायजा लिया वहीं परिवार को न्याय का भरोसा दिया।थानाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जाच की जा रही है।

निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत, अस्पताल संचालक सहित स्टाफ फरार

जन एक्सप्रेस । शाहाबाद

शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत हो गई । घबराया अस्पताल संचालक और पूरा स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। परिजनों और मोहल्ला वासियों द्वारा संचालक डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा काटा गया। अस्पताल पहुंची कोतवाली पुलिस ने समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने आरोपी डाक्टर के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। राजीव कुमार पुत्र सन्त राम निवासी मोहल्ला सुलेमानी कस्बा शाहाबाद के अनुसार वह 28 जनवरी को सुबह 10 बजे अपनी पत्नी रुचि उम्र 28 वर्ष को लेकर आल्ट्रासाउण्ड कराने राजपूत होस्पटिल आया था। यहाँ उपस्थित डाक्टर मनोज वर्मा ने आल्ट्रासाउण्ड करने के उपरान्त कहा कि इसका आपरेशन करना पड़ेगा। उसने ऑपरेशन के लिए 25 हजार रुपये जमा कर दिये। डाक्टर मनोज ने उसकी पत्नी का ओटी में ले जा कर आपरेशन कर दिया जिससे उसका लड़का पैदा हुआ। इसके बाद आरोपी डाक्टर पुनः पत्नी को ओटी में ले गये और अन्दर से दरवाजा बन्द कर पता नहीं क्या किया जिस कारण उसकी पत्नी की मौत आपरेशन थिएटर में हो गयी। आरोप है कि डाक्टर मनोज वर्मा द्वारा खुद आपरेशन किये जाने के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गयी है। डाक्टर मनोज वर्मा की जान बूझकर घोर लापरवाही, बिना समुचित योग्यता के कारण उसकी पत्नी की मौत हो गई। प्रसूता की मौत होने के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटना शुरु कर दिया मोहल्ले से भी भारी संख्या में भीड़ जुटने लगी। इस दौरान अस्पताल संचालक डॉक्टर मनोज वर्मा और पूरा स्टाफ फरार हो गया। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण और प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने समझा बुझाकर मामला शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक राज नारायण ने बताया कि निजी अस्पताल में प्रसूता कि इलाज के दौरान मौत के मामले में मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी डाक्टर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।

वैश्विक स्तर पर पहली बार, एयरटेल ने 36 करोड़ भारतीयों को एडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम निःशुल्क उपलब्ध कराया

आगरा। भारत की अग्रणी टेलीकम्युनिकेशन सेवा प्रदाताओं में से एक भारती एयरटेल अब अपने 36 करोड़ ग्राहकों को एडोबी एक्सप्रेस की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करा रही है। एडोबी एक्सप्रेस एक तेज़, आसान और हर तरह की डिज़ाइन जरूरतों को पूरा करने वाला एप है, जिसे अब पूरे भारत में एयरटेल के ग्राहक इस्तेमाल कर सकेंगे।

यह ऐतिहासिक और अपनी तरह की पहली साझेदारी एयरटेल के सभी ग्राहकों को एडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे वे हाई क्वालिटी वाली सोशल मीडिया एसेट्स, मार्केटिंग कंटेंट, शॉर्ट वीडियो और किसी भी प्रकार के डिज़ाइन को तेज़ी से और सहज तरीके से तैयार कर सकेंगे। लगभग रु 4,000 मूल्य वाला एडोबी एक्सप्रेस प्रीमियम अब एक वर्ष के लिए निशुल्क उपलब्ध होगा। इसके साथ एयरटेल के सभी ग्राहक अपनी रचनात्मक क्षमताओं को खुलकर अभिव्यक्त कर सकेंगे और पेशेवर स्तर का कंटेंट तैयार कर सकेंगे, चाहे उनका डिजाइनिंग का अनुभव किसी भी स्तर का हो।

प्रदेश सरकार में सशक्त हो रहा होमगाड्र्स विभाग, जालौन में नए भवन का शुभारम्भ

जन एक्सप्रेस । उरई

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) होमगाड्र्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्य अतिथि धर्मवीर प्रजापति, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, डीएम राजेश कुमार पाण्डेय, एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार, डिविजनल कमांडेंट होमगाड्र्स झांसी रवि शंकर त्रिवेदी, होमगार्ड कमांडेंट राजेश सिंह ने जालौन के जिला कमाण्डेन्ट होमगाड्र्स कार्यालय, चौरसी में नव निर्मित राजकीय भवन के निर्माण हेतु विधि-विधान से भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में होमगाड्र्स विभाग निरंतर सशक्त और आधुनिक बन रहा है। उन्होंने कहा यह विभाग सुविधाओं, सम्मान और सुरक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 39 जिलों एवं 07 मंडलीय प्रशिक्षण केंद्रों में विभाग के अपने शासकीय भवन स्थापित हो चुके हैं, जबकि 11 जिलों एवं 01 मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमें जनपद जालौन भी शामिल हो गया है। कहा कि पूर्व में ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में दिवंगत होमगाड्र्स को मात्र 03 लाख रुपये की बीमा राशि मिलती थी, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा सेवाकाल में दिवंगत होने पर 05 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, साथ ही एक पात्र आश्रित को होमगाड्र्स स्वयंसेवक के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना में दिवंगत होने पर 30 लाख रुपये तक की सहायता राशि विभिन्न बैंकों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि होमगाड्र्स के बेहतर टर्न-आउट हेतु 3000 रुपये प्रति होमगार्ड वर्दी भत्ता, प्रत्येक थाने में पुरुष एवं महिला होमगाड्र्स हेतु पृथक-पृथक सुविधायुक्त कक्ष, तथा प्रशिक्षण भत्ता व ड्यूटी भत्ता समान कर दिया गया है। वर्तमान में विभाग के समस्त कार्य पूर्णतः ऑनलाइन संचालित हो रहे हैं। सदर विधायक ने कहा कि होमगाड्र्स हमारे समाज की सुरक्षा की मजबूत कड़ी हैं, जो हर आपदा, चुनाव, पर्व-त्योहार और कानून-व्यवस्था के समय निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज जिला कमाण्डेन्ट कार्यालय के भवन का भूमि पूजन होना जनपद जालौन के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने होमगाड्र्स जवानों के सम्मान, सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। पहले जिन जवानों को पहचान और संसाधन नहीं मिलते थे, आज वही जवान आधुनिक सुविधाओं, बेहतर मानदेय और सुरक्षित भविष्य के साथ सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया भवन न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाएगा, बल्कि होमगाड्र्स जवानों के मनोबल को भी नई ऊँचाइयाँ देगा।उन्होंने निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध पूर्ण कराने की अपेक्षा व्यक्त की। कहा कि जालौन को यह सौगात मिलना विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है। कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सुरक्षा, ऑनलाइन व्यवस्थाएँ और आधारभूत सुविधाएँ यह दर्शाती हैं कि होमगाड्र्स अब केवल स्वयंसेवक नहीं, बल्कि एक सशक्त सुरक्षा बल के रूप में स्थापित हो रहे हैं।

घर के दरवाजे खड़ा ट्रैक्टर ट्राली उठा ले गए चोर

माधौगढ़। कोतवाली क्षेत्र में कस्बे के उमरी रोड पर मकान के दरवाजे पर खड़े ट्रैक्टर ट्राली को चोर चोरी कर ले गए। ट्रैक्टर स्वामी ने तहरीर पुलिस को सौंप दी है।

कोतवाली क्षेत्र के गांव रुदपुरा निवासी अनिल सिंह उर्फ पंकज राजावत पुत्र दीप सिह माधौगढ कस्वा के मुहोल्ला मालवीय उत्तरी के उमरी रोड पर कई सालों से मकान बना कर रह रहे थे। जो सड़क पर मकान होने व परिवार को चलाने के लिए बिल्डिंग मेटेरियल की दुकान किए हुए हैं। बिल्डिंग मेटेरियल इधर-उधर भेजने के लिए 2021 में महेन्द्रा टेक्टर ट्राली खरीदा था। बुधवार की रात में टेक्टर ट्राली को अपने मकान के बगल में खड़ा कर दिया और सर्दी होने की वजह से पत्नी रेनू देवी व बच्चों के साथ खाना खाने के बाद मकान के अंदर सोने चले गए। जब सुबह दरवाजे के बाहर टेक्टर ट्राली न देख उनके होश उड़ गए। वहीं टेक्टर ट्राली चोरी होने की बात सुनकर मुहोल्ले के लोग एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कोतवाल बिकेश बाबू पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। इतना ही नहीं बल्कि आसपास लगे सीसी टीबी फुटेज भी खंगाले। टेक्टर ट्राली मालिक अनिल सिहं उर्फ पंकज राजावत ने कोतवाली में पहुंचकर अज्ञात चोरो के खिलाफ तहरीर दे दी है।

प्रत्येक शिकायत का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण हो : डीएम

जन एक्सप्रेस । हरदोई

हरदोई।कलेक्ट्रेट कक्ष में जन सुनवाई के दौरान डीएम अनुनय झा ने आमजन की समस्याओं को सुना तथा जन सुनवाई मे आज कुल 82 शिकायते प्राप्त हुई, जिसके त्वरित निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए।डीएम ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण हो। जन सुनवाई मे प्राप्त कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान किया। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण लंबित न रखें तथा कृषक दुर्घटना बीमा योजना के किसी आवेदन को लंबित न रखा जाये व पात्रो को योजनाओं का लाभ दिया जाये। इस अवसर पर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भूमिका यादव व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

श्री बरसाना धाम फ़ाउंडेशन ने सिग्नेचर ग्लोबल के विशेष सहयोग से बरसाना में 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न कराया

जन एक्सप्रेस । मथुरा

बरसाना। श्री बरसाना धाम फाउंडेशन ने पावन भूमि बरसाना में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 101 कन्याओं का भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया। यह आयोजन संतों एवं आध्यात्मिक गुरुओं की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस पुनीत पहल को सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ, जो दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सशक्त पहचान रखने वाली भारत की अग्रणी रियल एस्टेट विकास कंपनियों में से एक है। यह सहयोग कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है।

बरसाना में आयोजित इस समारोह का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों को सहयोग प्रदान करना था, ताकि उनकी बेटियों के विवाह सम्मानजनक एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें, साथ ही सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए, सिग्नेचर ग्लोबल ने आयोजन के सुचारू संचालन में योगदान दिया। यह सहयोग इस विश्वास को दर्शाता है कि कॉरपोरेट जिम्मेदारी केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के प्रति सार्थक सहभागिता भी है।

इस अवसर पर टिप्पणी करते हुए, श्री बरसाना धाम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप अग्रवाल ने कहा, सिग्नेचर ग्लोबल में हमारा मानना है कि सामाजिक करुणा के बिना वास्तविक विकास अधूरा है। इस नेक पहल में श्री बरसाना धाम फाउंडेशन का सहयोग करना हमारे गरिमा, समावेशन और सामुदायिक उत्थान जैसे मूल मूल्यों के अनुरूप है। यह सुनिश्चित करना कि हर बेटी अपने नए जीवन की शुरुआत सम्मान और सुरक्षा के साथ करे, हम सभी की साझा सामाजिक जिम्मेदारी है।

सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के सह-संस्थापक एवं उपाध्यक्ष श्री ललित अग्रवाल ने कहा, इस तरह की पहल सामूहिक प्रगति की सच्ची भावना को दर्शाती हैं। ब्रज धाम फाउंडेशन के प्रयासों का समर्थन करके हमारा उद्देश्य समाज में सार्थक योगदान देना और परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक व सामाजिक बोझ को कम करना है। इस प्रकार की साझेदारियां समुदायों को सशक्त बनाती हैं और दीर्घकालिक सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बीएसए को ज्ञापन सौंपकर, शिक्षक समस्याओं के निराकरण की उठाई माँग

जन एक्सप्रेस । उरई

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का प्रतिनिधमंडल जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्र प्रकाश से मिला व शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं से संबंधित आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

जिला महामंत्री इलयास मंसूरी ने तीसरे चरण के समायोजन में लगी आपत्तियों को दूर करके शिक्षकों के साथ न्याय करने की मांग की। इसके साथ ही बेसिक शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने, शिक्षामित्रों के स्थानांतरण समायोजन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने, बीईओ द्वारा सीसीएल आवेदनों पर अनावश्यक आपत्ति लगाकर आवेदन अपने स्तर से निरस्त किए जाने पर रोक लगाने, आधार कार्ड बनवाने हेतु बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र बनवाने की जिम्मेदारी ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत सचिव को सौंपे जाने, 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे ऐसे शिक्षक जो गैर जनपद से आए थे परंतु उनका जीपीएफ फंड अभी तक नहीं आया है शीघ्र मंगवाने और समस्त सेवानिवृत शिक्षकों के की पेंशन व फंड भुगतान की कार्यवाहियों समय से पूर्ण करवाने, बाउंड्रीवल का निर्माण व उच्चीकरण करवाने, एमडीएम कनवर्जन कॉस्ट व फल वितरण धनराशि अग्रिम या समय से भेजे जाने आदि समस्याओं को दूर करने की मांग प्रमुख रूप से की।बीएसए द्वारा समस्याओं को गंभीरतापूर्व सुना गया व शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया गया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में प्रदेशीय मीडिया प्रमुख बृजेश श्रीवास्तव, सरला कुशवाहा, इनाम उल्ला अंसारी, संजीव गुर्जर, हेमा पटेल, कल्पना, शिल्पी, सत्यपाल, अमित यादव, रामराजा सोनी, सत्यनारायण, रामप्रकाश सोनी, सरला सिंह, राममनोहर आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।

महराजगंज में मतदाता पुनरीक्षण पर फोकस, डीएम की अध्यक्षता में बैठक

मतदाता सूची को त्रुटिरहित व अद्यतन बनाने पर जोर, राजनीतिक दलों से मांगा सक्रिय सहयोग

जन एक्सप्रेस । महराजगंज

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची के अद्यतन कार्य की प्रगति से राजनीतिक दलों को अवगत कराना तथा इस प्रक्रिया में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना रहा।

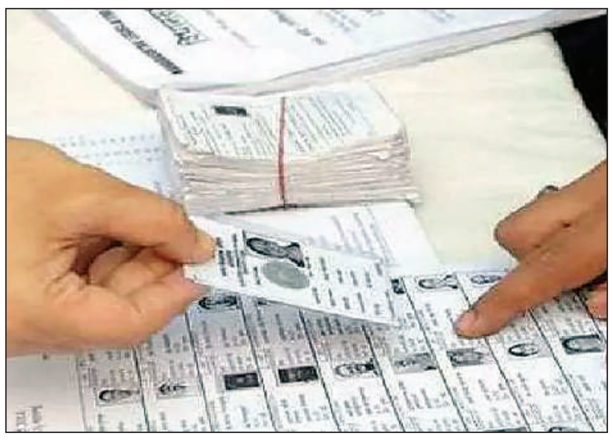

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने फॉर्म-06 (नया नाम जोड़ने), फॉर्म-07 (नाम विलोपन) एवं फॉर्म-08 (संशोधन) की प्राप्ति एवं निस्तारण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर से अब तक कुल 43,755 फॉर्म-06 प्राप्त हुए हैं, जिनमें 238 ऑफलाइन तथा 43,517 ऑनलाइन हैं। इसी प्रकार कुल 1,482 फॉर्म-07 प्राप्त हुए हैं, जिनमें केवल एक ऑनलाइन है। वहीं फॉर्म-08 की कुल संख्या 10,975 है, जिनमें 135 ऑफलाइन तथा 10,840 ऑनलाइन भरे गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन आवेदनों की अधिकता मतदाताओं के बढ़ते डिजिटल रुझान को दर्शाती है, जो एक सकारात्मक संकेत है।

जिलाधिकारी ने नो-मैपिंग मतदाताओं की सुनवाई, दावे एवं आपत्तियों के परीक्षण तथा निस्तारण की निर्धारित समयसीमा और पारदर्शी प्रक्रिया को बिंदुवार स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि सभी आवेदन भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे मतदाता सूची त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाई जा सके। बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एसआईआर प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से संचालित किए जाने पर संतोष व्यक्त किया और मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। जिलाधिकारी ने 31 जनवरी एवं 5 फरवरी को आयोजित होने वाले विशेष अभियान की जानकारी देते हुए सभी राजनीतिक दलों से सक्रिय सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि इन तिथियों पर बीएलओ एवं सुपरवाइजर पूरे समय उपस्थित रहेंगे। साथ ही बीएलए के माध्यम से फॉर्म-06, 07 एवं 08 के अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कराने का आह्वान किया, ताकि कोई भी अर्ह मतदाता नामावली में पंजीकरण से वंचित न रह जाए। बैठक में राजनीति दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

ई-रिक्शा ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, गंभीर

जन एक्सप्रेस प्रतापगढ़। जिले के कोहड़ौर थाना इलाके के अयोध्या-प्रयागराज राजमार्ग पर गुरुवार को कोहंडौर बाज़ार के वाजिदपुर मस्जिद के पास तेज रफ्तार ई रिक्शा ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया चालक रिक्शा छोडकर मौके से भाग निकला। मिली जानकारी के अनुसार कोहंडौर थाना इलाके के सरौली गांव निवासी बलिकरन का बेटा अजय कुमार (24 वर्ष) गुरुवार शाम घर से बाइक से कोहंडौर बाजार आया था। जैसे ही वह नई बाजार के पास पंहुचा था कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार ई-रिक्शा चालक ने टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गया। टक्कर मारकर रिक्शा चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची कोहंडौर पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोहड़ौर पहुंचाया जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने ई-रिक्शा और बाइक को कब्जे में ले लिया है।

हत्या के प्रयास का इनामिया आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

जन एक्सप्रेस । प्रतापगढ़

जिले में गुरुवार को नगर कोतवाली थाना इलाके में जियो पेट्रोल पंप के समीप एसटीएफ लखनऊ व थाना कोतवाली नगर पुलिस ने हत्या के प्रयास के इनामिया आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि देल्हूपुर थाना इलाके के भिखनापुर गांव निवासी सर्वजीत सिंह नगर कोतवाली थाना इलाके के जोगापुर में रहते हैं। बीते वर्ष अगस्त महीने में वो कचहरी से वकालत का कार्य समाप्त कर मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुँचे थे कि उसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी मोटरसाइकिल के बगल में अपनी मोटरसाइकिल लगाई और पीछे बैठे व्यक्ति ने अपने बैग से असलहा निकालकर सर्वजीत पर फायर कर दिया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के तीन दिन बाद ही कोतवाली नगर पुलिस एवं स्पेशल टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में दो अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था जबकि अभियुक्त संतोष ठाकुर जंगल का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया था। जिसके बाद पुलिस ने चार अभियुक्तों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया था। एसपी दीपक भूकर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एएसपी पूर्वी शैलेन्द्र लाल एवं सहायक पुलिस अधीक्षक (सीओ सिटी) प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में एसटीएफ यूनिट लखनऊ तथा थाना कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दबिश के दौरान मुखबिर की सूचना पर पच्चीस हजार रुपये के ईनामिया वांछित अभियुक्त संतोष ठाकुर उर्फ कृष्ण राज सिंह को नगर कोतवाली थाना इलाके के जियो पेट्रोल पंप के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त प्रयागराज जिले के झूसी थाना इलाके के वजहा गांव का रहने वाला है। इसके विरुद्ध जिले में दो मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया।

लग्जरी कार से बकरी चोरी करने का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, जेल

जन एक्सप्रेस । प्रतापगढ़

जिले देहात कोतवाली थाने की पुलिस ने लग्जरी कार से बकरियों की चोरी करने वाले एक अभियुक्त को प्रयागराज जिले के सोरांव थाना इलाके के तवकलपुर गांव के समीप से गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते वर्ष जुलाई महीने में देहात कोतवाली थाना इलाके के सिपाह महेरी गांव में एक महिला ने तहरीर देते हुए बताया कि उसके घर के बगल स्थित पशुशाला से बकरियों की चोरी कर रहे सफेद रंग की क्रेटा कार से आये चोर महिला के गुहार लगाने के बाद भाग गए। महिला की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। उसी क्रम में चौबीस घंटे के अंदर ही थाना देहात कोतवाली पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान दो अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर फरार अभियुक्त सलमान की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। एसपी दीपक भूकर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एएसपी पूर्वी शैलेन्द्र लाल एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर (सीओ सिटी) प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में एसआई अजीत सिंह व उनकी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दबिश के दौरान फरार अभियुक्त सलमान पुत्र पप्पू उर्फ हामिद को प्रयागराज जिले के सोरांव थाना इलाके के तवकलपुर से गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध दो मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार के गुरुवार को जेल भेज दिया।

अनैतिक देह व्यापार में दो होटल संचालक समेत 10 पर प्राथमिकी, भेजे गए जेल

देवरिया। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर कस्बे में स्थित होटल शिवाय में पुलिस की छापामारी के दौरान हिरासत में लिए गए युवक-युवतियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बुधवार को दो होटल संचालक समेत 10 लोगों के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर लिया। बाद में सभी को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस होटल शिवाय को सील कर मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर-देवरिया मुख्य मार्ग के बैतालपुर कस्बे में स्थित होटल शिवाय में लंबे अरसे से अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। स्थानीय लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर हरिराम यादव एवं नायब तहसीलदार गंगाराम के निर्देश पर सुरौली, गौरी बाजार तथा महिला थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने छापामारी कर सात जोड़ों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने थाने लाकर पकड़े गए लोगों से गहन पूछताछ के बाद होटल संचालक सहित 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया।

ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों पर डिजिटल लाइब्रेरी की होगी स्थापना

जन एक्सप्रेस । प्रतापगढ़

जिले में गुरुवार को विकास भवन के कक्ष में मुख्य विकास अधिकारी डा. दिव्या मिश्रा की अध्यक्षता में डिजिटल लाइब्रेरी समिति की बैठक की गयी। बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकान्त दर्वे ने बताया कि शासन द्वारा जनपद हेतु 319 ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जिले के 17 विकास खण्डों क्रमशः आसपुर देवसरा 19, बाबा बेलखरनाथधाम 16, बाबागंज 15, बिहार 17, गौरा 12, कुण्डा 17, कालाकांकर 15, लालगंज 15, लक्ष्मणपुर 15, मंगरौरा 27, मानधाता 18, पट्टी 17, रामपुर संग्रामगढ़ 14, सदर 21, सण्ड़वा चन्द्रिका 13, सांगीपुर 51 व शिवगढ़ की 17 चयनित ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जानी है। डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन के लिये यू.पी. डेस्को को सामग्री की आपूर्ति एवं एनबीटी के द्वारा पुस्तक की आपूर्ति हेतु आदेश कर दिया गया है। पंचायत भवनों पर डिजिटल लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री, ई-बुक्स, आनलाइन कोर्स, शैक्षणिक वीडियो, समाचार पत्र एवं इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है। डिजिटल लाइब्रेरी ग्रामीण छात्रों के लिये एक नई राह खोलेगी और उन्हे तकनीक के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी। इससे शिक्षा के क्षेत्र में समानता आयेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ग्राम पंचायत की यह पहल अच्छी साबित होगी। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक ओमकार राणा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेन्द्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य, पुस्तकालयाध्यक्ष नसरत अली सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

थाईलैंड की रानी ने बुद्ध प्रतिमा पर छतरी चढ़ाई

जन एक्सप्रेस । कुशीनगर

थाईलैंड की रानी चखुन फ्रा सुनीनाथा बिलासकल्याणी बुधवार को कुशीनगर स्थित थाई मोनास्ट्री में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहुंचीं। यहां कुछ देर आराम करने के बाद वह परिसर में ही विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुईं। इस बीच थाईलैंड के नौवें महाराजा रहे राम भूमिबोल अदुल्यदेज की प्रतिमा के समक्ष पूजा की। पूजा के बाद उपोसथ हाल में बुद्ध की प्रतिमा पर छतरी चढ़ाई। बिलासकल्याणी ने थाई चैत्य की भी पूजा की और परिसर में पौधरोपण किया। अभी थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकॉन हैं। रानी बृहस्पतिवार को सुबह महापरिनिर्वाण मंदिर और रामाभार स्तूप का पूजन व दर्शन करेंगी। इसी क्रम में वह थाई क्लीनिक का निरीक्षण भी करेंगी।

इससे पूर्व बिलासकल्याणी के वाहनों का काफिला जब गुजरा तो उनके स्वागत के लिए बुद्ध मंदिर पर सड़क के दोनों किनारे खड़े बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भारत और थाई का राष्ट्रीय ध्वज लहरा कर स्वागत किया। उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान डॉ. फ्रा बोधियांग, डॉ. पी खोमशान, फ्रा सोम पोंग, फ्रा सोंग क्रा, तहसीलदार धर्मवीर सिंह आदि मौजूद रहे।

काठमांडो को हराकर सेफा में पहुंचा गोपालगंज

कुशीनगर। तमकुही विकास खंड के ग्राम पंचायत बरवाराजापाकड़ के शनीचरी फील्ड में संजय क्लब के तत्वावधान में आयोजित 48वीं संजय कप आल इंडिया फुटबाल प्रतियोगिता के उद्घाटन मुकाबले में सनराइज स्पोर्टिंग क्लब गोपालगंज, बिहार ने अटैक फुटबाल क्लब काठमांडू, नेपाल को 3-0 से पराजित कर अगले दौर में जगह बना ली। इस मुकाबले में गोपालगंज की टीम ने शुरुआत से अंत तक खेल पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा। बुधवार को मैच प्रारंभ होते ही गोपालगंज की टीम ने आक्रामक रणनीति अपनाई। खेल के 8वें मिनट में जर्सी नंबर 12 खिलाड़ी कमरुन ने सटीक प्रहार कर पहला गोल दागा व टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद 18वें मिनट में जर्सी नंबर छह खिलाड़ी असगर ने गोल कर स्कोर 2-0 कर दिया। लगातार दबाव में रही काठमांडू की टीम संभल नहीं सकी। 32वें मिनट में असगर ने एक व आकर्षक गोल करते हुए व्यक्तिगत दूसरा व टीम के लिए तीसरा गोल किया।

संयुक्त कृषि निदेशक ने भूमि संरक्षण इकाई परियोजना का किया निरीक्षण

जन एक्सप्रेस । प्रतापगढ़

जिले में गुरुवार को संयुक्त कृषि निदेशक प्रयागराज संतोष कुमार राय द्वारा भूमि संरक्षण इकाई द्वितीय में संचालित योजना पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजनान्तर्गत परियोजना नेवाड़ी का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय परियोजना प्रभारी संजय सिंह, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-बी ध्रुव कुमार यादव व अवर अभियन्ता आशीष कुमार यादव एवं दिनकर मौके पर उपस्थित रहे। संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा योजना के लाभ के बारे में बताया गया कि बिहड़ बंजर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत मृदा कटाव रोकने एवं वर्षा जल संरक्षण हेतु अवरोध बांध, समोच्य रेखीय बांध, मार्जिनल बांध का कार्य कराया गया है एवं अवरोध बांधों पर वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है जिसे मृदा का स्थायित्व बना रहता है साथ ही इस योजना से फसलोउत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 3500 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान भी किसानों को दिया जायेगा।

सड़क पार करते समय साइकिल सवार वृद्ध को कार ने मारी टक्कर, मौत

जन एक्सप्रेस । प्रतापगढ़

जिले में कोहड़ौर थाना इलाके में प्रयागराज-अयोध्या राजमार्ग पर बुधवार शाम सड़क दुर्घटना में घायल वृद्ध की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी।

जिले के कोहड़ौर थाना इलाके के नगर पंचायत कोहंडौर के घनापुर निवासी मुनीर उर्फ फुल्लन (62 वर्ष) बुधवार देर शाम घर से कोहड़ौर बाजार किसी काम से आये थे। कस्बे में स्थित बड़ौदा ग्रामीण बैंक के सामने साइकिल से सड़क पार कर ही रहे थे कि सुल्तानपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि वृद्ध साइकिल समेत दूर जा गिरा और गम्भीर रूप से घायल हो गया। कार चालक कार समेत मौके से फरार हो गया। वहां मौजूद लोगों ने वृद्ध को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोहड़ौर पहुंचाया। सूचना पर परिजन भी रोते बिलखते सीएचसी कोहड़ौर पहुंचे। सीएचसी में वृद्ध की हालत गम्भीर देख डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन वृद्ध को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वृद्ध के भतीजे शकील की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच कर रही है। वहीं गुरुवार देर शाम वृद्ध का शव पोस्टमार्टम के बाद कोहड़ौर (घनापुर) पहुंचा जहां गमगीन माहौल में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया।

सिलिंडर फटने से रिहायशी झोपड़ी में लगी आग

देवरिया। कस्बे के हनुमान चौराहे के पास चाय बनाते समय छोटा सिलिंडर फटने से रिहायशी झोपड़ी में आग लग गई। इसमें गेहूं, चावल, चौकी, चारपाई, भूसा और 15 हजार नगद जलकर खाक हो गया। मईल थाना क्षेत्र के भागलपुर हनुमान चौराहे के पास कस्बा निवासी दूधनाथ यादव का घोठा है। बुधवार की शाम परिवार के सभी लोग खेत में थे। झोपड़ी में आठ वर्ष की शिल्पी बीमार दादा के कहने पर चाय बनाने के लिए छोटा सिलिंडर खोलकर उसने जैसे माचिस जलाई सिलिंडर में आग लग गई। यह देख शिल्पी चिल्लाते हुए बाहर भाग गई। तभी तेज आवाज के साथ पेट्रोमेक्स फट गया और झोपड़ी जलने लगी। जब तक लोग आग पर काबू पाते झोपड़ी में रखा गेहूं, चावल समेत अन्य सामान जलकर राख हो गए। प्रधान पति बृजभूषण यादव ने घटना की सूचना तहसील प्रशासन को दी।

मिशन शक्ति टीम ने महिला एवं साइबर सुरक्षा के मद्देनजर किया जागरूक

जन एक्सप्रेस । प्रतापगढ़

जिले के थाना कुण्डा कोतवाली पे तैनात मिशन शक्ति टीम द्वारा आदर्श प्राइमरी स्कूल साहाबपुर में बालिकाओं को महिला एवं साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। एसपी दीपक भूकर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बालिकाओं को महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को महिला सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन नंबरों, साइबर अपराध से बचाव, नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी गई तथा उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान टीम ने बालिकाओं से उनकी समस्याओं के बारे में संवाद कर उन्हें यह आश्वस्त किया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर पुलिस सदैव उनकी सहायता हेतु तत्पर है। इसके अलावां थाने पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क की जानकारी प्रदान करते हुए थाने का सीयूजी नम्बर उपलब्ध कराते हुए बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर सीधे संपर्क करने की बात कही गई। पुलिस द्वारा चलाये जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा के प्रति विश्वास, जागरूकता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती, स्कूली बसों की सुरक्षा सर्वोपरि : डीएम

जन एक्सप्रेस। जौनपुर

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली और इस पर सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि परिवहन विभाग की बसों के चालक किसी भी स्थिति में शराब पीकर वाहन न चलाएं, इसकी नियमित जांच की जाए।

जिलाधिकारी ने जेसीज चौराहे पर अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों पर नाराजगी जताते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस पर एआरटीओ ने आश्वस्त किया कि संबंधित व्यवस्थाएं शीघ्र ही सुधार ली जाएंगी।

इसके अलावा कुत्तूपुर चौराहे के पास सड़क पर बने गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए गए, जिससे आवागमन सुरक्षित और सुचारु हो सके। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्कूली बसें केवल फिटनेस प्रमाणपत्र के आधार पर ही संचालित हों। बच्चों को बस से उतारते और चढ़ाते समय बस सड़क के किनारे नहीं, बल्कि विद्यालय परिसर में ही खड़ी की जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों का जीवन अनमोल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में जनपद के सभी स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि बच्चों को सड़क पर न उतारा जाए और न ही सड़क से चढ़ाया जाए। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार नदी में गिरी, शीशा तोड़कर चालक ने बचाई जान

जन एक्सप्रेस। नरायनपुर। मिर्जापुर। अदलहाट थाना अंतर्गत रैपुरिया गांव में गंगा पार करते समय छिनैती की डर से तेज रफ्तार जा रही कार पीपा पुल के प्लेट में फंसकर मंगलवार की रात नदी में गिर गई। चालक शीशा तोड़कर कार से बाहर निकला। उसने पीपा में लगे रस्से को पकड़ कर जान बचाई। ग्रामीणों ने रैपुरिया घाट पहुंचकर कार चालक को बाहर निकाला रैपुरिया गांव निवासी विनय यादव (35) ने बताया कि वह अपनी कार से वाराणसी जा रहा था। पीपा पुल से नदी पार करते समय गमछा से मुंह बांधे लोग कुछ लाग उसे रोकने लगे। छिनैती की डर से वह कार घुमाकर वापस घर लौटने लगे। बीच गंगा में पीपा पुल पर बिछाई गई प्लेट में फंस कर कार रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में चली गई। वह कार का शीशा तोड़कर किसी तरह से बाहर निकलकर पीपा में बंधे रस्से को पकड़ गए। शोर मचाने पर आस-पास के ग्रामीण आए। उनको बाहर निकाला।

स्काउट-गाइड से विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा-भाव जागृत

जन एक्सप्रेस। बस्ती

हरैया कस्बे के हाजी मोहम्मद अमीन इण्टर कॉलेज में चल रहे तीन दिवसीय स्काउट गाइड शिविर प्रथम सोपान का गुरुवार को समापन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्यालय संगठन के पूर्व प्रधानाचार्य एमडी ओझा ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर समापन सत्र का शुभारंभ किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में विकास अधिकारी प्रेम शंकर ओझा, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष रवीश कुमार मिश्र, जिला संगठन मंत्री विवेक कान्त पाण्डेय रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य के एन वर्मा ने माल्यार्पण, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि स्काउट-गाइड प्रशिक्षण से विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा-भाव, नेतृत्व क्षमता और नैतिक आचरण विकसित होता है। कहा कि ऐसे प्रशिक्षण शिविर विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखते बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक और समाज के लिए उपयोगी स्वयंसेवक बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं।

विशिष्ट अतिथि विवेक कान्त पाण्डेय आदि ने कहा कि स्काउट और गाइड एक शैक्षिक युवा आंदोलन है, जो बच्चों और युवाओं को अच्छा नागरिक बनाने पर केंद्रित है। उन्होंने स्काउट गाइड से समाज और दूसरों की मदद के लिए आगे आने, भाईचारे, श्रमदान और शांति के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि युवाओं को समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिला संगठन कमिश्नर स्काउट प्रताप शंकर पाण्डेय, विजय कश्यप, आदर्श मिश्र, ट्रेनिंग काउंसलर गाइड नंदनी की देखरेख में बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रशिक्षण के दौरान स्काउट-गाइड के प्रथम सोपान के अंतर्गत ध्वज शिष्टाचार, मार्च पास्ट, ड्रिल, स्काउट प्रतिज्ञा एवं नियम, टोली पद्धति, प्राथमिक चिकित्सा, गांठें एवं बंधन, मैप रीडिंग, अनुशासन अभ्यास, सामूहिक खेल, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जानकारी तथा सेवा कार्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। शिविर समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टोली और प्रशिक्षण में लगे स्टाफ को पुरस्कृत किया गया।

सहखातेदार की जमीन से मिट्टी चोरी मामले पर कोर्ट सख्त, एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश

जन एक्सप्रेस। जौनपुर

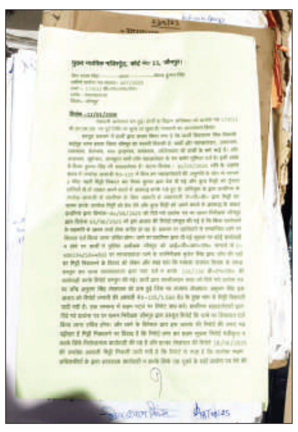

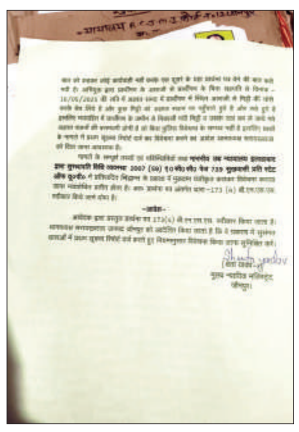

जिले के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र अंतर्गत सद्धोपुर गांव में सहखातेदारों की भूमि से बिना अनुमति के मिट्टी निकालकर बेचने के मामले में जनपद न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। माननीय न्यायालय ने धारा 173(4) बीएनएसएस के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थाना सरायख्वाजा को संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करने का निर्देश दिया है।

प्रार्थी शिवश्याम सिंह निवासी सद्धोपुर थाना बक्शा जिला जौनपुर द्वारा न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि वह और उनके भाई उदयभान, घनश्याम, तेजभान, स्व. इन्द्रभान, राधेश्याम, ललितभान सहित अन्य सहखातेदार आराजी संख्या 115 के भूमिधर हैं। इसी आराजी में विनय कुमार सिंह भी सहखातेदार हैं।

आरोप है कि दिनांक 16 मई 2025 की रात्रि में विनय कुमार सिंह द्वारा बिना सहखातेदारों की अनुमति जेसीबी मशीन से लगभग तीन फीट गहरी मिट्टी खुदाई कर बेच दी गई तथा कुछ मिट्टी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से ले जाकर अपने कब्जे में रख ली गई। प्रार्थी पक्ष द्वारा शिकायत किए जाने पर खनन निरीक्षक जौनपुर ने 5 जून 2025 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर बिना सहखातेदारों की सहमति के खनन कार्य होने की पुष्टि की और थाने में शिकायत दर्ज किए जाने को उचित बताया।

वहीं राजस्व लेखपाल की रिपोर्ट में भी आराजी संख्या 115 के कुछ भाग से मिट्टी निकाले जाने की पुष्टि हुई। इसके बावजूद थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज न कर केवल निरोधात्मक कार्रवाई की गई।

न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों, परिस्थितियों तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णयों के आधार पर माना कि प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराना न्यायोचित है। आदेश में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर प्रकरण में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार जांच सुनिश्चित करे।

वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता शेषनाथ सिंह सोलंकी ने पैरवी की, जबकि अभियुक्त विनय सिंह जौनपुर रेलवे स्टेशन पर पार्सल बाबू के पद पर कार्यरत हैं। इस आदेश के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना है।

यूरिया की किल्लत रोकने को सख्ती

17 खाद प्रतिष्ठानों पर छापा, 4 के लाइसेंस निलंबित

जन एक्सप्रेस। जौनपुर

रबी फसलों की बुवाई व सिंचाई के बाद टॉपड्रेसिंग के लिए किसानों द्वारा यूरिया की मांग तेजी से बढ़ने के बीच जिला कृषि विभाग ने उर्वरक वितरण व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इसी क्रम में 29 जनवरी 2026 को जनपद के 17 उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर एवं स्टॉक बोर्ड/रेट बोर्ड अद्यतन न पाए जाने पर चार उर्वरक बिक्री प्रतिष्ठानों सूरज खाद भंडार करंजाकला, प्रमोद खाद एवं बीज भंडार मनवल, नेशनल खाद भंडार तथा कृषि उन्नति एग्रीजंक्शन केंद्र सिद्दीकपुर का उर्वरक प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा आर.के. बीज भंडार मल्हनी पर रेट बोर्ड न पाए जाने तथा मैहर एग्रीजंक्शन केंद्र मल्हनी के बिना सूचना के बंद पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान पांच उर्वरक नमूने भी जांच के लिए संग्रहित किए गए। जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह ने किसानों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी अधिकृत बिक्री केंद्र से पीओएस मशीन पर अंगूठा लगाकर, अपनी जोत बही के अनुसार संस्तुत मात्रा में ही यूरिया उर्वरक खरीदें तथा रसीद अवश्य प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या मनमानी बिक्री की शिकायत जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 8419021250 पर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज कराई जा सकती है।

बाल वाटिका के माध्यम से हो रहा बच्चों का समग्र विकास : बीडीओ

जन एक्सप्रेस। बस्ती

ब्लाक संसाधन केंद्र हरैया पर गुरुवार को हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। बाल वाटिका में बच्चों को खेल के माध्यम से भाषा व गणित ज्ञान कराए जाने के साथ ही उनके समग्र विकास पर जोर दिया गया। खंड विकास अधिकारी विनय कुमार द्विवेदी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार आंगनबाड़ी केदो के माध्यम से तीन से 6 साल के बच्चों के समग्र विकास पर जोर दे रही है। आंगनबाड़ी तथा प्राथमिक विद्यालय के समन्वय से संचालित बाल वाटिका छोटे बच्चों के समग्र विकास हेतु अत्यंत प्रभावी है। खंड शिक्षा अधिकारी विजय आनंद ने कहा कि बाल वाटिका के प्रभावी संचालन हेतु कार्य योजना का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन किया जाए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वांडर बाक्स तथा अन्य सामग्रियों सहित खेल के समानों का समुचित प्रयोग किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकत्री शीला सिंह तथा अनीता ने बच्चों को अंक ज्ञान के सरल तरीके सुझाए। एआरपी संतोष शुक्ल तथा मनोज मिश्र, शिक्षक संकुल योगेश सिंह सुपरवाइजर नीता वर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रत्येक न्याय पंचायत के पांच निपुण बच्चों को स्टेशनरी किट देकर पुरस्कृत किया गया। प्राथमिक शिक्षक संघ के तहसील अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार तिवारी, ब्लाक अध्यक्ष हरैया विकास पाण्डेय, उपाध्यक्ष विपिन शुक्ला के साथ ही भारती शुक्ला, अखिलेश सिंह, लवकुश त्रिपाठी, पीयूष मिश्र, अशोक वर्मा, इश्तियाक अहमद,सूर्य प्रकाश सिंह, अरुण कुमार शुक्ल, गुलाम अशरफ, विश्वजीत गुप्ता, श्रवण कुमार मिश्र, बालकृष्ण मिश्र, राम भवन, छोटेलाल, हरि सिंह, मनोज उपाध्याय, जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी, विवेक कांत पांडेय, नईमुद्दीन, आनंद कुमार, मनोज कुमार वर्मा, सुनील कुमार, राजेश कुमार, गिरिजेश कुमार सिंह सर्वदेव सिंह आदि अध्यापक उपस्थित रहे।

टीचर्स गाइड्स मॉड्यूल पर आधारित तीन दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

जन एक्सप्रेस। बस्ती

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल के निर्देशन में चल रहे टीचर्स गाइड्स मॉड्यूल पर आधारित तीन दिवसीय प्रशिक्षण गुरुवार को सम्पन्न हुआ। जिसमें जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अंग्रेजी विषय के शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। सभी प्रतिभागी शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित कर प्रशिक्षण का समापन किया गया। डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों के ज्ञान, कौशल और क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे नई शिक्षण विधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। प्रशिक्षण के नोडल डायट प्रवक्ता डॉ रविनाथ त्रिपाठी ने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों में तर्कसंगत विचार, चिंतन और शिक्षण कौशल का विकास करना है। इस अवसर पर डॉ गोविन्द प्रसाद, वंदना चौधरी, डॉ ऋचा शुक्ला, मो. इमरान खान, सरिता चौधरी, कल्याण पाण्डेय, शशि दर्शन त्रिपाठी, कुलदीप चौधरी, अमन सेन आदि उपस्थित रहे।

सगाई के बाद धोखाधड़ी व झूठे मुकदमों में फँसाने की धमकी का आरोप पीड़ित परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार

जन एक्सप्रेस। जौनपुर

जनपद के शाहगंज थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहाँ सगाई के बाद युवक व उसके परिवार को झूठे मुकदमों में फँसाने, धन उगाही और मानसिक उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित रमाशंकर गुप्ता निवासी ग्राम सीड, थाना बदलापुर ने थाना शाहगंज में प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जाँच एवं विधिक कार्यवाही की माँग की है। पीड़ित के अनुसार उनके पुत्र सतीश कुमार गुप्ता की सगाई 29 मई 2025 को अमृता साहू पुत्री रामचंद्र साहू, निवासी शाहगंज के साथ तय हुई थी। सगाई के दौरान लड़की पक्ष की माँग पर लगभग ढाई लाख रुपये के आभूषण, नकद 11,000 सहित कपड़े, फल-मिष्ठान एवं अन्य उपहार दिए गए थे। आरोप है कि सगाई के बाद अमृता साहू एवं उसके परिजनों का व्यवहार बदल गया और वे अतिरिक्त गहनों, डायमंड ज्वेलरी, महंगे मोबाइल फोन व नकद धनराशि की माँग करने लगे। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मानसिक दबाव डालकर मोबाइल फोन बुक कराया गया तथा पेटीएम के माध्यम से पैसे भी ट्रांसफर करवाए गए। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि जब आगे धन देने से इनकार किया गया तो लड़की पक्ष द्वारा छेड़छाड़, बलात्कार और दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में फँसाने की धमकियाँ दी जाने लगीं। आरोप है कि फोन कॉल के माध्यम से युवक की नौकरी बदनाम कर समाप्त कराने की धमकी भी दी गई। इन कॉल्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग पीड़ित के पास होने का दावा किया गया है। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि लड़की की गंभीर चिकित्सीय स्थिति को सगाई से पहले छिपाया गया, जिसे पीड़ित पक्ष ने धोखाधड़ी बताया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अभियुक्तगण संगठित रूप से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और थाना शाहगंज में लगातार दबाव बना रहे हैं। पीड़ित रमाशंकर गुप्ता ने पुलिस से माँग की है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जाँच कराई जाए, फर्जी मुकदमों की धमकियों पर रोक लगाई जाए।

आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री को भेजा मांग-पत्र, कर्मचारियों को सरकारी दर्जा देने की मांग

जन एक्सप्रेस। जौनपुर

आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की लंबित मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। यह ज्ञापन जिलाधिकारी जौनपुर के माध्यम से भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ज्ञापन में बताया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां एवं सहायिकाएं विगत कई दशकों से महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारशिला के रूप में कार्य कर रही हैं।

वे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, टीकाकरण, मातृ-शिशु देखभाल सहित केंद्र व राज्य सरकार की अनेक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन कर रही हैं। इसके बावजूद आज भी उन्हें पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है और न ही सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मोर्चा की ओर से कहा गया कि उनकी मांगों से संबंधित ज्ञापन कई बार सरकार को सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं

- 1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए वेतनमान, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, महंगाई भत्ता तथा सवेतन मेडिकल अवकाश सहित सभी वैधानिक लाभ प्रदान किए जाएं।
- 2. उत्तर प्रदेश में भी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष की जाए तथा कोरोना काल से अब तक सेवानिवृत्त समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेंशन व ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए।
- मोर्चा ने सरकार से शीघ्र मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है, अन्यथा आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है।

इसी क्रम में 9 जनवरी 2026 को आगामी आंदोलन की पूर्व सूचना भी प्रशासन को दी गई थी, किंतु सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई।

नगर पालिका जौनपुर की लापरवाही से जनता बेहाल, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बना सालों का इंतज़ार

जन एक्सप्रेस। जौनपुर

नगर पालिका परिषद की सुस्त कार्यप्रणाली आम जनता के लिए भारी मुसीबत बनती जा रही है।

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे अत्यंत आवश्यक दस्तावेज़ों के लिए लोगों को महीनों नहीं, बल्कि एक-डेढ़ साल तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि कई मामलों में फाइलें रहस्यमय ढंग से लापता हो जा रही हैं। नियम के अनुसार एसडीएम कार्यालय से 10 दिनों के भीतर जांच आख्या मांगी जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वही रिपोर्ट आने में दो से तीन महीने लग जा रहे हैं। सफाई निरीक्षकों द्वारा समय से गवाही नहीं ली जा पा रही है, जिसके चलते फाइलें आगे बढ़ने के बजाय धूल फांकती रहती हैं। नगर पालिका और एसडीएम कार्यालय के चक्कर काटते-काटते आम नागरिक हताश हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो कोई ठोस जवाब मिलता है और न ही समस्या का समाधान। बाबू स्तर पर आए दिन किसी न किसी बहाने से फाइलें रिजेक्ट कर दी जाती हैं। कभी सर्वर डाउन तो कभी आवेदन ज्यादा हैं – बहानेबाजी का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जन्म प्रमाण पत्र न बनने से बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, न ही समय पर स्कूल में प्रवेश हो पा रहा है और न ही वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, मृत्यु प्रमाण पत्र न मिलने से विधवा पेंशन, बैंक संबंधी कार्य और अन्य सरकारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कई मामलों में फाइनल रिपोर्ट आने के बाद भी प्रमाण पत्र प्रिंट नहीं किए जा रहे हैं। लोग रोज़ाना दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। कई लोग तो बार-बार अपमान और टालमटोल झेलते-झेलते अपना सब्र खो चुके हैं। पूर्व में कर्मचारियों द्वारा एसआईआर प्रक्रिया में व्यस्त होने का बहाना बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी काम में कोई तेजी नहीं आई।

सवाल यह है कि आखिर जौनपुर की जनता कब तक यूं ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रहेगी? नगर पालिका की यह उदासीनता कब खत्म होगी और कब जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आम लोगों को समय से और आसानी से मिल पाएंगे? यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों के साथ खुला खिलवाड़ है – जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों का संज्ञान लेना अब बेहद जरूरी हो गया है।

जिले में एक निजी कार्यक्रम में यूपी के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्यमंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु पहुंचे जौनपुर

जन एक्सप्रेस। जौनपुर

मीडिया के सवालों का जबाव देते हुए कहा कि प्रयागराज के माघ मेला में एक घटना हुई उसके बाद उनको स्नान करने के लिए तमाम प्रयास किए गए तथा पूज्य शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को संगम में स्नान करना चाहिए था लेकिन अब वह लौट गए तो उस पर कमेंट करना ठीक नही है।

यूजीसी पर सुप्रीमकोर्ट द्वारा रोक लगाने को लेकर मंत्री दयाशंकर ने कहा कि अब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है तो अब उसमे कोर्ट निर्णय लेगी, उस विषय पर कुछ भी कहना उचित नही है क्योंकि उस विषय पर अब कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है।

एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि समाज के विरोध के बाद कोर्ट ने अब संज्ञान ले लिया है,जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान होगा।

अब किसी को भी इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नही है क्योंकि सुप्रीमकोर्ट से बड़ी कोई न्यायिक संस्था नही है।जो लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे है वह गलत है।

स्ढ्ढक्र के सवाल पर कहा कि अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए कि यह निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है,वोटर लिस्ट को शुद्ध करना समय की जरूरत होती है,बहुत सारे मृतकोंके नाम भी जुड़े हुए थे,वह सब हटाये गए। पारदर्शिता, वोटर लिस्ट की शुद्धता और समाज की भलाई का के लिए के लिए यह जरूरी था।

प्लेन क्रैश मामले पर ममता बनर्जी व अन्य नेताओं द्वारा राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री दयाशंकर ने कहा कि इस देश मे कई दुखद जाने प्लेन क्रैश होने की बजह से हुआ,इस पर किसी को कोई राजनीति नही करनी चाहिए।

अजीत पवार की दुखद मृत्यु एक अपूर्णीय क्षति है उनका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है,एक दुखद घटना है इस दुख की घड़ी में उस परिवार को सहारा देने की बजाय उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे है,उनके दर्द को और बढ़ाने का कार्य कर रहे है।यह दुखद और निंदनीय है।

शंकराचार्य जी को लेकर कहा कि इस मामले का पटाक्षेप हो गया,मुख्यमंत्री जी ने भी अपने स्तर से प्रयास किया न चाहते हुए भी घटना ऐसी हुई, उनको स्नान करना चाहिए था उनका जो मकसद था वह पूरा नही हुआ। मुख्यमंत्री बदलने के शंकराचार्य जी बयान पर उन्होंने कहा कि एक संत को राजनीतिक बयान नही करना चाहिए।

निपुण आकलन में फिर अव्वल रहने की तैयारी, बेसिक शिक्षा पर डीएम का फोकस

जन एक्सप्रेस। जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की डीटीएफ (ष्ठञ्जस्न) समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं और छात्रों के पोषण स्तर को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल ने बताया कि निपुण आकलन के परिणाम में विगत वर्ष जनपद जौनपुर ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने अवगत कराया कि इसी उपलब्धि को दोहराने के लिए इस वर्ष भी प्रभावी रणनीति के तहत सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

शैक्षिक भ्रमण के लिए आईआईटी कानपुर जाएंगी कस्तूरबा की छात्राएं

जन एक्सप्रेस। कन्नौज

जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों एवं शैक्षिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के भवन एवं शौचालय निर्माण, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थिति, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण, मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना के क्रियान्वयन सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के 05 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन हेतु प्रति विद्यालय ?1.72 लाख की धनराशि आईआईटी कानपुर शैक्षिक भ्रमण के लिए शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शैक्षिक भ्रमण से छात्राओं में जिज्ञासा-आधारित अधिगम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा नवाचार की भावना विकसित होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि यह भ्रमण कार्यक्रम 15 फरवरी से 25 फरवरी के मध्य अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। साथ ही, लग्जरी बस व्यवस्था, छात्राओं के साथ तैनात होमगार्ड, आवास, नाश्ता एवं भोजन सहित समस्त व्यवस्थाओं की विस्तृत कार्ययोजना तत्काल तैयार करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आवंटित एवं शेष धनराशि का विवरण अगले दिन तक उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को शासन द्वारा नामित 146 अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का ऑडिट कर प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं छात्र संख्या से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने परिषदीय विद्यालयों में स्वीकृत 21 दिव्यांगजन-सुलभ शौचालय, 10 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, 07 प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण, 01 उच्च प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में स्वीकृत 04 कंप्यूटर लैब, 01 टॉयलेट ब्लॉक, वॉलीबॉल ग्राउंड एवं बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कार्यदाई संस्था द्वारा धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि संबंधित संस्था के विरुद्ध शिथिलता संबंधी पत्राचार तत्काल किया जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षा समिति के अंतर्गत संचालित सभी निर्माण कार्य मार्च 2026 तक पूर्ण किए जाएं। कार्यों की प्रगति धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए तथा साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने फिनिशिंग, पेंटिंग एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य एकरूपता एवं निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिस प्रकार स्मार्ट सिटी एवं स्मार्ट विलेज की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है, उसी प्रकार स्मार्ट स्कूलों के विकास पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है।
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है, जिसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना होगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

माघ मेले गोताखोर टीम के साथ ही आपदा मित्रों की लगाई जाएगी ड्यूटी

महाशिवरात्रि पर मंदिर कमेटी के साथ व्यवस्था देखने आपदा मित्र

जन एक्सप्रेस। कन्नौज

जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में आगामी पर्वों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था एवं शान्ति समिति की बैठक के दौरान कहा है कि 01 फरवरी 2026 को माघी पूर्णिमा पर्व एवं संत रविदास जयन्ती है, जिसको ध्यान में रखते हुए समस्त प्रकार की तैयारी अभी से पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा है कि माघी पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेंहदी घाट पर स्नान हेतु आते है। माघी मेले की सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई, पार्किंग, विद्युत, गोताखोर,बैरिकेडिंग, मोबाइल शौचालय आदि की व्यवस्थायें समय से पूर्ण कर ली जाये। उन्होंने कहा कि घाट पर सुव्यवस्थित टॉयलेट, चेंजिंग रूम एवं लाइट की व्यवस्था तथा घाट की सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। घाट पर बैरिकेडिंग जाल होने के साथ ही उसपर झंडे लगे होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि गोताखोर टीम के साथ ही आपदा मित्रों की भी ड्यूटी मेले में लगाई जाए। मेले में मेडिकल टीम की भी तैनानी की जाएं। पार्किंग एवं ट्रैफिक प्लान की तैयारी पहले से ही कर ली जाए। डीएम ने कहा कि प्रभागीय वानिकी अधिकारी से समन्वय स्थापित कर गंगा आरती का भी भव्य आयोजन कराया जाये। उन्होने निर्देश दिये कि घाट पर गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कहा है कि संत रविदास जयंती के को ध्यान में रखते हुए जनपद में संत रविदास एवं अन्य महापुरूषो के स्थलों व सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि दिनांक 04 फरवरी को शब-ए-बरात को ध्यान में रखते हुए जनपद के विभिन्न मजारों/ कब्रिस्तानों पर साफ-सफाई एंव प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि महाशिवरात्रि के अवसर पर अधिक भीबड़ भाड़ वाले मंदिरों पर स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया जाये। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में आपदा मित्रों की ड्यूटी लगाई जाएं। मंदिर कमेटी के साथ महाशिवरात्रि पर व्यवस्था देखने में आपदा मित्रों से काम लिया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त/ राजस्व) देवेंद्र सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार, उप जिलाधिकारी सदर सुश्री वैशाली सहित अन्य संबंधित अफसर उपस्थित रहे।

न्यायिक कामकाज की समीक्षा में दो तहसीलदार और पांच नायब तहसीलदारों को फटकार

कारण बताओ नोटिस, तिर्वा का एक कर्मचारी निलम्बित

जन एक्सप्रेस। कन्नौज

जनपद में राजस्व वादों की समीक्षा के दौरान जनपद के समस्त राजस्व न्यायालयों में धारा-34 के कुल 4987 वाद लंबित पाए गए, जिसमें एक वर्ष से अधिक पुराने 888 वाद, तीन वर्ष से अधिक पुराने 234 वाद तथा पांच वर्ष से अधिक पुराने 34 वाद सम्मिलित हैं, जो न्यायिक कार्यप्रणाली में अपेक्षित गति न होने की ओर संकेत करते हैं।
समीक्षा में यह भी पाया गया कि नायब तहसीलदार, जलालाबाद के न्यायालय में धारा-34 के अंतर्गत कुल 378 वाद लंबित हैं, जिनमें एक वर्ष से अधिक पुराने 76 वाद, तीन वर्ष से अधिक पुराने 27 वाद तथा पांच वर्ष से अधिक पुराने 07 वाद शामिल हैं। पांच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित वादों की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री द्वारा नायब तहसीलदार, जलालाबाद को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने धारा-34 के अंतर्गत वादों का निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण न किए जाने के संबंध में तहसीलदार/ तहसीलदार (न्यायिक), छिबरामऊ एवं तिर्वा तथा नायब तहसीलदार, कन्नौज, तालग्राम, तिर्वा एवं हसेरन से भी स्पष्टीकरण मांगा।
उन्होंने समीक्षा में पाया कि तहसील तिर्वा के न्यायालय में धारा-34 के अंतर्गत वादों का समय से निस्तारण न होने के कारण एक कर्मचारी को निलंबित करते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजस्व वादों का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, तथा इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में समीक्षा के दौरान प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर और कठोर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

एसआईआर : शनिवार को विशेष अभियान, बूथ पर उपलब्ध होगी सूची और बीएलओ

जन एक्सप्रेस। कन्नौज

जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 31 जनवरी (शनिवार) को विशेष अभियान तिथि निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि विशेष अभियान तिथि के अवसर पर समस्त बूथ लेवल अधिकारी (बी0एल0ओ0) अपने-अपने मतदेय स्थलों पर पूर्वान्ह 10ः30 बजे से सायं 04ः30 बजे तक उपस्थित रहेंगे। इस दौरान आलेख्य निर्वाचक नामावली का वाचन किया जाएगा तथा मतदाताओं से दावे एवं आपत्तियां प्रपत्र-6, 7 एवं 8 पर निर्धारित घोषणा पत्र (अनुलग्नक-द्धङ्क) के साथ प्राप्त की जाएंगी।
विशेष अभियान के अंतर्गत गणना अवधि के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक एवं डुप्लीकेट श्रेणी में चिह्नित निर्वाचकों की सूची भी संबंधित बूथों पर उपलब्ध रहेगी एवं उसका वाचन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी बी0एल0ओ0 के पास प्रपत्र-6, 7, 8 एवं घोषणा पत्र (अनुलग्नक-द्धङ्क) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची में यदि कहीं कोई त्रुटि, कमी अथवा विसंगति पाई जाती है, तो उसे दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, जिससे मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।
उन्होंने बताया कि सभी मतदेय स्थलों पर बी0एल0ओ0 के साथ-साथ मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बी0एल0ए0 की उपस्थिति भी सुनिश्चित रहेगी। साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज को निर्देशित किया गया है कि संबंधित विद्यालयों, पंचायत भवनों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्वान्ह 10ः00 बजे तक खोला जाना सुनिश्चित करें, जिससे अभियान का सुचारू संचालन हो सके।
मतदाता अपनी किसी भी समस्या अथवा जानकारी के लिए मतदाता टोल-फ्री नंबर 1950 (स्त्रऌष्ठ कोड-05694) अथवा लैंडलाइन नंबर 05694-236467 पर संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अभियान की सतत निगरानी हेतु सुपरवाइजर, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहेंगे।
उन्होंने जनपद के समस्त मतदाताओं से अपील की जाती है कि वे विशेष अभियान तिथि 31 जनवरी 2026 को अपने संबंधित बूथ पर उपस्थित होकर मतदाता सूची का अवलोकन अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि अथवा सुधार की आवश्यकता हो, तो प्रपत्र-6 (नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु), प्रपत्र-7 (मतदाता सूची में सम्मिलित नाम पर आपत्ति हेतु) अथवा प्रपत्र-8 (प्रविष्टि में संशोधन, स्थानांतरण, ईपिक रिप्लेसमेंट एवं दिव्यांग चिह्नांकन हेतु) भरकर संबंधित बी0एल0ओ0 को समय से उपलब्ध कराएं, ताकि एक शुद्ध, अद्यतन एवं पारदर्शी मतदाता सूची तैयार की जा सके।

ग्राम समाज की जमीन पर लगे पेड़ों को प्रधान पर कटवाने का आरोप

जन एक्सप्रेस। सिंगाही खीरी

तहसील के ग्राम पंचायत बंगल्हा तकिया के ग्रामीणों ने प्रधान पर नियमो को दरकिनार रख ग्राम समाज की जमीन पर लगे पेड़ो को कटवाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को शिकायत की गई थी। जिसके बाद जांच को पहुचे राजस्व व वन कर्मियों संयुक्त टीम की जांच में नौ पेड़ सेमल के काटे हुए पाए गए।निघासन तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंगल्हा तकिया निवासी ग्राम जगेसर ने मुख्यमंत्री को शिकायत की थी कि परिन्दखां पुरवा के पूरब की और राजस्व की जमीन पर लगे सेमल पेड़ खड़े हुए थे। जिनको ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आजाद के द्वारा चोरी छिपे बेच दिया गया है। जिसको लेकर राजस्व विभाग के लेखपाल श्याम किशोर और वन विभाग के अखिलेश रावत ने जांच के दौरान बताया ग्राम पंचायत बंगल्हा तकिया के मजरा परिन्दखां पूर्व स्थित राजस्व की गाटा संख्या 2414 पर लगे सेमल के पेड़ काटे जाने की शिकायत मिली थी।मौके पर निरीक्षण करने पर नौ पेड़ कटे हुए पाए गए।

ये है प्रक्रिया

जबकि ग्राम पंचायत भूमि पर यदि पेड़ खड़े हुए हैं तो उनके बेचने के लिए पहले ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होना चाहिए फिर तहसील से लेखपाल गिनती कर वन विभाग से मूल्यांकन हो इसके पश्चात् खुली बोली से निलामी होगी और बिक्री का पैसा गांव निधि जमा किया जाता है।इस संबंध में उपजिलाधिकारी राजीव निगम ने बताया कि जांच करने के लिए मौके पर राजस्व कर्मचारियों को भेजा गया था। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एक्सप्रेस खबरें...

आयुष आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया

जन एक्सप्रेस। गोला गोकर्णनाथ खीरी। आयुष आपके द्वार के तहत ग्राम कपरहा मे पूर्व ग्राम प्रधान नीरज शुक्ला की अध्यक्षता मे उनके दरबाजे पर लगाया गया। शिविर में 28 मरीजो का परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान जडौरा के आयुर्वेद चिकित्सक डा हरि शंकर वर्मा व फार्मासिस्ट अनंग पाल सिह के द्वारा शिविर में आये हुये सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, डायबिटीज, संधिवात, आम बात, रक्तवात, आदि के रोगी देखे गए, और उनको नि- शुल्क दबाइयो का वितरण किया गया। वही डायबिटिज के मरीजो को मशीन से चेक करने के पश्चात अनको दवाइयां देकर परहेज की भी जानकारी दी गई।

सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अल्टीमेटम

जन एक्सप्रेस। लखीमपुर खीरी। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा और संबंधित संगठनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार को अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि यदि 7 मार्च 2026 तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो 8 मार्च को प्रदेशभर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लखनऊ कूच करेंगी। ज्ञापन में बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्षों से पोषण, टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही हैं। हालांकि, उन्हें अभी तक पूर्णकालिक कर्मचारी का दर्जा, वेतनमान, पेंशन और अन्य वैधानिक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

431 अधिवक्ताओं ने किया मतदान

जन एक्सप्रेस। कन्नौज। बार कौंसिल चुनाव के दूसरे दिन बुधवार को परिवार न्यायालय परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। सुबह से ही प्रत्याशियों के काउंटरों पर अधिवक्ताओं की भीड़ रही। 431 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पहले दिन 427 मत पड़े थे। इस प्रकार कुल पंजीकृत 971 में से 858 अधिवक्ताओं ने वोट डाले। मतदान के लिए तीन बूथ बनाए गए थे। चुनाव अधिकारी न्यायाधीश हरेंद्रनाथ की देखरेख में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। छिबरामऊ में बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए 281 वकीलों ने मतदान किया। मुंसिफी परिसर में वकीलों की भीड़ बनी रही। दूसरे दिन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपम कुशवाह की देखरेख में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद सिंह राठौर और महासचिव ललित प्रताप सिंह की मौजूदगी में सील मत पत्र खोले गए। 558 मतदाताओं में से पहले दिन 231 तथा दूसरे दिन 281 मतदाताओं ने मतदान किया। इस प्रकार कुल कुल 512 वोट पड़े।

घरेलू विवाद में किशोरी ने पीया कीटनाशक, मौत

जन एक्सप्रेस। कन्नौज। घरेलू विवाद के चलते बुधवार को एक किशोरी ने कीटनाशक पी लिया। घटना सौरिख के नगरिया महादेव की है। गंभीर हालत में किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां से उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही किशोरी ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। गरिया महादेव निवासी जहूर की बेटी मुस्कान (16) का मंगलवार को परिजनों से कहासुनी हो गई थी। इस बात से आहत होकर मुस्कान ने घर में रखा कीटनाशक पी लिया। उसकी हालत जब बिगड़ने लगी तब परिजनों को घटना की जानकारी हुई। परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा रेफर कर दिया। परिजनों द्वारा मुस्कान को राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। वहीं, प्रभारी निरीक्षक जयंती प्रसाद गंगवार ने बताया कि इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बारिश ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, फसलों को भारी नुकसान

जन एक्सप्रेस। कन्नौज। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 24 घंटों से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने ठंड के मौसम में 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंगलवार की रात से 12 घंटे तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश से खेतों में पानी भर गया है। इससे आलू, सरसों और दलहनी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार, जिले में 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है जो सामान्य से पांच मिलीमीटर अधिक है। इस बेमौसम बरसात के कारण तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। साथ ही सात किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही सर्द हवाओं ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। ठंड में हुई अप्रत्याशित बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में जलभराव के कारण आलू की फसल सड़ने की आशंका बढ़ गई है, साथ ही झुलसा रोग लगने का खतरा भी सता रहा है। तिलहनी फसलों, विशेषकर सरसों और अरहर को भी काफी नुकसान हुआ है। जमीन गीली होने और तेज हवाओं के कारण कई जगह सरसों की फसल गिर गई है, जिससे उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने की उम्मीद है। कृषि विभाग के अनुसार, जिले में 54 हजार हेक्टेयर में आलू और 17 हजार हेक्टेयर में सरसों की फसल बोई गई थी। बारिश और कोहरे की मार से अब तक 40 प्रतिशत आलू की बेलें मर चुकी हैं। सरसों में फूल झड़ने से भी उत्पादन घटने की आशंका है। बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे आम लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है। रोडवेज बस स्टैंड परिसर, कलक्ट्रेट के पास गेट और तिर्वा क्रासिंग जैसे स्थानों पर पानी भर जाने से यात्रियों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। धीरा ताल के ओवरफ्लो होने से कृष्णानगर के निवासियों को भी दिक्कतें हुईं। मौसम विभाग ने अगले तीन-चार दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है।

बैंक मित्र से दो लाख रुपए छीन कर युवक फरार

जन एक्सप्रेस। लखीमपुर खीरी

मैगलगंज लखीमपुर रोड स्थित इंडियन बैंक के बीसी संचालक राम लखन से किसी व्यक्ति द्वारा दो लाख रुपये की डिमांड की गयी डिमांड पर बीसी संचालक ने दो लाख रूपये की व्यवस्था की इसके बाद बिना नंबर की कार से वह व्यक्ति बीसी संचालक की दुकान पर आया और इधर-उधर की बातें करते हुए दो लाख रूपए छीनकर बिना नंबर की कार से फरार हो गया बीसी संचालक रामलखन ने बताया की सफेद कार थी आगे पीछे नंबर नहीं था। गाड़ी कोई और चल रहा था दूसरा व्यक्ति पैसा छीनकर गाड़ी में बैठकर फरार हो गया पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी है। इस घटना के बाद भी मैगलगंज पुलिस सक्रिय नहीं हुई घटना के कुछ देर बाद ही मेंन चौराहे पर लगे सब्जी बाजार से 75 वर्षीय बुजुर्ग की साइकिल चोरी हो गयी बुजुर्ग साइकिल खड़ी करके सब्जी खरीद रहे थे चंद मिनट में ही साइकिल चोरी हो गई फिलहाल दोनों घटनाओं के बाद मैगलगंज में पुलिस पर अपराधी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं वहीं दूसरी ओर मैगलगंज कस्बे के प्रभारी झरिया सिंह पूरी तरीके से निष्क्रीय नजर आ रहे हैं बीते कुछ दिनों में मैगलगंज कस्बे में अपराध का ग्राफ बड़ा है कुछ दिन पहले क्षेत्र में हुई चोरियों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया था लेकिन एक ही दिन में कस्बे में दो घटनाएं होने से पुलिस की कार्यशाली पर लोग सवाल उठा रहे हैं।

ओवरलोड गन्ना ट्रक पलटने से चपेट आई स्कूल वैन चार घायल, एक की हालत गंभीर

जन एक्सप्रेस। सुनहरा/ सिदाकत मंसूरी

लखीमपुर/ मोहम्मदी खीरी। मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को एक ओवरलोड गन्ना लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे की चपेट में एक स्कूल वैन आ गई, जिसमें सत्य पब्लिक स्कूल, मोहम्मदी के 19 छात्र सवार थे। यह घटना शुक्लपुर के पास हुई, जब छात्र विद्यालय से बिचपुरी की ओर जा रहे थे।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुवाया की ओर से मोहम्मदी गन्ना मंडी जा रहा ट्रक अचानक अपना संतुलन खो बैठा। इसके बाद वह सड़क किनारे चल रही स्कूली वैन पर पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से वैन में सवार सभी 19 बच्चे फंस गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में कक्षा छह का छात्र विराट गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके सिर में गंभीर चोटें आई हैं।उसे मोहम्मदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है।घायल छात्र ने बताया कि वैन में कुल 19 बच्चे सवार थे। इस दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल भी ट्रक के नीचे दब गई, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार, प्रभारी निरीक्षक सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पुलिस-प्रशासन की लापरवाही के कारण कस्बे में ओवरलोड वाहनों का संचालन लगातार जारी है, जिससे इस तरह के हादसे हो रहे हैं। हादसों के बाद भी जिम्मेदार संज्ञान नहीं लेते जो अपने आप में प्रश्न है।

ध्रुव प्रसंग सुन श्रोता हुए मंत्र मुग्ध

जन एक्सप्रेस। गोला गोकर्णनाथ खीरी

गांव कैमहरा में श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास ने ध्रुव प्रसंग सुनाया। नैमिषारण्य धाम से पधारे आचार्य शिव प्रकाश मिश्रा ने सुनाया कि सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए परीक्षित जी से कहते हैं परीक्षित बचपन में भगवान की भक्ति करना बहुत आसान होता है जो बालकपन में भगवान की भक्ति करता है भगवान उस पर बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं,इसी संदर्भ में ध्रुव जी की पावन कथा सुनाई। जिसमें कथा व्यास आचार्य शिव प्रकाश जी ने बताया श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार की बात ध्रुव जी अपने पिता की गोदी में बैठे हुए थे इतने में ध्रुव जी की सौतेली मां ने ध्रुव जी का अपमान कर दिया उन्होंने कहा कि अगर पिता की गोदी में बैठना है सो जाओ तपस्या करो और फिर मेरे गर्भ में आकर के जन्म लो तब तुम पिता की गोदी और राजगद्दी पर बैठने के लायक होंगे। इस तरह से ध्रुव जी का अपमान किया और भगवान का अपमान किया ध्रुव जी रोते हुए आए और अपनी माता सुनीति को बताया। तब सुनीति ने ध्रुव जी को परमपिता परमात्मा की गोदी के बारे में बताया ध्रुव की तपस्या करने के लिए चले गए और भगवान की तपस्या की जिस भगवान की गोदी प्राप्त की और भगवान ने 36000 वर्षों तक आकंटक राज्य करने का वरदान दिया। यह प्रसंग सुन श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए।

आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आवारा कुत्तों के मामले में पहले दिए गए आदेशों में बदलाव की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजनिया की पीठ ने एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। उन्होंने पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। पीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से पेश वकील की भी दलीलें सुनीं। ये दलीलें सात नवंबर 2025 के उस आदेश के पालन को लेकर थीं, जिसमें प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा जानवरों को हटाने और सड़कों के किनारे जाली लगाने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट ने एडब्ल्यूबीआई से क्या कहा?

- शीर्ष कोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) से कहा कि वह उन गैर-सरकारी संगठनों के आवेदनों पर कार्रवाई करे, जो पशु आश्रय स्थल या एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) केंद्र खोलने की अनुमति मांग रहे हैं।
- पीठ ने एडब्ल्यूबीआई के वकील से कहा, या तो आप आवेदन स्वीकार करें या खारिज करें, लेकिन इसे जल्दी करें।
- वकील ने बताया कि सात नवंबर के आदेश के बाद अलग-अलग संगठनों से ऐसे आवेदनों की संख्या काफी बढ़ गई है।
- सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि वे इस मामले में अपनी लिखित दलीलें जल्द से जल्द दाखिल करें।

निर्देशों का पालन न होने पर राज्यों पर जताई नाराजगी

इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने बुधवार को कई राज्यों की ओर से आवारा कुत्तों की नसबंदी न करने, डॉग पाउंड न बनाने और शिक्षण व अन्य संस्थानों के परिसरों से कुत्तों को न हटाने पर कड़ी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा, ये सभी हवा में महल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को पहले दिए गए निर्देशों के पालन पर भी दलीलों को सुना और असंतोष जताया। बेंच ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वे कहानियां सुन रहे हैं।

कोर्ट ने असम के आंकड़ों पर जताई हैरानी

कोर्ट ने असम से जुड़े आंकड़ों पर आश्चर्य जताया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राज्य में 2024 में कुत्तों के काटने के 1.66 लाख मामले सामने आए, जबकि वहां केवल एक डॉग सेंटर है। कोर्ट ने यह भी बताया कि जनवरी 2025 में ही 20,900 लोगों को कुत्तों ने काटा, जो कि बेहद चिंताजनक है। न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि आंध्र प्रदेश में 39 एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर हैं, जिनकी रोजाना 1,619 कुत्तों की नसबंदी करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि राज्य को मौजूदा सुविधाओं का ऑडिट करना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि उनका पूरा इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। साथ ही नए एबीसी सेंटर स्थापित करने के लिए एक समय-सीमा तय की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क पर रहने वाले कुत्तों की पहचान के लिए राज्य को संबंधित हितधारकों की मदद लेनी चाहिए।

13 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट सात नवंबर 2025 के अपने उस आदेश में बदलाव की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें अधिकारियों को सार्वजनिक क्षेत्रों और सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने का निर्देश दिया गया था। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह कुत्तों के काटने की घटनाओं पर राज्यों से 'भारी मुआवजा' दिलाने और ऐसे मामलों में कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जिम्मेदार ठहराने पर विचार करेगा। कोर्ट ने पिछले पांच साल से आवारा जानवरों से जुड़े नियमों को लागू न किए जाने पर भी चिंता जताई थी।

आवारा कुत्तों को तय आश्रय स्थलों में भेजा जाए

शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों और रेल स्टेशनों जैसे सार्वजनिक जगहों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में 'चिंताजनक वृद्धि' को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सात नवंबर को निर्देश दिया था कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद तुरंत आवारा कुत्तों को तय आश्रय स्थलों में भेजा जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि पकड़े गए आवारा कुत्तों को उनकी पुरानी जगह पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से सभी मवेशियों और अन्य आवारा जानवरों को हटाने का भी निर्देश दिया था।

'अजित दादा' पंचतत्व में विलीन

परिवार समेत समर्थकों ने नम आंखों से दी विदाई, अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। बारामती

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को गुरुवार को उनके गृहनगर बारामती में अंतिम विदाई दी गई। एक दुखद विमान हादसे में उनके निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में भारी संख्या में समर्थक अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे।

'अजित दादा अमर रहें' के नारे से गूंजा बारामती

अंतिम संस्कार की रस्में दोपहर में शुरू हुई। अजित पवार के बेटों, पार्थ और जय ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान उनकी पत्नी और राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार अपने आंसू नहीं रोक पा रही थीं। जब उनके पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ उनके गांव काटेवाड़ी से विद्या प्रतिष्ठान मैदान लाया गया। मैदान में मौजूद हजारों लोगों ने 'अजित दादा अमर रहें' के नारे लगाए, जिससे पूरा माहौल गमगीन हो गया।

अंतिम संस्कार में शामिल हुए कई केंद्रीय मंत्री

इस दुखद घड़ी में देश और राज्य के कई बड़े नेता बारामती पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, मुरलीधर मोहोल और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। अजित पवार के चाचा और एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार भी वहां मौजूद थे। वे पूरे समय चुपचाप बैठे रहे और अपने भतीजे को अंतिम विदाई दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पुणे से बारामती पहुंचे और पुष्पचक्र अर्पित किए।

अभिनेता रितेश देशमुख भी मौके पर रहे मौजूद

अजित पवार की चचेरी बहन और सांसद सुप्रिया सुले पूरे समय सुनेत्रा पवार के साथ खड़ी रहीं और उन्हें सांत्वना देती रहीं। अंतिम संस्कार में प्रफुल्ल पटेल, रामदास अठावले, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पूर्व मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे और अशोक चव्हाण जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हुए। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी काटेवाड़ी जाकर अजित पवार को श्रद्धांजलि दी। अजित पवार अपने अनुशासन के लिए जाने जाते थे। अंतिम संस्कार के दौरान लाउडस्पीकर से बार-बार लोगों से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई।

कैसे हुआ हादसा?

यह हादसा बुधवार को तब हुआ जब अजित पवार का विमान बारामती एयरस्ट्रिप के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान लैंडिंग से महज 200 मीटर पहले गिर गया और उसमें आग लग गई। इस हादसे में अजित पवार के साथ चार अन्य लोगों की भी मौत हो गई। मृतकों में पायलट कैप्टन सुमित कपूर, को-पायलट कैप्टन शाम्भवी पाठक, सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली शामिल थे।

ब्लैक बॉक्स हुआ बरामद

हादसे की जांच के लिए पुलिस ने आकस्मिक मौत (एडीआर) का मामला दर्ज किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। इसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर शामिल हैं, जिससे हादसे की असली वजह पता चल सकेगी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, खराब विजिबिलिटी की वजह से विमान को लैंडिंग में दिक्कत हुई थी।

विमानन मंत्री ने महाराष्ट्र सीएम फडणवीस को लिखा पत्र, हादसे की जांच में सहयोग मांगा

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से सहयोग मांगा, ताकि पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे पर हुए विमान हादसे की तेजी से जांच की जा सके। इस विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोग मारे गए थे।

बारामती जा रहे थे अजित पवार

अजित पवार बुधवार को निजी विमान से मुंबई से अपने पैतृक शहर बारामती जा रहे थे। उनके साथ चार अन्य सवार थे। लेकिन यह विमान बारामती की टेबलटॉप हवाई पट्टी (एयरस्ट्रिप) से करीब दो सौ मीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कोई भी जीवित नहीं बच पाया।

हादसे में अजित पवार के अलावा कौन लोग मारे गए?

इस हादसे में अजित पवार के साथ कैप्टन सुमित कपूर (जिनका उड़ान अनुभव 15,000 घंटे का था) सह-पायलट कैप्टन शांभवी पाठक (जिनका उड़ान अनुभव 1,500 घंटे का था) पवार के निजी सुरक्षा अधिकारी विदिप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी मारे गए।

फडवीस के आग्रह पर विमानन मंत्री ने क्या कहा?

इससे पहले फडणवीस ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया था कि वह इस दुर्घटना का सही कारण पता लगाने के लिए विस्तृत जांच का आदेश दें। उन्होंने भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का अनुरोध किया। नायडू ने कहा कि उनके मंत्रालय ने ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मुख्यमंत्री के अनुरोध को ध्यान में रखा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर जरूरी सुरक्षा सिफारिशें और नियामक या परिचालन संबंधी उपाय एएआईबी, विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और अन्य संबंधित पक्षों के तालमेल में लागू किए जाएंगे।

विमानन मंत्री ने क्या कहा?

- हादसे के एक दिन बाद विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा।
- पत्र में उन्होंने दुर्घटनास्थल तक पहुंच, स्थानीय प्रशासनिक मदद और स्थानीय एजेंसियों के साथ तालमेल सहित अन्य कदमों के लिए राज्य सरकार का सहयोग मांगा
- उन्होंने कहा कि जांच के परिणाम राज्य सरकार के साथ साझा किए जाएंगे।

भाजपा से जुड़ी हुई महिलाओं का यूजीसी एक्ट के विरुद्ध रौद्र रूप दिखाया

जन एक्सप्रेस । गाजियाबाद

गाजियाबाद से सवर्ण समाज की महिलाओं बेटियों ने जगदम्बा महाकाली डासना परिसर से यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इन सबने जगदम्बा महाकाली और महादेव के नाम पर इस काले कानून के विरुद्ध हर संघर्ष करने की शपथ लेकर पैदल मार्च निकालकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। विश्व के प्राचीनतम महाकाली मंदिर शिवशक्ति धाम डासना गाजियाबाद से गुरुवार को मंदिर परिसर से महिलाओं और बेटियों ने यूजीसी एक्ट के विरोध में शिवशक्ति धाम डासना से गाजियाबाद जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया और जिलाधिकारी के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के अनुसार यूजीसी एक्ट 2026 को सरकार व्यापक हिन्दू नरसंहार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लाई है। यह अन्यायपूर्ण एक्ट अगर सात दिन के अंदर वापस नहीं हुआ तो डॉ उदिता त्यागी एवं शशि चौहान सभासद नगर पंचायत डासना भारी संख्या में सामान्य वर्ग की महिलाओं और बेटियों के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के सामने सामूहिक अग्निसमाधि ले लेगी। शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर व श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने पुष्प अर्पित करके इन बहनों को शिवशक्ति धाम डासना से विदा किया और उनके साथ अपने सभी यति संन्यासियों और शिष्यों को बहनों और बेटियों की सुरक्षा के लिए साथ भेजा। इस पैदल मार्च में गीता त्यागी,अंजना त्यागी,गुंजन गुप्ता,पलक गुप्ता,गीता त्यागी मंडला,मोना शर्मा,गुडी शर्मा,रीना,गीता,काजल तथा अन्य बहने उपस्थित थी।

भाजपा सांसद ने उठाया टेलीविजन पर गुमराह करने वाले विज्ञापनों का मुद्दा, सख्त निगरानी की मांग की

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद के लक्ष्मण ने गुरुवार को टेलीविजन पर शराब और पान मसाला जैसे उत्पादों के गुमराह करने वाले (सरोगेट) विज्ञापनों पर कड़े नियंत्रण और निगरानी की मांग की, खासकर क्रिकेट मैच व अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों के दौरान। भाजपा सांसद ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद लक्ष्मण ने कहा, मशहूर हस्तियां, खासकर क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे गुमराह करने वाले विज्ञापनों के जरिये उत्पादों का प्रचार करने से बचें। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मामला बहुत अहम है और समाज में हर माता-पिता के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि उन कार्यक्रमों में ऐसे विज्ञापन बढ़ते जा रहे हैं, जिन्हें परिवार और खासकर छोटे बच्चे बड़ी संख्या में देखते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भारत में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं बल्कि देश के प्रति भावनात्मक जुड़ाव है, क्योंकि इसे परिवार के सदस्य दादा-दादी, माता-पिता और बच्चे साथ मिलकर देखते हैं।

'नाबालिगों और युवाओं के दिमाग पर गहरा असर'

उन्होंने कहा, ऐसे व्यापक दर्शक वर्ग वाले कार्यक्रमों के दौरान दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का प्रभाव बच्चों और युवाओं के दिमाग पर गहरा पड़ता है। इसमें पान मसाला, गुटखा, शराब और अन्य उत्पादों का प्रचार सरोगेट ब्रांडिंग के जरिये किया जाता है और इसमें फिल्म सितारे और क्रिकेट खिलाड़ी जैसी मशहूर हस्तियां ब्रांड एंबेसडर भी होते हैं। लक्ष्मण ने बताया कि ये विज्ञापन म्यूजिक सीडी, बोतलबंद पानी और जीवनशैली से जुड़े उत्पादों जैसी वस्तुओं के माध्यम से होते हैं, लेकिन इसमें ब्रांड की पहचान, रंग, जिंगल और एंबेसडर वयस्क उत्पादों से जुड़े रहते हैं।

'अन्य प्लेटफॉर्म में भी अपनाई जा रही यह प्रवृत्ति'

अब इसी प्रवृत्ति (पैटर्न) को ओटीटी प्लेटफॉर्म, अवार्ड शो, म्यूजिक इवेंट और डिजिटल इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म में भी अपनाया जा रहा है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि गुमराह करने वाले विज्ञापनों की निगरानी मजबूत करने के लिए सख्त नियम बनाए जाएं, स्पष्ट किया जाए कि अप्रत्यक्ष प्रचार क्या है और ऐसे विज्ञापनों को उन कार्यक्रमों में प्रतिबंधित करने पर विचार किया जाए, जिन्हें परिवार और नाबालिग अधिक देखते हैं।

'मशहूर हस्तियों को ऐसे विज्ञापन करने से रोका जाए'

सभी सांसदों से अपील की कि मशहूर हस्तियों खासकर खिलाड़ी और फिल्म स्टार को ऐसे विज्ञापनों में भाग लेने से रोका जाए, ताकि बच्चे प्राइम टाइम में ऐसे उत्पादों के संपर्क में न आएं और उनका उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित रहे।

पहाड़गंज के एक होटल में लगी आग, तीन लोग घायल

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बुधवार और बृहस्पतिवार की मध्य रात्रि एक होटल में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दिल्ली दमकल सेवा को रात तीन बजकर पांच मिनट पर पांच मंजिला इमारत में आग लगने की सूचना मिली। आग भूतल पर लगी थी और तेजी से फैलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत हरकत में आई और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने को प्राथमिकता दी गई। राहत और बचाव कार्यों के दौरान, कुल आठ लोगों को होटल परिसर से सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि, आग की चपेट में आने से तीन लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान 36 वर्षीय विनोद, 38 वर्षीय वसंत कुमार और 36 वर्षीय हितेश कुमार के रूप में हुई है। विनोद को 70 प्रतिशत तक जलने की गंभीर चोटें आई हैं, जबकि वसंत कुमार 10 प्रतिशत और हितेश कुमार पांच प्रतिशत झुलसे हैं। तीनों घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दमकल विभाग के अथक प्रयासों के बाद, तड़के चार बजकर 25 मिनट तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और जांच जारी है।

'बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर सरकार की नजर'

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

भारत सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की घटनाओं पर लगातार नजर बनाए हुए है। इनमें अल्पसंख्यकों के घरों, संपत्तियों और पूजा स्थलों पर हमले शामिल हैं। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि इस मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के सामने बार-बार उठाया गया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित जवाब में इस बात की जानकारी राज्यसभा को दी है। दरअसल, सीपीआई (एम) के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों, धमकियों और वहां बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार से जानकारी मांगी थी। इस पर सरकार ने बताया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा बांग्लादेश के सामने राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर कई बार उठाया गया है। प्रधानमंत्री ने 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस से मुलाकात में यह मुद्दा उठाया था। इसके अलावा, विदेश मंत्री ने 16 फरवरी 2025 को विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन के साथ बातचीत में भी इस पर चर्चा की थी।

विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि अन्य देशों के नेताओं के साथ हुई बैठकों में भी इस विषय को उठाया गया है। उन्होंने साफ कहा कि बांग्लादेश के सभी नागरिकों, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, की जान-माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की सरकार की है। एक अन्य सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि अगर अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को निजी रंजिश या राजनीतिक कारण बताकर टाला जाता है, तो इससे अपराधियों और चरमपंथियों को बढ़ावा मिलता है। इससे अल्पसंख्यकों में डर और असुरक्षा की भावना और बढ़ती है।

भाजपा ने राज्य सरकार पर राज्यपाल का फोन टैप करवाने का आरोप लगाया, गृह मंत्री ने ने दी सफाई

जन एक्सप्रेस/एजेंसी। नई दिल्ली

कर्नाटक की राजनीति में उथल-पुथल लगातार जारी है। विपक्षी भाजपा और राज्य सरकार में लगातार राज्यपाल को लेकर लड़ाई हो रही है। अब भाजपा ने राज्य सरकार पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत का फोन कॉल टैप करने का आरोप लगाया है। लेकिन राज्या के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इन आरोपों का खंड़न किया है। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने राज्य विधानसभा में भाजपा के इस आरोप पर कहा कि भगवा पार्टी के नेताओं का आरोप ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस वही कर रही है जो भाजपा ने पहले किया था। हमने न तो किसी का फोन टैप किया है और न ही हम भविष्य में ऐसा करेंगे। साथ ही, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। राज्यपाल ने हाल ही में विधानमंडल में अपने भाषण को सिर्फ तीन लाइनों में खत्म कर दिया था। इस पर विधानसमंडल में भारी बवाल हुआ था। इसी पर चर्चा के दौरान, कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे गहलोत को केंद्र से फोन पर निर्देश मिल रहे हैं।